हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

26 फरवरी, 2019

खण्ड–1, अंक–6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 26 फरवरी, 2019 (प्रथम बैठक)

पृष्ठ संख्या

मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व मंत्री तथा वर्तमान सदस्य और हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नेशनल महाविद्यालय शाहबाद मारकंडा, जिला कुरुक्षेत्र के प्रौफेसर्ज तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

कन्या राजकीय महाविद्यालय, सैक्टर–42, चण्डीगढ़ के प्रौफसर्ज एवं विद्यार्थियों का स्वागत

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

राज्यपाल महोदय से संदेश

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन

विभिन्न मामले उठाना/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

वर्ष 2019–2020 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा

हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन तथा सदस्यों का अभिनन्दन

वर्ष 2019–2020 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा

बैठक का समय बढ़ाना

मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 26 फरवरी, 2019 (प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

———————

मध्य प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व मंत्री तथा वर्तमान सदस्य और हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनंदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक श्री विश्वास सारंग तथा श्री अतर सिंह सैनी, पूर्व मंत्री, हरियाणा, सदन की कार्यवाही देखने के लिए वी.आई.पीज. गैलरी में उपस्थित हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

तारांकित प्रश्न संख्या 2981

(यह प्रश्न नहीं पूछा गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश बरवा सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

To Construct New Building of School

***3015. Shri Subhash Sudha :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the new building of the Government Girls Senior Secondary School, Thanesar in Thanesar City together with the time by which the said building is likely to be constructed?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हां, श्रीमान् जी थानेसर शहर में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की नई ईमारत का निर्माण वर्ष 2019–20 के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री सुभाष सुधा जी ने थानेसर के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की नई बिल्डिंग के बारे में पूछा है। कुरूक्षेत्र हमारी कल्चरल कैपिटल है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गीता जयन्ती के अवसर पर इस बारे में घोषणा भी की है। हमने वर्ष 2019–20 के बजट में इसका प्रावधान कर दिया है तथा बहुत जल्दी इस पर काम शुरू कर दिया जायेगा।

श्री सुभाष सुधा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं लेकिन वहां पर दो शिफ्टों में लड़कियों की क्लासिज लगती हैं, इससे

उनको बहुत दिक्कत होती है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस काम को जल्दी शुरू किया जाये।

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने मुझसे मिलकर भी अनुरोध किया था और वहां पर बच्चियों की संख्या काफी अधिक है इसीलिए एक ही भवन में 2 शिफ्टों में विद्यालय लगता है। हमने प्रक्रिया शुरू कर रखी है और बहुत जल्दी वहां पर बिल्डिंग का निर्माण करके लड़कियों को शिफ्ट कर देंगे।

डॉ. पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव बीड़ मथाना में डेढ साल पहले स्कूल की बिल्डिंग के लिए राशि मंजूर हो चुकी है। वहां पर बच्चे बाहर बैठते हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी उस बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाये।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो डॉ. पवन सैनी जी से मेरी बात हो गई थी और इस बारे में इनकी रिक्वैस्ट भी है तथा विभाग ने भी यह महसूस किया है कि वहां पर बिल्डिंग की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक को कहना चाहता हूं वहां पर हम बहुत जल्द कार्य शुरू करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव धारणवास के राजकीय स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। उसमें 7 नये कमरे बनाये जाने थे। मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी को 4–5 बार रिमाइंड भी करवा चुकी हूं। मुझे हर सत्र में कहा दिया जाता है कि हम इस काम को करवायेंगे। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि यह काम कब तक शुरू हो जायेगा?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक श्रीमती किरण चौधरी जी को बताना चाहूंगा कि धारणवास के स्कूल के भवन के लिए हमने 30 लाख रुपये सैंक्शन कर दिये हैं तथा नये सत्र से उस पर युद्धस्तर पर काम शुरू कर देंगे।

.....

Repair of Road

***2873. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the road from Sonepat to Farmana via Bhatgaon is in

very bad condition; and

(b) if so, the time by which it is likely to be repaired?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : (क) व (ख) श्रीमान जी, इस सड़क की मजबूतीकरण का कार्य रुपये 0953.45 लाख की अनुमानित लागत से करने के लिये दिनांक 13.02.2019 को ठेकेदार को अलॉट कर दिया गया है। इस सड़क की रिपेयर का कार्य अक्टूबर 2019 तक पूर्ण कर दिया जायेगा ।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं इसके अलावा यह भी पूछना चाहता हूं कि सदन में ही मंत्री जी ने गोहाना का पश्चिमी बाई पास बनाने की बात कही थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गोहाना के पश्चिमी बाईपास के बारे में भी मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे?

श्री नरबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक को बताना चाहता हूं कि हम इस काम को बहुत जल्द करवा देंगे।

.....

MOU for Lakhwar and Kishau Projects/Dams

***2987. Smt Prem Lata** : Will the Chief Minister be pleased to state the details of MOU signed by the Government in respect of Lakhwar and Kishau-projects togetherwith water and power sharing ratio between all the beneficiary states?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी । विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरणी

जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) में यमुना नदी पर लखवाऱ बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से 300 मेगावॉट बिजली उत्पन्न होगी तथा 330.60 मिलीयन क्यूबिक मीटर (एम0सी0एम0) पानी का भण्डारण होगा। इस परियोजना के निर्माण के लिए भागीदार राज्यों द्वारा 28.08.2018 को सहमति ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए । सहमति ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के अनुसार, इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली बिजली उत्तराखंड को दी जाएगी क्योंकि सारा जलभराव उनकी भूमि क्षेत्र में ही होगा। बेसिन राज्यों के बीच 330.60 एम0सी0एम0 जल भंडारण का आंवटन 1994 के समझौते में दिए गए उनके समग्र वार्षिक आंवटन के अनुपात में किया जाएगा जो निम्नलिखित है।

राज्य	जल हिस्सा एम0सी0एम0
हरियाणा	158.10
उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड सहित	111.20
राजस्थान	30.90
हिमाचल प्रदेश	10.40
दिल्ली	20.00
कुल जोड़	**330.60**

किसााऊ बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण युमना नदी की सहायक टोंस नदी पर किया जाएगा, जोकि उत्तराखंड के देहरादून जिले और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले मे है। यह 660 मेगावॉट बिजली उत्पादन करेगा और इसमें 1324 एम0सी0एम0 पानी का भंडारण होगा। इस परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रस्तावित समझौते के अनुसार इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली बिजली उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों को दी जाएगी क्योंकि सारा जलभराव उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भूमि क्षेत्र में ही होगा । बेसिन राज्यों के बीच 1324 एम0सी0एम0 जल भंडारण का आवंटन 1994 के समझौते के अनुसार उनके संपूर्ण वार्षिक आबंटन के अनुसार निम्न प्रकार से होगाः–

राज्य	जल हिस्सा एम0सी0एम0
हरियाणा	633
उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड सहित	445
राजस्थान	124
हिमाचल प्रदेश	42
दिल्ली	80
कुल जोड़	**1324**

श्रीमती प्रेम लता : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि कल जो बजट पेश किया गया था उसमें किसानों के लिए जो प्रावधान रखा गया है जिसमें किसानों की पेंशन भी है । वह बात अलग है कि अभी तक यह अनाउंस नहीं किया गया है कि वह पेंशन कितनी देंगे लेकिन देंगे । मैं देश के प्रधान मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने किसानों के बारे में पहली बार यह सोचा है कि उनको खुद का पैसा भी चाहिए । उन्होंने दो दिन पहले अनाउंस किया था कि किसानों को 6000/रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे । जहां तक लखवार डैम और किसाऊ डैम की बात है उसमें मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि लखवार डैम और किसाऊ डैम में से पहले किसाऊ डैम की परियोजना हस्ताक्षर हुई थी लेकिन अभी तक उस पर कोई भी काम नहीं हुआ है । उसके लिए अभी तक न तो कोई जमीन ली गई है और अभी तक न यह तय हुआ

है कि उस पर कब तक काम शुरू हो जाएगा । दूसरी तरफ लखवार डैम के लिए 28 अगस्त 2018 को चार हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। जिसमें 6 प्रदेशों ने हस्ताक्षर किए थे । हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली । उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिन्धिया । मैं यह जानना चाहती हूं कि यह प्रोजैक्ट लोहारी में बनने जा रहा है जो देहरादून में पड़ता है । इस प्रोजैक्ट की शुरुआत के लिए क्या कोई जमीन खरीदी गई है ? या जो प्रोजैक्ट तैयार हुआ है उस पर काम कब शुरू होगा ? इसके लिए दिसम्बर 2022 की डैड लाईन रखी गई है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या उस पर कोई काम शुरू हुआ है ? क्योंकि वह हमारी लाइफ लाईन है । अगर यह प्रोजैक्ट बन जाता है तो हरियाणा के करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जीन्द, गुरूग्राम और झज्जर को पूरा पानी मिलेगा । यमुना का सिरसा ब्रांच का पानी जो हमें दिल्ली में देना पड़ता है । इस प्रोजैक्ट के बनने से उसमें भी फर्क पड़ जाएगा क्योंकि अगर दिल्ली को यमुना नदी का पानी मिलेगा तो दिल्ली से सिरसा ब्रांच से जो पानी हमें आज दिया जा रहा है उससे भी हमें निजात मिलेगी । मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि इस प्रोजैक्ट का काम कब तक शुरू हो जाएगा ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, एक खुशी की बात यह है कि लखवार डैम का काम शुरू हो गया है । जैसा माननीय सदस्या ने कहा है कि जो 12 मई 1994 का बेसिक एम.ओ.यू. साइन था उसके आधार पर इन सभी मुख्यमंत्रियों ने फिर से साइन किए हैं उसकी कॉपी हमारे पास है और रेणुका डेम का एम.ओ.यू. भी फिर से रि–साइंड हो गया है तथा लखवार डैम का काम शुरू हो गया है लेकिन किसाऊ दो राज्यों के बीच पड़ता है । अभी किसाऊ डैम का एम.ओ.यू. भी एक बार फिर से रि–साइंड होना है । यह बात सही है कि इन तीनों डैम्ज के बन जाने से पानी के मामले में हमारी काफी अच्छी पोजीशन हो जाएगी । इन डैम्ज में 17 लाख 11 हजार फिट पानी स्टोरेज होगा । उसमें से 8 लाख 18 हजार एकड़ फिट हरियाणा का होगा । उसके कारण से हमारे हरियाणा की स्थिति यह होगी कि हम जो हर मौसम में ढाई हजार क्यूसिक के आस–पास पानी ले पाते हैं, उससे 1700 क्यूसिक अतिरिक्त पानी हमें पूरे 9 महीने गैर बरसात के समय में भी

मिलेगा । इस तरह से हम 4000 क्यूसिक पानी से क्रोस कर जाएंगे और हमें 4200 क्यूसिक के आस–पास पानी मिलना शुरू हो जाएगा जिसकी सुनिश्चितता बरसात के अलावा भी पूरे साल भर के लिए हो जाएगी । इसलिए यह एक बड़ी शुरूआत हो रही है । इसमें राज्यों की पैसे की जो हिस्सेदारी है वह केवल 10 प्रतिशत है इसके अलावा बाकी सारा खर्च सैंटर गवर्नमैंट कर रही है । हम एक ऐसा प्रोजैक्ट लेकर चले हुए हैं कि लखवार डैम का काम साढ़े चार साल में पूरा हो जाए । इसी तरह से किसाऊ डैम का काम भी हम लेकर चल रहे हैं और रेणुका डैम का काम 6 वर्षों में पूरा हो जाएगा लेकिन किसाऊ डैम का काम अभी आगे तक जा सकता है क्योंकि यह दो राज्यों के बीच में है। इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जमीन लगती है । उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इसके लिए 9 वर्ष का समय दिया गया है ।

श्रीमती प्रेम लता : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि इस प्रोजैक्ट को बनाने में हरियाणा राज्य के हिस्से में जो 123.29 करोड़ रुपये आए हैं क्या उसके लिए कोई एडवांस राशि दी गई है ? क्योंकि इसमें 90–10 का रेशो है । इस प्रोजैक्ट का 90 प्रतिशत खर्च तो सैंटर गवर्नमैंट वहन करेगी और 10 प्रतिशत खर्च बाकी 5 राज्यों की सरकारें वहन करेंगी । इसमें मैं यह जानना चाहती हूं कि इसमें हरियाणा के हिस्से में जो पैसा आया है क्या उसमें से कुछ राशि एडवांस दी गई है ? क्योंकि अगर इस प्रोजैक्ट का काम शुरू हो जाता है तो जिस प्रकार से हम यह कहते हैं कि गंगा का पानी बहुत दूषित हो गया है तो जो पानी यमुना से आता है जो आगे जाकर कानपुर, आगरा और आगे त्रिवेणी में जाकर मिलता है । सभी शहरों का गन्दा पानी यमुना में आकर फिर गंगा में मिल जाता है । अगर यह डायलूट हो जाएगा तो बारह महीने पानी मिलने लग जाएगा जो अब 6 महीने तक तो मिल ही नहीं रहा है क्योंकि बरसात के दिनों में तो दो लाख क्यूसिक पानी आ जाता है और जब बरसात के दिन खत्म हो जाते हैं तो 200 क्यूसिक पानी भी नहीं आता है । अगर यह बांध बन जायेगा तो उससे जो पानी की स्टोरेज होगी उससे 12 महीने जो पानी मिलेगा उससे एक तो गंगा की सफाई में सहयोग मिलेगा और गंगा को साफ रखना हमारे प्रधानमंत्री जी का एक प्राईम प्रोजेक्ट भी है दूसरा यमुना का जो पानी वेस्ट जाता है वह भी हमारे प्रदेश को मिलेगा।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैडम प्रेमलता जी के पति केन्द्रीय मंत्री हैं और दिल्ली में बैठते हैं तो संभव सी बात है कि इनके पास कुछ ज्यादा

जानकारियां होंगी कि कितना पैसा गया या फिर कितना नहीं गया ? मैडम के द्वारा जो सवाल किए जा रहे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली से सवाल आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन परियोजनाओं की बात की गई हैं उन सबमें 10 परसेंट राज्य सरकार को पैसा देना है और 90 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार ने देना है जिसके लिए एम.ओ.यू. भी साइन हो चुके हैं, जो भी हमारी हिस्सेदारी होगी, उसके लिए हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है, जो भी मांगेगे, हम दे देंगे।

.....

Unemployment Youths Registered in Employment Exchanges

***2879. Smt Kiran Choudhry**: Will the Employment Minister be pleased to state -

(a) the district wise details of the unemployed youths registered in employment exchanges in State;and

(b) the number of youths being provided employment in the last four years?

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : श्रीमान, इस बारे कथन सभा के पटल पर रख दिया गया है।

कथन

श्री मान जी,

(क) दिसम्बर 2018 के अन्त तक कुल 6,18,565 बेरोजगारों प्रार्थियों ने हरियाणा राज्य के रोजगार कार्यालयों में विभागीय पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करवाया।

(जिलावार ब्योरा परिशिष्ट –1 पर है)

(ख) पिछले चार वर्षों (26 अक्तूबर 2014 से 31 जनवरी 2019 तक) में हरियाणा राज्य में स्थित रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कुल 49,299 बेरोजगार प्रार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया।

परिशिष्ट– 1

राज्य के रोजगार कार्यालयों में दिसम्बर–2018 के अन्त तक कुल पंजीकृत प्रार्थियों की संख्या

क्र0.स0.	रोजगार कार्यालय	पंजीकृत प्रार्थी
1	अम्बाला	25,888
2	पंचकूला	9,569
3	यमुनानगर	41,376
4	कुरूक्षेत्र	30,260
5	कैथल	28,344
6	करनाल	46,382
7	पानीपत	27,865
8	रोहतक	34,242
9	झज्जर	30,617
10	सोनीपत	39,478
11	जीन्द	53,553
12	भिवानी	57,685
13	गुरूग्राम	10,166
14	फरीदाबाद	29,930
15	नूंह(मेवात)	9,997
16	नारनौल	22,695
17	रेवाडी	19,125
18	हिसार	49700
19	फतेहाबाद	22,856
20	सिरसा	28,837
21	राज्य रोजगार कार्यालय	0
22	कुल योग	**6,18,565**

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में जो बात बताई है, उसी प्रश्न से संबंधित "दि ट्रिब्यून अखबार" की न्यूज की एक कटिंग मेरे पास है जोकि आर.टी.आई. एक्टिविस्ट द्वारा ली गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। अगर माननीय मत्री के जवाब और "दि ट्रिब्यून" में दी गई न्यूज दोनों को मिलाकर देखते हैं तो मंत्री जी द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल अलग दिखाई देगी। "दि ट्रिब्यून" की न्यूज के मुताबिक 15 जिलो में 15,21,854 युवाओं का इम्पलॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हुआ। जिनमें रोहतक, नूंह, करनाल,

कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, अम्बाला, जींद, फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद, सिरसा, यमुनानगर, दादरी, भिवानी और पंचकुला शामिल हैं। 15,21,854 इम्पलॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड युवाओं में से केवल मात्र 647 युवाओं को नौकरी दी गई है। 647 युवाओं में से भी 28 युवा कांट्रैक्ट पर लगाये गए और 139 प्राईवेट जॉब्स में हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि वह बातें तो लंबी चौड़ी करते हैं कि इतनी नौकरियां दी जा रही है लेकिन जो मैं न्यूज को कोट करके बात बता रही हूँ उससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सारी बातें केवल और केवल जुमला हैं क्योंकि एक लंबी संख्या रजिस्टर्ड युवाओं की होने के बावजूद भी केवल मात्र 647 युवाओं को जॉब देना कहां तक वाजिब ठहराया जा सकता है? बी.जे.पी. का इलेक्शन मैनिफैस्टो था कि 10वीं पास युवाओं को 6000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा और बी.ए. पास को 9000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगी कि कितने बेरोजगार युवाओं को यह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है?

श्री नायब सैनीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जिस आर.टी.आई. आधारित खबर की बात की है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जिस अधिकारी ने यह गलत खबर दी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। असल में बेरोजगारों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका विवरण इस प्रकार है अम्बाला में 25,888, पंचकुला में 9,569, यमुनानगर में 41,376, कुरूक्षेत्र में 30260, कैथल में 28,344, करनाल में 46,382, पानीपत में 27865, रोहतक में 34,242, झज्जर में 30617, सोनीपत में 39478, जींद 53,553, भिवानी में 57,685, गुरूग्राम में 10,166, फरीदाबाद में 29,930, नूंह में 9,997, नारनौल में 22,695, रेवाड़ी में 19,125, हिसार में 49,700, फतेहाबाद में 22,856 तथा सिरसा में 28,837 अर्थात कुल 6,18,565 युवाओं की रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि वर्ष 2014 से पहले रोजगार कार्यालयों में कोई भी युवा आना नहीं चाहता था बल्कि रोजगार कार्यालयों में जाले लग गए थे। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में हमारी सरकार आने के बाद ही रोजगार कार्यालयों में जाले उतारने का काम शुरू हुआ था। रोजगार कार्यालयों को बंद किया जाए इस तरह का प्रस्ताव भी कांग्रेस पार्टी ने दिया था। दूसरी बात मैं माननीय सदन को बताना चाहूँगा कि 'सक्षम योजना' के माध्यम से ग्रुप–डी में 1490 युवा भर्ती हुए हैं। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 2461 युवाओं को रोजगार दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमने मेगा

जॉब फेयर लगाकर उसके माध्यम से 2338 युवाओं को रोजगार दिया। उसके बाद स्किल अकेडमी खोली और उसके माध्यम से 12 युवाओं को रोजगार दिया। कैब टैक्सी उबर के माध्यम से 11105 युवाओं को रोजगार दिया गया। कैब टैक्सी ओला के माध्यम से 5567 युवाओं को रोजगार दिया गया। जी0 फॉर एस0 सिक्योरिटी गार्ड के माध्यम से 641 युवाओं को रोजगार दिया गया। अध्यक्ष महोदय, फिर हमने 312 मेगा जॉब फेयर लगाए और उसके माध्यम से 27167 युवाओं को रोजगार दिया गया। अध्यक्ष महोदय, साढ़े चार वर्ष में 50801 युवाओं को अलग–अलग रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है और उसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 54510 युवाओं को रेगुलर नौकरी दी है। जो रिक्रूटमैंट अंडर प्रौसेस है वह 17503 युवाओं की है और माननीय न्यायालय में जिन भर्तियों पर स्टे लगा हुआ है उसमें भी 5600 युवाओं को रोजगार मिलेगा। वह भर्ती भी जल्दी ही होने वाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को एक आइना दिखाना चाहता हूँ कि वे 10 साल तक सत्ता पर काबिज रहे और जो आज नौकरियों की बात कर रहे हैं उन्होंने आखिर युवाओं के लिए क्या किया है? अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने जो युवाओं को रोजगार दिया चाहे वह रोजगार कार्यालय के माध्यम से दिया हो, चाहे वह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से दिया हो या फिर हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से दिया वह 10 साल के कार्यकाल में केवल 50753 युवाओं को रोजगार दिया है। हमारी साढ़े चार साल की सरकार ने लगभग 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है और आगे भी नौकरियों की ऐडवरटाईजमैंट हो रही है, इस प्रकार से इसमें और ज्यादा युवाओं की भागीदारी होगी।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, रोजगार के संबंध में जो इतना बड़ा वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने पढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े मेरे पास है वह आर.टी. आई. के माध्यम से लिए गए हैं क्या ये सारे आंकड़े झूठे हैं? यह बात दैनिक ट्रिब्यून अखबार में भी छपी है।

श्री नायब सैनी : अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी मैंने सदन में भी है वह तथ्यों के आधार पर दी है। बहन किरण चौधरी पता नहीं कौन से अखबार की कटिंग लेकर आ जाती है। बहन जी अपने आप ही प्रैस कांफ्रैंस करती है और गलत आंकड़े लेकर सदन में आ जाती हैं। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में जो आंकड़े दिए हैं उनके अनुसार दिसम्बर, 2018 तक 6,18,565 प्रार्थियों ने हरियाणा के रोजगार कार्यालय के माध्यम से अपना पंजीकरण करवाया है । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने कुल 49,210 प्रार्थियों को रोजगार प्रदान किया है । यह माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया जवाब है । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि पंजीकरण करवाये हुए अभी भी लगभग पौने 5 लाख बच्चे रोजगार प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं । भाजपा ने विधान सभा चुनावों के समय वादा किया था कि हम दसवीं पास को 6 हजार रुपये रोजगार भत्ता और बी.ए. पास को 9 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इन पौने 5 लाख पंजीकरण करवाये हुए बेरोजगार युवकों को आपने अब तक कितना अनइम्पलॉयमैंट अलाउंस दिया है और अगर नहीं दिया है तो कब तक दे दोगे ? सरकार वैसे तो बहुत बड़ी–बड़ी बातें करती है लेकिन ये आंकड़े कुछ और ही असलियत बयां कर रहे हैं ।

श्री नायब सैनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या किरण चौधरी जी कल हाउस में उपस्थित नहीं थी । (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों के आधार पर बात कर रही हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, माननीय मंत्री जी आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं ।

श्री नायब सैनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का प्रश्न है कि कितने युवाओ ने रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाया और कितने युवाओं को रोजगार दिया गया । इस बारे में सदन में कल सक्षम युवाओं के विषय पर पूरा उत्तर दिया गया था । माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बताया गया कि हरियाणा प्रदेश में युवाओं के लिए ऐसी पहली लोकहित योजना बनाई गई है जिसका युवा पूरा लाभ उठा रहे हैं । हम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को सौ घंटे काम के बदले साढ़े सात हजार और नौ हजार रुपये दे रहे हैं । आज फिर से इसी बारे में सदन में प्रश्न किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि मैट्रिक पास युवाओं की रजिस्ट्रेशन जीरो है । वैसे हम उनको सौ रुपये प्रतिमाह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देते हैं । इसके अलावा कुल 19,508 बारहवीं पास युवाओं ने रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाया है । मैं बताना चाहता हूं कि हमने अपनी वैबसाइट पर किसी भी युवा को

बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने से नहीं रोका है । हमने तो माननीय सदस्या को भी रजिस्ट्रेशन करने से नहीं रोका है । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को प्रश्न का उत्तर नहीं सूझ रहा है । (विघ्न)

श्री नायब सैनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहती हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मुझे बतायें कि वे पौने पांच लाख युवा जो रोजगार पाने से वंचित हैं उनको कब तक रोजगार दिया जाएगा ? (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, ऑनरेबल मैम्बर का सवाल करने का यह तरीका गलत है । मेरा इनसे प्रश्न है कि ये पौने पांच लाख युवा जो बेरोजगार हैं क्या ये वर्ष 2014 के बाद पैदा हुए हैं ? माननीय सदस्या अपनी सरकार का आइना नहीं देखना चाहती हैं । ये 10 साल तक सरकार में रही हैं । यह हो सकता है कि इनको सरकार में पूरा हिस्सा न मिला हो । (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, किरण जी का सरकार में पूरा हिस्सा था। माननीय सदस्या बहुत ही बहादुर हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में केवल 9,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी और उन नौकरियों में पैसा, पर्ची और सब कुछ चलता था। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में इन कामों से कई लोगों के परिवार भी चलते थे। आज हमारी सरकार ने 72,000 लोगों को रोजगार दिया है। हमारी सरकार ने कांग्रेस सरकार से 8 गुना अधिक लोगों को रोजगार दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। वर्तमान सरकार ने आपकी सरकार की तुलना में 8 गुणा ज्यादा स्पीड से रोजगार दिया है।

श्री नायब सैनीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के कार्यकाल के समय की एक बात और बताना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के माननीय सदस्यों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारी सरकार ने कांग्रेस पार्टी की सरकार से अच्छा काम किया है। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य हर बात पर गलत टिप्पणी करते हैं। यह बेरोजगारी कांग्रेस की सरकार ही छोड़कर गयी थी। कांग्रेस सरकार ने

अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल 9,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी थी जिसमें पर्ची, पैसा, बेईमानी और सब कुछ चलता था। हमारी सरकार ने 72,000 लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ नौकरी दी हैं। कांग्रेस के माननीय सदस्यों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री नायब सैनी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सरकार के कार्यकाल की एक बात और बताना चाहूंगा। माननीय सदस्या को उसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि इनकी सरकार के समय में शायद इनको कोई पूछता नहीं था। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में 10वीं पास युवाओं का बेरोजगारी भत्ता भी बन्द कर दिया गया था। (शोर एवं व्यवधान) शायद माननीय सदस्या को इस बात की जानकारी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। अब जाकिर जी अपनी बात रखेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगी कि इनके कार्यकाल में 5 लाख युवा बेरोजगार घूम रहे हैं।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या यह भी बता दें कि इनके कार्यकाल में कितने युवा बेरोजगार थे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को अपनी सरकार की ही बात करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को 10 साल तक लूटा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि आने वाले 5 साल हमारी सरकार के ही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पाटी को कई सालों तक घर में बैठना पड़ेगा। प्रदेश की जनता इनको घर बैठा देगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सपने देख रहे हैं।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी हवा में बातें कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्य बैठ जाएं, अब माननीय सदस्य श्री जाकिर हुसैन जी अपना प्रश्न पूछेंगे।

.....

Renewal and Issuance of Heavy Driving Licenses

***2883. Shri Zakir Hussain :** Will the Transport Minister be pleased to State the steps taken by the Government for the renewal and issuance of new Heavy Driving Licenses in District Nuh and Palwal togetherwith the details thereof?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान् जी, राज्य भर में नए हैवी ड्राईविंग लाईसैन्सों का नवीनीकरण तथा जारी करना संबंधित लाईसैंसिंग प्राधिकरणों (मोटर वाहनों) द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। वर्ष 2010 से दिनांक 08.02.2019 के दौरान जिला नूंह में 1183 नए हैवी ड्राईविंग लाईसैंस जारी किए गए तथा जिला पलवल में 2607 नए हैवी ड्राईविंग लाईसैंस जारी किए गए हैं जबकि उक्त अवधि के दौरान जिला नूंह में 34137 हैवी ड्राईविंग लाईसैंस नवीनीकृत किए गए तथा जिला पलवल में 857 हैवी ड्राईविंग लाईसैंस नवीनीकृत किए गए हैं।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है उसमें एक बहुत बड़ी बात का फर्क हैं कि जो हैवी ड्राईविंग लाईसैंस वर्ष 2010 में बनाये गये थे उन हैवी ड्राईविंग लाईसैंस को दोबारा से रिन्यूवल करवाने के लिए 2 कंडीशंज लगा दी हैं। इस कारण संबंधित लोग लाईसैंस रिन्यूवल नहीं करवा सके। कल भी सदन में यह विषय सामने आया था। वर्ष 2007 में एक कंडीशन तो सैक्शन 8 में सैंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्ज में मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास की लगायी गयी है। सारे देश के हालात अलग हो सकते हैं लेकिन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे कुछ स्टेट्स में आज भी बहुत से लोग अनपढ़ हैं। जो ड्राईवर्ज लगभग 30–30 साल से गाड़ियां चला रहे थे उनके लाईसैंस दोबारा से न तो रिन्यूवल हो पा रहे हैं और न ही नये लाईसैंस बन पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में जब श्री आफताब अहमद जी ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर थे तो उस समय बहुत से लोगों के खिलाफ झूठी एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी। 23 दिसम्बर, 2013 को तावडू के थाने में एफ.आई.आर. नम्बर 39 दर्ज हुई थी। इसके अतिरिक्त नूंह के थाने में जनवरी, 2016 में एफ.आई.आर. नम्बर 16 दर्ज हुई थी। ये

एफ.आई.आरज. माननीय परिवहन मंत्री श्री आफताब अहमद के समय में दर्ज हुई थी इस एक्ट का दुष्परिणाम यह हुआ कि ड्राईविंग लाईसैंसिज का नवीनीकरण बन्द हो गया और नये लाईसैंस बनने भी बन्द हो गये । मेवात जिले के ज्यादातर लोगों का रोजगार का साधन हैवी ड्राईविंग लाईसेंस से जुड़ा हुआ है क्योंकि इस जिले में ड्राइवर्ज की संख्या बहुत ज्यादा है। आज भी लाईसैंसिज रिन्यूवल/नये लाईसैंसिज न बनने से 30–35 हजार लोग घर पर बेरोजगार बैठे हैं और उनके भूखों मरने की नौबत आ गयी है। दिनांक 16 मार्च, 2016 को भी मेरे द्वारा लगाये गये तारांकित प्रश्न संख्या 1224 के बारे में जवाब में माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई में कहा था कि इस मामले को सुलझाएंगे। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी मेवात डिवैलपमैंट बोर्ड की बैठक में आश्वासन दिया था कि इस मामले को सुझलाएंगे। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि सरकार द्वारा मामले को सुलझाने के लिए प्रयास किये गये हैं। हैवी ड्राईविंग लाईसैंस बनवाने में 8वीं पास की जो कंडीशन लगायी गयी है, उसको हटाने के लिए माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को भी एक रिप्रजैंटेशन दी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वे इस समस्या का समाधान निकालेंगे ? अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आज की स्थिति यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बावजूद वहां पर मौके पर जो अधिकारी थे, उन्होंने पिछले एक–डेढ़ साल से एक भी लाइसेंस रिन्यू नहीं किया और न ही कोई नया लाईसेंस बनाया। आज के समय में इक्का–दुक्का काम होना शुरू भी हुआ है, लेकिन मैं एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज भी मेवात के लोग धक्के खा रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंसिज की रिन्यूवल और उनके नए बनने की प्रक्रिया बिल्कुल न के बराबर हो रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये इस पर कोई कार्रवाई करेंगे ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को कहना चाहूंगा कि इन्होंने सही बात कही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेवात के युवाओं की तरफ विशेष ध्यान देते हुए दिनांक 04.04.2016 को नूंह विकास बोर्ड की एक बैठक भी की थी और उस बैठक में यह तय किया गया कि जिन लोगों के पास एल.एम.वी. या एल.टी.वी. लाइसेंस हैं, उनको रिन्यू कर दिया जाएगा। हमारे हरियाणा प्रदेश में कुल 18 ऐसे ड्राइविंग स्कूल्ज हैं, जिनमें ड्राइवर्ज को ट्रेनिंग दी जाती है और जिसके पास एक महीने की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होता है, उसके

लाइसेंस को रिन्यू कर दिया जाता है। हमने जब जांच करवाई तो पाया गया कि बहुत सारे लोगों के पास न तो एल.एम.वी., एल.टी.वी. लाइसेंस था और न ही कोई ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट था। अध्यक्ष महोदय, इन सबके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया कि हमारी नीति प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की है और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार के द्वारा मार्गदर्शन ले लिया जाएगा। स्पीकर सर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि लाइसैंस बनाने के लिए आठवीं क्लास पास की कंडीशन है और इस कंडीशन से पहले अंडर मिडिल क्लास वालों के भी लाइसैंस बनाए जाते थे, लेकिन लेटेस्ट पॉलिसी आने के बाद लाइसेंस बनाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आठवीं क्लास पास की कंडीशन किस सरकार के कार्यकाल में आई थी?

श्री कृष्ण लाल पंवारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह पॉलिसी वर्ष 2007 में कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में आई थी और इसमें सबसे पहली एफ.आई.आर. नूंह डिस्ट्रिक्ट में दिनांक 23.12.2013 को कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में दर्ज की गई थी। उस समय मैं विधायक था और श्री आफताब अहमद जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे को लेकर मार्च, 2016 में भी इस सदन में विस्तृत डिस्कशन हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी एम.डी.बी. की मीटिंग में बराबर इस बात को कहते आए थे कि जो ड्राइविंग लाइसेंस बाहर से बने हैं, उनमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की गलती नहीं है। सर, अगर मैं कहूं तो सही मायने में मेवात के लोग टटलू काटने में मशहूर हैं, लेकिन मेवात के लोगों का टटलू कट गया और दलालों ने उनसे पैसे ले लिए और झूठे लाइसैंस बना दिये, यहां तक कि जब मैं एल.एल.बी. कर रहा था तो उस समय मेरा भी लाइसैंस फर्जी बना दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम नूंह के अंदर इनके लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवा सकते हैं, लेकिन इनके बिना ट्रेनिंग वगैरह के नए लाइसेंस बनवा सकते हैं। सर, नए लाइसेंस बनवाने में सबसे बड़ी समस्या यह आ गई है कि लोग बाहर जाकर तीन–तीन महीने नहीं रह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की घोषणा है और माननीय मंत्री जी ने सदन में भी कहा था कि उन्हें हर जिले में ड्राइविंग स्कूल्ज

खोलने हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि मेवात जिला के छपेड़ा गांव में कई साल पहले विभाग के पास जमीन आ गई थी और आज तक उस पर विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने सरकार को उस समय भी ऑफर किया था और आज भी कर रहा हूं कि वहां पर सरकार के पास जो सरकारी बिल्डिंग्ज हैं, अगर सरकार को उनमें ड्राइविंग स्कूल खोलने में दिक्कत है तो मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर मेरे दादा जी मरहूम यासीन खां के नाम से 36 एकड़ में एक कॉलेज है और मैं आज भी मंत्री जी को ऑफर करना चाहूंगा कि अगर मंत्री जी हमसे 10 या 20 कमरों के लिए कहेंगे तो हम इनको स्पेअर कर देंगे और चाहे कल से ही ट्रांसपोर्ट विभाग इसे अपने हैंड–ओवर कर ले, ये बात मैं as a Chairman, Mewat Education Board on the floor of the house कहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेवात डिस्ट्रिक्ट के लिए इससे बड़ा कोई रोजगार नहीं हो सकता, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये मेवात में ड्राइविंग स्कूल खोलने की घोषणा करें। अगर माननीय मंत्री जी चाहे तो ट्रांसपोर्ट विभाग के किसी अधिकारी को मेवात में भेजकर उसकी जांच करवा सकते हैं, क्योंकि वहां पर लाइसैंस न तो रिन्यू हो रहे हैं और न ही नए बनाए जा रहे हैं और इसके कारण मेवात के लोग बहुत परेशान हैं। यह मेवात के लोगों का सबसे बड़ा धंधा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये मेवात में ड्राइविंग स्कूल जल्दी खोलने का कष्ट करेंगे और क्या ये वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल और नए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना जल्दी शुरू करवाएंगे ?

नेशनल महाविद्यालय, शाहबाद मारकंडा, जिला कुरुक्षेत्र के प्रौफेसर एवं विद्यार्थियों का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज शाहबाद मारकंडा नेशनल कॉलेज के प्रौफेसर और विद्यार्थी हरियाणा विधान सभा की दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए विराजमान हैं । मैं पूरे सदन की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारंभ)

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि नूंह जिले के गांव छपेड़ा में ग्राम पंचायत की 87 कैनाल भूमि 23 वर्ष के लिए 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ले ली है और

दिनांक 27.2.2018 को एम.ओ.यू. टाटा मोटर्स के साथ हो चुका है इस पर हम जल्दी कार्रवाई करवायेंगे, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। हमने मीटिंग करने के बाद एल.आर. विभाग से सलाह ली थी और कहा था कि इसका समाधान करवाया जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि इन युवाओं को रोजगार देने का काम करे और इनके लाईसैंस रिन्यू किये जायें । सरकार ने जो एल.आर. से राय मांगी थी, जिसमें एल.आर. ने कहा कि फर्जी ड्राईविंग लाइसैंसों का नवीनीकरण किया जाता है तो उसको कानून की गाइडलाइंज़ में फर्जी दस्तावेज ही माना जाता है। अगर किसी अधिकारी/कर्मचारी ने गलती से लाईसैंस रिन्यू कर भी दिए तो रिकॉर्ड के हिसाब से वैलिड नहीं पाये जायेंगे ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद ही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर.के. खुल्लर साहब की चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया था । आर. के. खुल्लर साहब ने और श्रीमती आशिमा बराड़ जी ने एक रिप्रजैंटेशन बनाकर दी थी । अध्यक्ष महोदय, हमारे एम.पी. साहब तो मेवात जिले से वोट लेने के बाद लापता हो जाते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता कि गुरूग्राम के एम.पी. कहां पर हैं ? फरीदबाद के एम.पी साहब श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और हम सभी (श्री करण सिंह दलाल, श्री रहीश खान, श्री उदय भान श्री मूलचन्द शर्मा, श्री नसीम अहमद, श्री टेक चन्द शर्मा, श्रीमती सीमा त्रिखा, श्री केहर सिंह, श्री ललित नागर और श्री तेजपाल तंवर) विधायकों ने इस रिप्रजैंटेशन पर साईन किये थे। यह कोई एक विधायक की कंसर्ड नहीं थी। यह मेवात जिले से लगते हुए पूरे इलाके की कंसर्ड थी, आपने भी इस बात को माना है। यदि किसी कारणवश इसका हल सैंटर्ल गवर्नमेंट से न भी निकले तो हरियाणा सरकार से मेरी अपील है कि इस पर दोबारा से गौर करते हुए, जो बीच का रास्ता निकल सके उसे निकलवाने का कष्ट करें । उसके लिए आपकी बहुत मेहरबानी होगी । जो हमने माननीय नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा है वह इस प्रकार हैः–

To

Sh. Nitin Gadkari,
Union Minister for Road Transport, Highways, Shipping and
Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation,
Government of India,
New Delhi.

Sub: For beseeching kind indulgence of your good self in modifying/exempting minimum educational qualification prescribed under Rule 8 of the Motor Vehicle Rules, 1989, to

obtain the license to drive the transport vehicles, in view of the extreme hardship being faced due to this condition, by the residents of Haryana especially living in the notified area falling under Mewat Development Board, Haryana.

Respected Sir,

It is respectfully prayed that Chapter-II of the Motor Vehicle Act, 1988 deals with the licensing of drivers of motor vehicles, Section 27 of this Chapter deals with the power of Central Government to make rules, and its clause (g) empowers the Central government to specify the minimum educational qualifications of persons to whom license to drive transport vehicles may be issued under this Act and the time within which such qualifications are to be acquired by such persons.

Acting thereupon, the Central government had specified the minimum educational qualifications of pass in the eighth standard (Rule 8) by an amendment in 2007; as a pre-requisite condition to obtain the license to drive the transport vehicle.

In the case of Mewat Development Board area of the State of Haryana, extreme hardship is being faced by innocent people who are suffering a hand to mouth existence because of the Rule 8. There are thousands of unemployed men of the area, who used to have driving licenses for heavy vehicles, but which were subsequently declared invalid because they were not verified by the licensing authorities concerned for no fault of these poor and gullible people. The licenses, therefore, could not be renewed by the licensing authority and as a result, these people are not able to drive transport vehicles, which was the only source of livelihood for them.

In such cases, these individuals are not able to get even a new driving license for transport vehicles due to condition of Academic qualification. Though these persons has a long experience in driving both transport and non-transport vehicles proficiently, but they do not fulfil the conditions of eighth pass because of the historical backwardness of the area, poverty and non-accessibility to education at

the time which they were young. These persons are suffering since many years, and the State Government also cannot do anything about this problem because all the powers with respect to prescribing educational qualifications reside with the Central Government.

Definitely, there is no doubt that the intent of the legislature behind providing educational qualification as to ensure that a person who is driving the transport vehicle should be in a position to read/understand the traffic signs. But at the same time, it can also not be denied that experience, if not long experience, can also be a substitute to the educational qualification prescribed to hold the license. There are many instances wherein the persons who have been driving a transport vehicle for a long time, thereby gained experience, but only because of the lack of educational qualification prescribed they are unable to obtain license to drive the transport vehicle leading to hardship not only to them but to their families also, who are dependent upon them for livelihood needs.

It is humbly requested that a lasting solution may be found out to mitigate the extreme hardship and financial distress of a large number of residents of this area, who are yet not able to participate in the growth process witnessed by this area by virtue of the huge infrastructural additions made under your able leadership.

The following possible solutions are proposed for your kind consideration, in this regard:

1) Rule 8 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 may be done away with.

Or

2) The following Proviso may be added in the said Rule, viz.,:
"Provided that this Rule shall not apply in the case of Mewat Development Board area, as notified by the Government of Haryana, from time to time."

Or

3) The following Proviso may be added in the said Rule, viz.,:
"Provided that this Rule shall not apply in the case of Aspirational districts, as notified by the Niti Aayog or the Central Government, from time to time."

Or

4) The following Amendment may be made in the Sections 27 and 28 of The Motor Vehicles Act, 1988, viz.,

i) Clause (g) of Section 27 may be amended and the following proviso added:

"Provided that the minimum educational qualifications of persons to whom licenses to drive transport vehicles are to be issued in areas which are aspirational districts, as notified from time to time, may be determined by the respective State Governments."

ii) The following clause may be prescribed in Section 28:

"Section 28(1) the minimum educational qualification, to drive a transport vehicle, in the case of aspirational district(s) of the State."

Or

5) In the proviso to rule 8, after clause (ii), the following clause may be inserted:-

(iii) "persons who have attained the age of 20 years as on 10.04.2007 i.e. the date of Notification of Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2007."

It is under these compelling circumstances, your kind indulgence is sought, to examine the issue in hand and to grant exemption from minimum educational qualification, for these affected persons, by taking a sympathetic view in their favour. This step will also go a long way in boosting employment and growth opportunities in the area falling under Mewat Development Board comprising the whole of district Nuh which is an aspirational district and Block Hathin of district Palwal.

Thanking you,

Sd/-
Date: (Krishan Pal Gurjar)
Minister of State for
Social Justice & Empowerment
Govt. of India

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(Zakir Hussain)	(Karan Singh Dalal)	(Rahish Khan)
MLA, Nuh, Hr.	MLA, Palwal, Hr.	MLA,Punhana,Hr.
Mob.9212456100	Mob.9811165623	Mob.9813258786

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(Udai Bhan)	(Mool Chand Sharma)	(Naseem Ahmad)
MLA, Hodal, Hr.	MLA, Ballabgarh, Hr.	MLA,F.P.Jhirka ,Hr.
Mob.9467781500	Mob.9811556272	Mob.9991515584
Sd/-	Sd/-	Sd/-
(Tek Chand Sharma)	(Seema Trikha)	(Kehar Singh)
MLA, Prithla, Hr.	MLA, Badkhal, Hr.	MLA,Hathin,Hr.
Mob.9811527009	Mob.8195900087	Mob.9813136990
Sd/-	Sd/-	
(Lalit Nagar)	(Tejpal Tanwar)	
MLA, Tigon, Hr.	MLA, Sohna, Hr.	
Mob.9811201444	Mob.9899381020	

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार को इस कार्य के लिए मेवात के लगते हुए जिले की जनता दुआएं देगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में सरकार द्वारा कई बार देखने में आता है कि इमीडिएटली जिस तरह से बहुत से रीजनल सैंटर खुल जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में सैंटर खुल जाते हैं और कई स्थानों पर सैंटर्ज खुल जाते हैं इसलिए मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है कि ड्राईविंग स्कूल के लिए जहां पर कई स्थानों पर सरकारी बिल्डिज़ भी खाली पड़ी हुई है, ड्राईविंग स्कूल खुलवाने की मेहरबानी करें तथा आज ही इसकी सदन में घोषणा करें।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की बात ठीक है कि वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2019 तक 34137 नए हैवी ड्राईविंग लाईसैंसों का नवीनीकरण हुआ है मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से लेकर वर्ष 2019 में मेवात जिले में कितने लाइसैंस बने हैं और कितने रिन्यू किए गए हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जिन ड्राईवरों के लाईसैंस गुरूग्राम या मेवात जिले से बने थे, उन ड्राईवरों के सभी डॉक्यूमैंटस कंपलीट थे, जैसा कि मंत्री जी कह रहे थे कि उनके पास फर्जी डॉक्यूमैंट्स थे । अध्यक्ष महोदय, कभी तो नूंह के अधिकारी कह देते हैं कि आप गुरूग्राम में जाकर लाईसैंस रिन्यू करवायें और गुरूग्राम के अधिकारी कह देते हैं कि नूंह में जाकर लाईसैंस रिन्यू करवायें। इस तरह से आज वे ड्राईवर धक्के खाने को मजबूर हो रहे हैं फिर भी उन ड्राईवरों के नए हैवी ड्राईविंग लाईसैंस रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नए हैवी ड्राईविंग लाईसैंसों की

डिटेल्ज़ बताने का कष्ट करें और दूसरा यह है कि पूरे डॉक्यूमेंटस होने के बावजूद भी उनको धक्के खाने को मजबूर होना पड़ा है तो इस बात का हाउस में आश्वासन दें कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम किया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन ड्राईवरों के पास ओरिजनल डॉक्यूमेंटस हैं उनके लाईसैंस बनवाने का कष्ट करें ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उन पर सरकार पूरा गौर करने का काम करेगी । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार में यह मामला अंडर कंसीड्रेशन है । जैसा कि मेरे साथी विधायक ने पूछा कि वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2019 तक नूंह जिले में कितने लाईसैंस नये बने और कितने रिन्यू हुए । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में नूंह जिले में 50 और पलवल जिले में 133 नए हैवी ड्राईविंग लाईसैंस बने और इसी तरह से नूंह जिले में 4952 और पलवल जिले में 1007 लाईसैंस रिन्यू किए गए । वर्ष 2015 में नूंह जिले में 26 और पलवल जिले में 590 लाईसैंस बने और इसी तरह से नूंह जिले में 4456 और पलवल जिले में 937 रिन्यू किए गए । वर्ष 2016 में नूंह जिले में 27 और पलवल जिले में 482 नए लाईसैंस बने और इसी तरह से नूंह जिले में 1129 और पलवल जिले में 1213 लाईसैंस रिन्यू किए । वर्ष 2017 में नूंह जिले में 434 और पलवल जिले में 170 लाईसैंस बने और इसी तरह से नूंह जिले में 3613 और पलवल जिले में 1748 लाईसैंस रिन्यू किए गए । वर्ष 2018 में नूंह जिले में 469 और पलवल जिले में 1150 लाईसैंस बने और इसी तरह से नूंह जिले में 86 और पलवल जिले में 1479 लाईसैंस रिन्यू/जारी किए गए । दिनांक 01.01.2019 से लेकर दिनांक 08.02.2019 तक नूंह जिले में 128 और पलवल जिले में 42 लाईसैंस बने और इसी तरह से नूंह जिले में 58 और पलवल जिले में 183 लाईसैंस रिन्यू किए गए ।

कन्या राजकीय महाविद्यालय, सैक्टर–42, चण्ड़ीगढ़ के प्रोफेसर्ज एवं विद्यार्थियों का स्वागत

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, आज कन्या महाविद्यालय, सैक्टर–42, चण्ड़ीगढ़ के प्रोफेसर्ज एवं विद्यार्थी हमारे सदन की दर्शक–दीर्घा में सदन की कार्यवाही को देखने के लिए आई हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से सभी छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनका स्वागत करता हूं ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारंभ)

To Increase the Milling Rate of Rice

***2947. Shri Aseem Goel :** Will the Minister of State for Food and Supplies be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the milling rate of Rice in the State on the pattern of adjoining States; if so , the details there of ?

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री कर्ण देव कम्बोज) : महोदय, हॉ, राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से माननीय उपभोक्ता मामले खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री, भारत सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान की कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्ज को मिलिंग चार्जिज की अदा की जाने वाली राशि 10/– रूपये प्रति क्विंटल से बढाकर 15/– रूपये प्रति क्विंटल करने बारे अनुरोध किया गया है।

श्री असीम गोयल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हरियाणा प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश में 900 राईस मिलर किसानों के धान को क्रश करके सरकार को देते हैं जोकि एक प्रकार से जोखिमपूर्ण काम है। केन्द्र सरकार की तरफ से लगभग 25 साल पहले 10/– रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलिंग रेट तय किया गया था जोकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बहुत ही कम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा जो 10/– रुपये प्रति क्विंटल का मिलिंग रेट निर्धारित किया गया है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार की तरफ से 40/– रुपये अतिरिक्त जोड़कर दिये जाते हैं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस 10/– रुपये की राशि में 30/– अतिरिक्त जोड़कर दिये जाते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस 10/– रुपये की राशि में 28/– रुपये अतिरिक्त जोड़कर दिये जाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस 10/– रुपये की राशि में 30/– अतिरिक्त जोड़कर दिये जाते हैं और इसी प्रकार से तेलंगाना राज्य की सरकार द्वारा इस 10/– रुपये की राशि में 15/– अतिरिक्त जोड़कर दिये जाते हैं। इस अतिरिक्त राशि को हरियाणा सरकार की तरफ से 5/– रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया गया है यह बहुत ही कम है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि इस राशि को कम से कम 5/– रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से

बढ़ाया जाये ताकि हरियाणा प्रदेश के राइस मिलर्ज़ को उनकी मेहनत और जोखिम का वाजिब हक मिल सके। विगत धान के सीज़न में हरियाणा के राईस मिलर्ज़ द्वारा 5 करोड़ 30 लाख मीट्रिक धान को क्रश किया गया है जोकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से मेरा पुनः अनुरोध है कि इस मिलिंग रेट को हरियाणा सरकार की तरफ से कम से कम 20/– रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाकर दिया जाये।

श्री कर्ण देव कम्बोज़ : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री असीम गोयल जी को यह कहना है कि उनकी यह चिंता पूरी तरह से वाजिब है। इसके लिए प्रदेश के राइस मिलर्ज़ मुझे भी आकर मिले हैं। मैं भी यह मानता हूं कि उनकी यह समस्या पूरी तरह से न्यायसंगत हैं। सम्मानित साथी ने जिन स्टेट्स का यहां पर जिक्र किया है हम उनके यहां से पूरी की पूरी पॉलिसी डिटेल रूप में मंगवाकर उसको एग्जामिन करवा लेते हैं। उसके बाद हम भी उनको इन प्रदेशों के मुताबिक अतिरिक्त राशि जोड़कर भुगतान करने का प्रावधान अपने यहां भी कर देंगे।

श्री असीम गोयल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिन स्टेट्स के बारे में मैंने यहां पर जिक्र किया है उन सभी स्टेट्स के पत्र मेरे पास हैं उनका एक सैट मैं सदन की टेबल पर रख देता हूं और एक सैट माननीय मंत्री जी को भी दे देता हूं। अध्यक्ष जी, हरियाणा राईस मिलर्ज़ के चीफ पैट्रन के नाते जब भी मैं और माननीय सदस्य श्री सुभाष सुधा जी माननीय मंत्री जी के पास गये तब उन्होंने उनकी सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। हमारे माननीय साथी श्री सुभाष सुधा जी और श्री बख्शीश सिंह विर्क जी भी यहां बैठे हैं इन दोनों माननीय सदस्यों का भी यही मत है कि इस राशि को अधिक से अधिक बढ़ाया जाये इसलिए मेरा भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन है कि मिलिंग रेट की राशि को बढ़ाया जाये।

श्री बख्शीश सिंह विर्कः अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार मिर्ल्स को यह 20 रुपये का लाभ देगी तो उससे बहुत फायदा होगा। इसके अतिरिक्त मेरा एक सुझाव और है कि सरकार मिलर्स से एक क्विंटल पैडी के बदले 67 किलोग्राम चावल लेती है जिससे उनको नुकसान होता है इसलिए इसको घटा कर 64 किलोग्राम किया जाये ताकि मिर्ल्स को नुकसान न हो।

श्री कर्ण देव कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, कई मिल्र्स की तरफ से भी यह डिमांड आई थी कि आजकल पैडी की हारवेस्टिंग कम्बाइन से होती है जिसके कारण जीरी में नमी रह जाती है। एक क्विंटल जीरी में से जितना चावल निकलना चाहिए उतना हमें प्राप्त नहीं हो पाता है इसलिए प्रति क्विंटल जो 67 किलोग्राम चावल सरकार मिलर्स से लेती है उसको कम करके 64 किलोग्राम किया जाये ताकि मिलर्स को नुकसान न हो। सर, इस बारे में हमने भारत सरकार को लिख कर भेजा हुआ है कि इस 67 किलोग्राम चावल को घटाकर 64 किलोग्राम किया जाये। यदि केन्द्र सरकार से हमें इस बारे में स्वीकृति मिल जायेगी तो इसको भी लागू कर दिया जायेगा।

.....

To Open Medical College

***2970. Shri Umesh Aggarwal :** Will the Medical Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a medical college in Kherki Majra of Gurugram; if so, the details thereof togetherwith the time by which the abovesaid college is likely to opened ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : हॉ, श्रीमान् जी। गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, नगर निगम गुरूग्राम एवं श्री शीतला माता देवी श्राईन बोर्ड के सहयोग से गांव खेड़की माजरा, सैक्टर–102, गुरूग्राम में एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कर रहा है। परियोजना प्रबंधन परामर्श का कार्य दिनांक 3 जनवरी 2019 को मैसर्ज उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) को आवंटित कर दिया गया है।

श्री उमेश अग्रवालः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि वे गुरूग्राम में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल बनेगा वह कितने बैड का बनेगा? कब तक इसके बनने की सम्भावना है क्योंकि अभी तक तो केवल परियोजना के प्रबन्ध समिति परामर्श की बात हुई है। इसका टैंडर 3.1.2019 को अलॉट किया गया है। इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है तथा कितने चरणों में यह काम पूरा होगा यह माननीय मंत्री जी कृपया बतायें

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इस कॉलेज का काम हमने अलॉट कर दिया है और यही कम्पनी इसका प्रोजैक्ट प्लान बनायेगी और यही इसको कंस्ट्रक्ट करेगी। इसके साथ ही साथ हमने तीन कॉलेज और बनाने का वर्क भी अलॉट कर दिया है। गवर्नमैंट मेडिकल कॉलेज गांव प्रेम नगर, जिला भिवानी का वर्क हमने मै. ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी लि. को अलॉट किया है। इसी प्रकार से गवर्नमैंट मेडिकल कॉलेज गांव हैबतपुर, जिला जीन्द का काम हमने पी.डब्ल्यू.डी. बी. एण्ड आर. को अलॉट कर दिया है। गवर्नमैंट मेडिकल कॉलेज गांव कोरियावास, जिला महेन्द्रगढ़ का वर्क भी हमने पी.डब्ल्यू.डी. बी. एण्ड आर. को अलॉट कर दिया है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसकी ऐस्टीमेटिड कॉस्ट क्या होगी तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि गुरूग्राम में जो मेडिकल कॉलेज बनेगा उसकी कॉस्ट 500 करोड़ रुपये कॉस्ट होगी, जीन्द में जो मेडिकल कॉलेज बनेगा उसकी कॉस्ट 550 करोड़ रुपये होगी, भिवानी में जो मेडिकल कॉलेज बनेगा उसकी 372 करोड़ रुपये और जो महेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा उसकी कॉस्ट 500 करोड़ रुपये होगी और मैंबर ने इसकी टाईम लाईन भी पूछी है । गुरूग्राम का जो मैडिकल कॉलेज है वह 36 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा । जीन्द का जो कॉलेज है, वह 24 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा । जो भिवानी का कॉलेज है वह 27 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा और जो महेन्द्रगढ़ का कॉलेज है वह 24 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा । जहां तक इन्होंने सीट की बात कही है तो ये चारों कॉलेज इनीशियली 100–100 सीट के बनाए जाएंगे ।

श्री उमेश अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह किया था कि इस कॉलेज के साथ जो हॉस्पीटल बनेगा, वह कितने बैड का होगा ? इसमें एक छोटी सी शंका और रह गई है कि अभी इसका जो वर्क अलॉट किया गया है क्या उसमें परियोजना प्रबंधन परामर्श का वर्क अलॉट किया है या डिवैल्पमैंट वर्क का किया है ? कृपा इसको भी मंत्री जी क्लीयर करें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यहां पर 500 बैड का होस्पीटल बनाया जाएगा । यह हर मैडिकल कॉलेज के लिए जरूरी होता है। कोई भी होस्पीटल मिनिमम 300 बैड का और ज्यादा से ज्यादा 500 बैड का बनाया जाता है । उसके बिना मैडिकल कॉलेज खोलने की एम.सी.आई. इजाजत नहीं देती है । जहां तक इन्होंने कहा है कि यह खाली प्लान बनाने का कॉन्ट्रक्ट दिया है ऐसा नहीं है । वह उन चारों कॉलेज का प्लान भी बनाएंगे । वह हमसे एप्रूव भी करवाएंगे और वह कॉन्ट्रैक्ट भी

करेंगे । उसका सिविल वर्क भी इन्हीं एजेंसियों को दिया गया है । इसके फुल एण्ड फाईनल टैंडर हो चुके हैं ।

श्री कुलवंत राम बाजीगर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे गुहला चीका में पी.एच.सी. बनाने की मंजूरी हुई थी जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी लेकिन उसकी बिल्डिंग नहीं है । एक चौपाल में बैठकर गुजारा कर रहे हैं । इसलिए वह बिल्डिंग कब तक बन जाएगी ? वह बहुत ज्यादा जरूरी है और वह माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल अलग विभाग का है । यह एम.ई.आर. का प्रश्न चल रहा है लेकिन फिर भी मैं आदरणीय साथी को बताना चाहता हूं कि यें हमें इसका प्रपोजल भेज दें। हम इस बिल्डिंग को बना देंगे ।

श्रीमती प्रेम लता : अध्यक्ष महोदय, जीन्द में एक मैडिकल कॉलेज बन रहा है उसका काम तो शुरू हो गया है लेकिन वह काम आगे चल नहीं रहा है तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उस कॉलेज का काम जल्दी करवाया जाए ।

————————

Enhanced Compensation to the Farmers

***2925. Shri Lalit Nagar :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that enhanced compensation of Rs.200 crore in lieu of acquired 1029 acres of land of the 19 villages to Tigaon Assembly Constituency has not been disbursed till to date; and

(b) If so, the time by which the above said amount of compensation is likely to be disbursed together with the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी,

(ए) तिगांव विधान सभा क्षेत्र के 19 गांवों की 1029 एकड़ की बजाए कुल 1647.20 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया। माननीय अपर जिला न्यायाधीश की अदालत द्वारा 882.63 करोड़ रूपये की राशि के मुआवजे की बढोतरी की गई जिसमे से 209.78 करोड रूपये की राशि भूमि मालिकों को वितारित की जा चुकी है। भूमि मालिकों/राज्य सरकार द्वारा दायर अपीलें अभी तक माननीय उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय मे निर्णय हेतु लम्बित है।

(बी) उपरोक्त (ए) मे वर्णित बकाया बढ़े हुए मुआवजे की राशि की अदायगी मामलों के निर्णय के बाद किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा कि तिगांव विधान सभा के 19 गांवों की टोटल 1647.20 एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी । इसमें से जो 1029 एकड़ जमीन का मामला बचा है उसको ए.डी.जे.कोर्ट ने उस कम्पंसेशन को बढ़ाकर 882.63 करोड़ रुपये कर दिया गया है । उसमें से भी 209.78 करोड़ रुपये दे दिया गया है । अभी कुछ लैंड ऑनर्स की और कुछ स्टेट गवर्नमैंट की अपील ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है । हरियाणा सरकार ने बाकायदा जितना भी मुआवजा देना है उसका एक क्रम बना दिया है और उसको तय कर दिया है कि जो ओरिजनल अवॉर्ड था उसको पहले पे कर दिया जाए जिसमें कोई डिस्प्युट नहीं है । या जो अन्तिम स्थिति प्राप्त कर गया है जिसमें कोई लिटिगेशन पैंडिंग नहीं है उसकी प्राथमिकता बनाकर के और उनका एक क्रम बनाकर उनको रिलीज करते जा रहे हैं लेकिन जो मैटर अभी कोर्ट में पैंडिंग है और उसकी अन्तिम स्थिति होने का इन्तजार है । जब वह अन्तिम स्थिति हो जाएगी तो उसके बाद उनका मुआवजा दे दिया जाएगा ।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा के ये 19 गांवों के ऐसे हजारों किसान हैं जिनमें कोई लिटिगेशन नहीं है। ये किसान बढ़ा हुआ मुआवजा प्राप्त करने के लिए कोर्ट में गए थे और माननीय हाई कोर्ट ने यह आदेश भी कर दिया था कि इन किसानों को मुआवजा बढ़ाकर दे दिया जाए फिर भी उन्होंने किसानों को बढ़ाकर मुआवजा नहीं दिया । उसके बाद वह किसान सुप्रीम कोर्ट में चले गए फिर उनका केस सुप्रीम कोर्ट से वापिस हाई कोर्ट में भेज दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह बेचारे किसान 5 वर्ष से परेशान हैं । वह दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं । कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जब किसान डी.सी. के दफ्तर के बाहर धरना–प्रदर्शन न करते हों । उन लोगों में किसी ने अपनी बेटियों की शादी करनी है, किसी ने अपना घर बनाना है, कोई बीमार है इसलिए वे बेचारे मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मुआवजा मिले और कब उनके काम आगे बढ़ें। इन किसानों की कोई लिटिगेशन नहीं है क्योंकि इनके बढ़े हुए मुआवजे के लिए तो माननीय हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश दे दिए हैं। जब हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिए हैं तो मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन किसानों के साथ बातचीत करके उनको मुआवजा दिलाने का काम करें। वैसे भी सरकार किसान हितैषी होने की बात करती है। यह किसान अपने मुआवजे के लिए पांच वर्ष से लगातार

चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। सरकार को इन्हें मुआवजा देने का काम करना चाहिए और इनका मुआवजा कुछ ज्यादा भी नहीं है। लगभग 680 करोड़ के आसपास इनका मुआवजा बैलेंस है। अतः सरकार की तरफ से यह मुआवजा उनको जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। दूसरा हरियाणा लैंड पॉलिसी के तहत इन किसानों के परिवारों को एक–एक सरकारी नौकरी तथा उचित दामों पर प्लॉट देने का काम किया जाये। वैसे इन किसानों को प्लॉट देने का वायदा कर भी लिया गया था कि एक जमीदार जिसका एक खाता है उसको एक प्लॉट दिया जायेगा लेकिन वहां पर प्लॉट्स के मार्किट रेट लगाये जा रहे है जो कि ठीक बात नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जब इन किसानों की जमीन में से ही प्लॉट देना है तो सरकार को उनको यह प्लॉट्स उचित दामों पर देने का काम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद में जमीदारों का बहुत बुरा हाल है। 19 गांवों के जमीदार आई.एम.टी. के पास पिछले डेढ़ वर्ष से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन जमीदारों ने भूख हड़ताल कर ली थी। जब इन्हें लगा कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है तो बेचारों ने खुद ही भूख हड़ताल भी तोड दी। आज भी वे हड़ताल पर बैठे हैं तो उन किसानों के लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि उन्हें दरियादिली दिखाते हुए, इन किसानों के साथ बैठना चाहिए और इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। यही नहीं अगर सरकार इन किसानों की समस्या को सुलझाना चाहती है तो मैं खुद इन किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेकर आता हूं और बातचीत के माध्यम से इन किसानों को कुछ न कुछ मुआवजा देकर इस समस्या को निपटाना चाहिए।

कैप्टन अभिमन्युः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल भी किए हैं और सुझाव भी दिए हैं। सवाल के उत्तर में तो यह कहूंगा कि उन्होंने जो एक जानकारी दी है कि मामला पैंडिंग नहीं है और फिर खुद ही कहा है कि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट से रैफर होकर माननीय हाई कोर्ट में आया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में हकीकत यह है कि सैक्टर 75, 76, 77, 78 से लेकर 89 तक का जो एरिया है, इसके लिए इनकी कांग्रेस की सरकार के वर्ष 2010–2011 के दौरान दो रेट अर्थात 16 लाख रुपये और 42 लाख रुपये के हिसाब से अवार्ड हुआ था लेकिन किसान इनके द्वारा दिए गए मुआवजे से संतुष्ट नहीं थे जिसके लिए किसानों ने विरोध किया और उन्हें मजबूर होकर अपील में जाना पड़ा। आज जो किसान दर–दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं यह सब इनकी वजह से

है। अगर इन कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा इन किसानों को ओरिजिनल अवार्ड देते समय ईमानदारी बरत ली जाती तो जिस दरियादिली की आज हमारे साथी उम्मीद कर रहे हैं, यदि अवार्ड करते समय यही दरियादिली कांग्रेस पार्टी के लोग दिखा देते तो आज इन किसानों को दर–दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती और किसानों के परिवारों के जिन कष्टों को आज सदन के माध्यम से बताया जा रहा है, अगर किसानों की समस्या को ये लोग अपनी सरकार के समय सुलझा देते तो आज कोई समस्या ही नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, यह समस्या भी उन सभी कांटो रूपी समस्याओं में से एक है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़कर गई थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा खोदे गए गडढों को भरने में लगी हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, सरकार को बने 5 साल पूरे होने जा रहे हैं अभी तक यह लोग गड्ढे नहीं भर सके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिह कादियानः अध्यक्ष महोदय, अब तो सरकार का इन गड्ढ़ों में गिरने का समय आ गया है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब मैंने इन लोगों की बातों को पूरे ध्यान से सुना है और अब जबकि मैं जवाब दे रहा हूँ तो इनको मेरी बात को भी ध्यान से सुनना चाहिए। 16 लाख रुपये वाला जो अवार्ड है वह 585 रुपये प्रति गज के हिसाब से बना है और 42 लाख रुपये वाला अवार्ड 1118 रुपये प्रति गज के हिसाब से बना है। आज भी इस संबंध में अपील कोर्ट में पैंडिंग है। जैसे ही इस संबंध में कोई फैसला आता है तो यह मुआवजा किसानों को दिया जायेगा लेकिन जहां तक जॉब या प्लॉट देने की बात है, इस संबंध में एक नीति इनकी सरकार के समय में बनी थी, उसी नीति के आधार पर जमीन अधिग्रहित किसानों को उनका हक देने का काम किया जायेगा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

.....

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Flyover

*__2937. Shri Tek Chand Sharma :__ Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the flyover in villages Baghola, Prithla and

Sikri on National Highway; if so, the time by which these are likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान् जी, पृथला तथा सीकरी में उपरि पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है परन्तु भगोला में उपरि पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पृथला तथा सीकरी में उपरि पुल का निर्माण करने के लिए निविदांए आमंत्रित की जा चुकी हैं, इसलिए इन दोनों उपरि पुलों के निर्माण की समय सीमा अभी नहीं दी जा सकती।

.....

Rehabilitation of Rani Ki Chhatri

***2916. Shri Mool Chand Sharma :** Will the Tourism Minister be pleased to state -

(a) whether it is a fact that the Rani Ki Chhatri build in the Nagri of Raja Ballu of Ballabhgarh is in dilapidated condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Govt. to renovate above said Rani Ki Chhatri together with the time by which it is likely to renovated ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : (क) श्रीमान् जी, हाँ। (ख) पर्यटन विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

.....

Construction of Roads

***2926. Shri Jai Parkash :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the time by which the construction work of roads from village Lamba Kheri to village Sajuma and village Kurar to village Sinand are likely to be completed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान् जी, इन सड़कों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं होने के कारण समय निर्धारण की प्रतिबद्धता नहीं की जा सकती है।

.....

To Develop HSVP Sector

***2930. Shri Ved Narang** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a residential sector of HSVP in Barwala city; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान जी ।

.....

Basic Amenities in CHC Kalanwali

***2954. Shri Balkaur Singh :** Will the Health Minister be pleased to state the time by which the shortage of staff in the upgraded CHC of Kalanwali is likely to be met out togetherwith the time by which the basic amenities are likely to be provided in the above said CHC ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालांवाली में चिकित्सकों की स्थिति निम्न अनुसार हैः–

क्रं0सं0	श्रेणी का नाम	स्वीकृत	भरे हुये	रिक्त	टिप्पणी
1	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	0	1	
2	चिकित्सा अधिकारी	7	2	5	5 नियुक्त चि0अधि0 अनुपस्थित है और दो चि0अधि0 प्रतिनियुक्त किए गए है
3	दंतक सर्जन	1	0	1	डा0 मंयक अरोडा को दिनांक 30.11. 2018 को नियुक्ति दी गई परन्तु कार्यग्रहण नही किया
4	औषधाकारक	2	1	1	
5	पब्लिक हैल्थ नर्स	1	0	1	
6	नर्सिंग सिस्टर	1	0	1	
7	प्रयोगशाला तकनीशियन	2	0	2	
8	स्टाफ नर्स	8	7	1	
9	रेडियोग्राफर	1	0	1	
10	आपरेशन थियेटर सहायक	1	0	1	
11	नेत्र सहायक	1	0	1	
12	एम.पी.एच.एस. (फिमेल)	1	1	0	
13	एम.पी.एच.एस. (मेल)	1	1	0	
14	एम.पी.एच.डब्लयू. (फिमेल)	15	8	7	
15	एम.पी.एच.डब्लयू. (मेल)	15	0	15	
	कुल	**58**	**20**	**38**	

सी0एच0सी0 कालांवाली में दो चिकित्सा अधिकारियों और अन्य अमला को 60 दिनों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया हैः–

1. डा0 रवि कुमार, चिकित्सा अधिकारी
2. डा0 गुरविन्द्र सिंह, चिकित्सा अधिकारी

3. श्री विजेन्द्र सिंह, प्रयोगशाला तकनीशियन
4. श्री नवदीप सिंह, रेडियोग्राफर

नई भर्ती के माध्यम से अमला उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरने के प्रयास किए जाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालांवाली में मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

.....

Shortage of Specialist Doctors

***2922. Shri Pirthi Singh :** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that there is shortage of specialist doctors in Civil Hospital, Narwana; if so, the time by which it is likely to be met out ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

सब डिवीजनल अस्पताल, नरवाना में चिकित्सकों की स्थिति निम्न अनुसार हैः–

क्रं0सं0	श्रेणी का नाम	स्वीकृत	भरे हुये	रिक्त	टिप्पणी
1	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	3	1	2	
2	उप चिकित्सा अधीक्षक	2	0	2	
3	चिकित्सा अधिकारी	42	9	33	5 विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त किए हुए है
4	वरिष्ठ दंतक सर्जन	1	0	1	
5	दंतक सर्जन	2	2	0	
	कुल	**50**	**12**	**38**	

सिविल अस्पताल में तैनात कुल 12 चिकित्सकों में से 2 विशेषज्ञ हैः–

5. डा0 डी.के. बिन्दलीस (नेत्र रोग)
6. डा0 रिया मित्तल (बायो–कैमिस्ट्री)

सब डिवीजनल अस्पताल, नरवाना में 60 दिनों के लिए 5 विशेषज्ञ भी तैनात किए गए हैः–

1. डा0 सचिन (स्त्री रोग)
2. डा0 सुभाष चन्द्र (एनैस्थिसिया)
3. डा0 दिनेश कुमार कौशल (सर्जरी)
4. डा0 आर.एस. पुनिया (शिशू रोग)
5. डा0 शैलेन्द्र डोगरा (अल्ट्रा साउंड प्रशिक्षित)

नई भर्ती के माध्यम से और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स पूरा होने पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के प्रयास किए जाएंगे।

.....

Secial Policy for Irrigation

***2980. Shri Ram Chand Kamboj :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether any special policy has been formulated by the

Government for the Irrigation of the crops of farmers of the blocks declared as dark zone in the state; if so the details thereof?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हाँ, श्रीमान राज्य में डार्क जोन घोषित किए गए ब्लॉकों के लिए सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं और प्रावधान किए गए हैं । इन योजनाओं के संबंध में विवरण सदन के पटल पर है ।

विवरण

1. सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित/डार्क जोन ब्लॉकों में प्रणाली की कुल लागत 85 प्रतिशत अनुदान किसानों को विशेष प्रावधान किया गया है ।

2. राज्य सरकार द्वारा भू–जल विकास तथा सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए 786.20 करोड़ रूपये की लागत की एक अटल भू–जल योजना अनुमोदित की गई है जो कि धनराशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार के विचाराधीन हैं ।

3. किसानों को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एस.टी.पी.) से उपचारित पानी के उपयोग हेतु एक पायलट परियोजना 3.65 करोड़ रूपये अनुमानित लागत की एक परियोजना 30 एमएलडी एस.टी.पी., बरसत रोड, पानीपत से उपचारित पानी को पानीपत जिले के बापोली और समालखा ब्लॉक के 17 गांवों के 9808 एकड़ भूमि में प्रयोग करने हेतु विचाराधीन है ।

4. 21 अधिसूचित/डार्क जोन में पेयजल आपूर्ति और पुराने नलकूपों के नवीनीकरण के अलावा नए नलकूपों के बोर पर भी प्रतिबंध है ।

.....

To Provide Canal Water Twice a Month

***3005. Shri Ranbir Gangwa** : Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken by the Government to provide canal water twice a month in district Hisar together with the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, हिसार जिले के कुछ हिस्सों में पहले से ही महीने में दो बार नहरी पानी पहुंचाया जा रहा है । वहन प्रणाली में पानी की सीमित उपलब्धता के मद्देनज़र पूरे हिसार जिले में पानी की एक समान आपूर्ति नहीं की जा सकती है ।

To set-up Industrial Corridor

***3024. Shri Udai Bhan:** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up any industrial corridor on both sides of KMP and KPG Express High ways near Palwal; if any so, the details thereof?

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल) : हरियाणा सरकार ने पलवल के पास के.एम.पी. और के.जी.पी. के साथ एक नया शहर विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। यह शहर हरियाणा के इन एक्सप्रेस–वे के साथ 5 नए शहरों में प्रस्तावित पंचगाव का हिस्सा होगा, जोकि औद्योगिक, वाणिज्य और आवासीय विकास पर केंद्रित होगा। मामला अभी शुरूआती दौर में है, अभी और विवरणों पर काम करना बाकी है।

To Set Up Solid Waste Management Plant

***2998. Smt Geeta Bhukkal :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the time by which a solid waste management plant is likely to be set up in Jhajjar ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : नगर पालिका झज्जर इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रोहतक कलस्टर का हिस्सा है, जिसके लिए निविदा 15 मार्च 2019 तक आमंत्रित किए जाने की संभावना है। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अगस्त 2021 तक स्थापित हो जायेगा।

.....

To Meet Out The Shortage of Teachers

***3036. Shri Jasbir Singh :** Will the Education Minister be pleased to state the steps taken by the Government to meet out the shortage of the teachers in Government Schools of State?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान जी, अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए अक्तूबर 2014 से निम्नलिखित कदम उठाए गए–

1. 9870 जे0बी0टी0, 1210 टी0जी0टी0 और 8291 पी0जी0टी0 की सीधी भर्ती में से 8376 जे0बी0टी0, 1137 टी0जी0टी0 और 2159 पी0जी0टी0 को कार्यभार ग्रहण करवाना सुनिश्चित किया गया।

2. पदोन्नति के लिए आरक्षित 1942 टी0जी0टी0 एवम् 5291 पी0जी0टी0 के पदों को भरा गया ।

3. सीधी भर्ती के लिए आरक्षित 8450 टी0जी0टी0 एवम् 8145 पी0जी0टी0 के पदों पर मांग भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।

.....

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Sanctioned post in Laboratories

781. Shri Karan Singh Dalal : Will the Agriculture Minister be pleased to state –

(a) the sanctioned strength of Junior System Analyst, Analyst and Senior Analyst in each fertilizers and pesticides laboratories in the State as on 31.12.2018; and

(b) the steps taken by the Government to fill-up the vacant posts in the above said laboratories ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) श्रीमान्, विभाग में वरिष्ठ विश्लेषक के 7 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 5 पद भरे हुये हैं। कनिष्ठ प्रणाली विश्लेषक तथा विश्लेषक के पदों का सम्बन्ध है, यह पद विभाग में स्वीकृत नहीं है।

(ख) वरिष्ठ विश्लेषक के 2 रिक्त पदों की मांग पर्ची हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजी हुई है।

.....

Problem of Drinking Water

746. Shri Pirthi Singh : Will The Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that there is acute shortage of drinking water in Kanha Khera, Karamgarh, Ismailpur, Harnampur, Khanpur, Phulian Kalan, Phulian Khurd, Frain Kalan and Frain Khurd villages of Narwana Assembly Constituency; if so, the time by which

the shortage of drinking water in above said villages is likely to be met out?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डॉ0 बनवारी लाल) : श्री मान जी, गांव कान्हा खेड़ा, कर्मगढ़, हरनामपुर, खानपुर, फुलियां कलां, फुलियां खुर्द, तथा फरैन कलां में पेयजल आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। परन्तु गांव इस्माईलपुर तथा फरैन खुर्द में ग्रीष्म काल के चरम पर पेयजल आपूर्ति में कमी हो जाती है। पेयजल आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिए गांव ईस्माईलपुर में एक स्वतन्त्र जलघर निर्माणाधीन है, जिसकी अनुमानित लागत 149.05 लाख रूपये है तथा फरैन खुर्द में स्वतन्त्र जलघर निर्माणाधीन है, जिसकी अनुमानित लागत 84.80 लाख रूपये है इन दोनों कार्यों के पूर्ण हो जाने की संभावित तिथि क्रमशः 30.09.2019 तथा 31.12. 2019 है। इन नहर आधारित स्वतन्त्र जलघरों के बन जाने के उपरान्त इन दोनों गांवों में पेयजल आपूर्ति की कोई कमी नहीं रहेगी।

To Widen the Bye-pass

774. Shri Ravinder Singh Baliala : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the Bye-Pass constructed on Ghaggar river in Ratia City which connects the Tohana Road to Budhlada road; if so, the time by which the above said Bye-Pass is likely to be widened?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी, टोहाना सड़क को बुढलाडा सड़क तक जोड़ने के लिए रतिया शहर में घग्गर नदी पर बाई–पास के चौड़ीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

.....

To Construct a Multipurpose Pall

759. Shri Pirthi Singh : Will the Industrial Training Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the government to construct a Multi purpose hall in ITI Narwana for conducting examination, seminar and other student activities; if so, the time by which it is likely to be constructed?

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल) : नहीं, श्रीमान जी।

To Metal the Unmetalled Passage

775. Shri Ravinder Singh Baliala : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled road from Village Nangal Dhani up to Nangal road near Bhakhra bridge via village Bora; if so, the time by which the abovesaid passage is likely to be metalled?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी, इस समय लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग द्वारा गांव नांगल ढाणी से नांगल सड़क नजदीक भाखड़ा पुल वाया गांव बोरा तक के कच्चे रास्ते को पक्का करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

.....

Reconstruction of Road

760. Shri Pirthi Singh : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the road from Narwana to Tohana via Dhamtan Sahib is in very bad condition; if so, the time by which it is likely to be reconstructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं श्रीमान् जी, यह सन्तोषजनक अवस्था में है।

.....

राज्यपाल महोदय से संदेश

11.00 बजे

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कल दिनांक 25.02.2019 को श्री सत्यदेव नारायण आर्य, माननीय राज्यपाल महोदय, हरियाणा से एक संदेश प्राप्त हुआ है, जो कि निम्न प्रकार से है –

''प्रिय श्री कंवरपाल,

मुझे, मेरे द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2019 को दिए गए अभिभाषण के बारे में आपके अर्ध–सरकारी पत्र दिनांक 22 फरवरी, 2019 (द्वितीय बैठक) को हरियाणा विधान सभा द्वारा पारित किये गये "धन्यवाद प्रस्ताव" की एक प्रति प्राप्त हुई है।

कृपया इस सम्बन्ध में मेरी हार्दिक सराहना और प्राप्ति सूचना हरियाणा विधान के सभी सम्मानित सदस्यों तक पहुंचा दें। सम्मान सहित।''

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ:–

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार ग्राम तथा नगर आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 2821, दिनांकित 31 जनवरी, 2019।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (1.1.2017 से 31.12.2017) के लागू होने पर राज्य सूचना आयोग, हरियाणा की 12वीं रिपोर्ट।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2015–2016 के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2017–2018 (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018) के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2012–2013 के लिए हरियाणा खादी एवं ग्राम–उद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट`।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013–2014 के लिए हरियाणा खादी एवं ग्राम–उद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2014–2015 के लिए हरियाणा खादी एवं ग्राम–उद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोट ।

मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 की धारा 28 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2016–2018 के लिए हरियाणा मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2017–2018 के लिए वित्तीय लेखे (भाग–I तथा II) ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2017–2018 के लिए विनियोग लेखे ।

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनंदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री अशोक अरोड़ा, सदन की कार्यवाही को देखने के लिए अति विशिष्ट दीर्घा में बैठे हुए हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ।

विभिन्न मामले उठाना/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह ज़ीरो ऑवर है, इसलिए हमें बोलने का मौका दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन इशूज हैं, जो मैं ज़ीरो ओवर में उठाना चाहती हूँ। जो ग्रुप–डी के कांट्रैक्ट पर लगे कर्मचारी थे, उनको निकाल दिया गया है। क्या सरकार इनको दोबारा से रोजगार देने जा रही है, या नहीं ? यह भी सदन को बताया जाये? दूसरी बात यह है कि जो 5100 एजुकेशन मोटीवैटर लगाए गए थे जिन्होंने 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' आदि कार्यक्रमों के अंदर भी भाग लिया था, उनको भी निकाल दिया गया है। क्या सरकार इनके लिए कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी बना रही है या नही? यह भी सदन को बताया जाये। तीसरी बात यह है कि जो एन.एच..एम. कर्मचारी सड़कों पर हैं या जो आंगनवाड़ी हैल्पर्स और टीचर्स भी सड़कों पर हैं, उनके बारे में सरकार क्या करने जा रही है? यह भी सदन को बताया जाये।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूँ कि हथीन में दोहरा हत्याकांड हुआ है। मण्डकोला गांव के दो बच्चे श्री लेखन पुत्र श्री राम सिंह व कुमर पाल उर्फ सुरेश को ईको गाड़ी में जबरदस्ती उठाकर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ले गए थे। गाड़ी में ही पेय पदार्थ में कोई जहरीली चीज पिलाकर गाड़ी को आग लगा कर जघन्य हत्या कर दी गई थी। करीब 9 दिन बाद इनके शव मिले थे। उन शवों को कभी मथुरा से लखनऊ ले जाया गया कभी लखनऊ से मथुरा ले जाया गया। अध्यक्ष महोदय, फिर इस केस को पलवल के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया और केस को ट्रांसफर करने के बाद आज तक कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, हथीन थाने के अंदर अपराधियों के नाम समेत एफ.आई.आर. नं0 0053 के तहत केस दर्ज है। अध्यक्ष महोदय, कुमर पाल की मां अंधी है और उसकी पत्नी गुजर चुकी है। उसके दो बच्चे एक पांच साल का और एक बच्चा सात साल का है। मां अंधी होने के कारण खाना–पीना कुमर पाल स्वयं बनाता था। मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आज उन परिवारों की कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। पूरे गांव में भय का वातावरण बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उन अपराधियों को पकड़ा जाए ताकि परिवार को कोइ न कोई राहत मिल सके।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 22.02.2019 को भी मैंने हल्का जुलाना के किसानों की जमीन के मुआवजे बारे जिक्र किया था। इस संबंध में दिनांक 08.03.2018 को आपके द्वारा स्वयं दिए गए एक ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस संबंध में आश्वासन दिया था और इस संबंध में हमारी पार्टी द्वारा पिछले सत्र में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया गया था। अध्यक्ष महोदय, आपने इसके बारे में लिखित में ऑर्डर दिया हुआ है कि संसदीय कार्य मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे। एन.एच रोहतक से जीन्द की तरफ जो हाई–वे बन रहा था तो उस समय जुलाना हल्के के पांच–छः गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि आपके निर्देश के बावजूद भी एक साल हो गया है लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। (इस समय ऑर्डर की कॉपी अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई।) एक साल से किसान धरना दे रहे थे। सरकार के मंत्री वहां गए थे और आश्वासन देकर आए थे कि तुम्हें उचित मुआवजा दिया जायेगा। हमारे यहां 12 लाख रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया गया जबकि हमारे से पीछे वाले गांवों में 70 लाख रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया गया और हमारे से आगे की तरफ वाले गांवों में 65 लाख रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया गया । पौली, किलाजफरगढ़, शादीपुर जुलाना, जुलाना, बुड़ढ़ा खेड़ालाठर, गतौली, करसौला, जयजयवंती, बिशनपुरा, अशरफगढ़, बिरोली, अनूपगढ़ आदि ये सारे के सारे गांव अपने मुआवजे के लिए धरने पर बैठे थे उनको आश्वासन देने के बाद भी आज तक मुआवजा नहीं दिया गया । इस बार भी ग्रीन फील्ड नैशनल हाइवे के लिए जो जमीन ली गई थी उसमें भी हमारे साथ पक्षपात हुआ है । हमारे क्षेत्र के गांवों किलाजफरगढ़, लिजवाना कलां, फतेहगढ़, लिजवाना खुर्द, नन्दगढ़ चाबरी, बुढ़ाखेड़ालाठर, आसन, सिवाहा आदि गांवों की तरफ 14–14 लाख रुपये दिए गए और दूसरे जिलों में 70–70 लाख रुपये दिए गए । अध्यक्ष महोदय, यह हमारे साथ सरासर ज्यादती है । अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि मुझे जो आश्वासन दिया गया था उसके अनुसार आप उस पर कार्रवाई करवाइये । मैंने आपको 'एक्सटैंशन लेक्चरर्स एसोशियेशन' के संबंध में कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था । यू.जी.सी. और 7वें वेतन आयोग के नॉर्म्स हैं कि उनको 57,700 रूपये तनख्वाह दी जानी चाहिए । सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 2013 का पंजाब बनाम जगजीत सिंह के केस में फैसला है कि 'समान काम समान वेतन' के आधार पर तनख्वाह देनी चाहिए ।

एक्सटैंशन लेक्चरर्स एसोशियेशन नेट क्वालीफाइड और पी.एच.डी. होल्डर हैं । बड़ी अजीब बात है हरियाणा में पी.जी.टी. के जो गैस्ट लेक्चरर्स लगे हुए हैं उनको तो 36 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है और एक्सटैंशन लेक्चरर्स एसोशियेशन को 26 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है । यू.जी.सी. और 7वां वेतन आयोग ने उनको 57,700 रुपये देने के लिए कहा है । पी.जी.टी. के जो गैस्ट लेक्चरर्स से ज्यादा पढ़ाई करके 2000 से अधिक यूनीवर्सिटीज़ और कॉलेजिज में जो लेक्चरर्स हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है । मेरी प्रार्थना है कि सरकार उनकी पालना करे यू. जी.सी. और 7वें वेतन आयोग के नॉर्म्स के हिसाब से सैलरी दे । तीसरा विषय यह है कि संपूर्ण हरियाणा का फ्लड एजेंडा तय हो चुका है कि आने वाले वर्ष में फ्लड कैसे कंट्रोल हो ? दुःख की बात है कि अकेले जीन्द जिले को छोड़ दिया गया कि जीन्द का फ्लड एजेंडा बाद में तय करेंगे । इस सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री महोदय फ्लड कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं । मेरा उनसे प्रश्न है कि जब सारे हरियाणा का फ्लड एजेंडा तय कर दिया गया है तो फिर अकेले जीन्द जिले को क्यों छोड़ा गया ? इसके अतिरिक्त जीन्द में वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में बहुत–से किसान बर्बाद हुए हैं । जीन्द में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हुई है ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जीन्द में फ्लड एजेंडा तय न करने का कारण अच्छी तरह से जानते हैं परंतु पता नहीं क्यों वे इस बात को सदन में रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं । जब फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई उस वक्त जींद जिले में आचार संहिता लगी हुई थी । उस समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह निर्देश दिया था कि आचार संहिता हटते ही जीन्द के प्रस्ताव को अलग से फाइल पर लाकर फ्लड एजेंडा तय करने की मंजूरी दे दी जाएगी । फिलहाल इसकी प्रक्रिया चल रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यह कार्य जल्दी ही हो जाएगा ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको 5 कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिए थे। मेरे यह कॉलिंग अटैंशन मोशंज ओ.डी.एफ. प्रोजैक्ट के तहत शौचालयों का निर्माण करवाने उपरांत सरपंचों तथा आम जन का भुगतान न करने बारे, non availability of irrigated water upto tail, किसानों को कम मात्रा में दिए गए मुआवजे के कारण पनपते रोष बारे, protest by NHRM employees and re-employment of Group-D contract employee में है । आप मुझे बताइये कि आपने मेरा एक भी कॉलिंग अटैंशन मोशन क्यों स्वीकार नहीं किया है ?

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैंने आपके दिए हुए कॉलिंग अटैंशन मोशंज को मन्जूर नहीं किया है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर आप मेरे दिए हुए कॉलिंग अटैंशन मोशंज को रिजैक्ट कर रहे हो तो उन्हें कम से कम रिकॉर्ड पर तो लाइये । मैंने 5–5 अहम मुद्दों पर कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिए थे । आपने हमें यह भी नहीं बताया कि आपने उन्हें रिजैक्ट क्यों किया है ? हमारे पास बहुत–से लोग बड़ी आशाओं के साथ आते हैं और हम उनकी समस्याओं को कॉलिंग अटैंशन मोशंज के माध्यम से सदन में उठाते हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप जब बजट पर बोलो तो उस समय इन विषयों पर चर्चा कर लेना।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब सैशन स्टार्ट होने वाला होता है तो हम लोग उससे पहले बड़ी मेहनत करके कॉलिंग अटैंशन मोशंज पर तैयारी करते हैं । आप हमारे दिए हुए कॉलिंग अटैंशन मोशंज को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं । अगर आप उन्हें स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उन्हें रिकॉर्ड पर तो लाइये । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपने इन कॉलिंग अटैंशन मोशंज के विषयों के बारे में ऑन रिकॉर्ड बोल तो दिया है । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने जो कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टैंट इशूज हैं । हमने बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में भी आपसे यही बात कही थी कि आपको सदन में इस बारे में क्लीयर बोलना चाहिए लेकिन आप उनके नाम नहीं बोल रहे हैं । यह बात ठीक नहीं है । (विघ्न)

श्री अध्यक्षः किरण जी, प्लीज आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश जी अपनी बात रखेंगे।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी कहे रहे थे कि उन्होंने सभी शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं। (विघ्न) माननीय मंत्री जी मेरी बात को ध्यान से सुन लें।

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, आप अपनी बात रखें, माननीय मंत्री जी आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, कल बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि सरकार ने सभी शहीदों के परिवारों को नौकरी दी हैं और सभी रिटायर्ड

सैनिकों को रोजगार दिया है। मेरे एक सैनिक साथी श्री राजेश गुहला हल्के के बादल गांव के शहीद हो गये थे। सरकार की तरफ से माननीय मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार जी भी शहीद सैनिक के दाह संस्कार पर गये थे और उन्होंने कहा था कि सरकार को वीर शहीदों के बलिदान पर गर्व है। माननीय मंत्री जी ने शहीद के परिवार में से एक सदस्य को नौकरी देने का वायदा किया था और 50 लाख रुपये देने का भी वायदा किया था। कल ही उस शहीद के परिवार के सदस्य मुझसे मिले थे और उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा उनके परिवार के एक सदस्य को न तो सरकारी नौकरी दी गयी और न ही पैसे दिये गये हैं। माननीय मंत्री जी बड़े–बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने सभी शहीदों के परिवारों को नौकरी दी हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वे उस वीर शहीद के परिवारों को नौकरी तथा पैसे कब तक दिये जाएंगे ? इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा सवाल फसल बीमा योजना के बारे में है।

कैप्टन अभिमन्यु :अध्यक्ष महोदय, यह क्वैश्चन ऑवर नहीं है।

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा हल्के के बालन गांव के किसानों को उनकी खराब हुई फसलों के मुआवजे का पैसा नहीं मिला है और मेरे पास उस गांव की पंचायत द्वारा पास किया गया रैजोल्यूशन भी है परन्तु माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि सरकार ने किसानों को करोड़ों रुपये का मुआवजा दे दिया है।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है उन्होंने बताया कि एक शहीद सैनिक के परिवार को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार के लिए शहीद सैनिकों के परिवार भगवान से कम नहीं है। यह रिकार्ड की बात है और मैंने बजट स्पीच में भी कहा है कि हमारी सरकार ने सभी शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने का काम किया है। यह आंकड़ा पुलिस में भर्ती किये गये सैनिकों को मिलाकर लगभग 18,000–20,000 के करीब नौकरियां देने का बनता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मैंने तो माननीय मंत्री जी से यही पूछा है कि उस शहीद सैनिक के परिवार के सदस्य को नौकरी कब देंगे ? इसके बारे में बता दें।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के साढ़े 4 साल के कार्यकाल में 273 शहीद सैनिकों के परिवारों को

नौकरियां दी हैं। सन् 1971 की लड़ाई में जो सैनिक शहीद हो गये थे, उनके परिवारों की तीसरी पीढ़ी के बच्चों को भी नौकरी दी है।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप जवाब सुन लें।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही सीनियर मैम्बर हैं और वे केन्द्र में भी मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने भी कानून/नियम बनाये हैं। इसलिए उनके पास जो दस्तावेज हैं वे आपके माध्यम से मुझे दे दें। हम सरकार द्वारा बनाये गये नियम/नीतियों के तहत शहीद परिवार के अधिकारों में थोड़ी–सी भी कमी नहीं रहने देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि शहीद सैनिक के परिवार के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा शहीद सैनिक के परिवार का अपमान किया जा रहा है। सरकार ग्रुप 'डी' ग्रुप की भर्ती की तरह झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार वाहवाही के लिए काम नहीं कर रही है बल्कि शहीद सैनिक परिवारों के सम्मान का काम कर रही है। झूठे काम तो आपकी सरकार के समय में हुआ करते थे। हमारी सरकार के समय में शहीद सैनिकों के आश्रितों को 273 नौकरियां दी गयी और कांग्रेस की सरकार के समय में 8 नौकरियां दी गयी। इसलिए माननीय सदस्य दोनों सरकारों के समय में दी गयी नौकरियों की तुलना करके देख लें कि कौन–सी सरकार के समय में ज्यादा नौकरियां दी गयी हैं। माननीय सदस्यों को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, झूठ बोलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। (शोर एवं व्यवधान) मैं वित्त मंत्री जी को संबंधित दस्तावेज दिखा देता हूं ।

(इस समय श्री जय प्रकाश सदन की वैल में आकर माननीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को संबंधित दस्तावेज दिखाने लगे।)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बार–बार बात की जलेबी बना रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, माननीय मंत्री जी झूठ नहीं बोल रहे हैं बल्कि तथ्यों पर आधारित बातें ही कह रहे हैं। माननीय मंत्री जी आंकड़ों पर आधारित बात कह रहे हैं। यह बात झूठ कैसे हो सकती है ?

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में शहीद सैनिकों के परिवारों को नौकरी देने के बारे में चर्चा चल रही थी। सदन में ये बातें कही गयी कि शहीद सैनिक के परिवार को इग्नोर किया गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि सरकार शहीद सैनिकों के परिवारों को नौकरी दे रही है। माननीय मंत्री जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के सवाल का जवाब दे दिया है। माननीय सदस्य को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैंने सदन में जवाब दे दिया है। माननीय सदस्य के बोलने का तरीका ठीक नहीं हैं। माननीय सदस्य धमकाने की कोशिश न करें। माननीय सदस्य को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें धमकाने की आवश्यकता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय सदस्य को ऐसा करने से रोकें। (विघ्न)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य को बोलने से रोकें। माननीय सदस्य को बात करने की तमीज नहीं है और इनको गलतफहमी हो गयी है। इसलिए माननीय सदस्य बदतमीजी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नायब सैनीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कांग्रेस पार्टी के साथ मिले हुए हैं और उनके कहने पर ही सदन में ऐसी बातें कह रहे हैं। माननीय सदस्य झूठ बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, प्लीज आप बैठ जाएं। इस तरह से बहस करने से हाउस का समय खराब हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने आपके सवाल का जवाब दिया है। इस माननीय सदन में सभी माननीय सदस्यों को परमीशन से ही बोलना चाहिए।

श्री नायब सैनीः अध्यक्ष महोदय, सदन में ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के सवाल का जवाब दे दिया है। हम माननीय सदस्य का सीनियर मैम्बर और पूर्व केन्द्रीय मंत्री होने के कारण सम्मान कर रहे हैं और माननीय सदस्य के द्वारा बनाये गये कानून बता रहे हैं परन्तु माननीय सदस्य बदतमीजी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने जो नाम बताया है, वह शहीद नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य झूठ बोल रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा कि माननीय सदस्य ने जो नाम बताया है वह सैनिक शहीद नहीं हुआ। माननीय सदस्य सदन में झूठ बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, माननीय मंत्री जी ऐसा नहीं कहा। आप चाहें तो सदन की कार्यवाही में से रिकार्ड निकलवाकर देख सकते है।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य झूठ बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं एक सैनिक हूं और सैनिक के दर्द को समझ सकता हूं। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य के लिए सैनिक राजनीति हो सकते हैं परन्तु हमारी सरकार शहीदों का सम्मान करती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए सैनिकों का सम्मान करना राष्ट्रीय धर्म है। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने शहीद सैनिकों की चिताओं पर राजनीति की होगी। हमारी सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों की सेवा की है। शहीद सैनिकों के परिवारों के साथ राजनीति कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने की है। हमारी सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों के 273 परिवारों को नौकरी देकर धर्म निभाने का काम किया है।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी मेरे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं ?

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बता दिया है कि अगर इस जवान के आश्रितों को नीति के अनुसार सहायता देनी बनती है तो हम उनको जरूर सहायता देंगे। हमने जिस तरह से दूसरे शहीदों के परिवार वालों को सहायता दी है, उस तरह से हम इसके आश्रितों को भी सहायता जरूर देंगे।

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, वित्त मंत्री जी ने आपकी सारी बातें मान ली हैं, इसलिए आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

डॉ. पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश जी से कहना चाहूंगा कि ये जिस तरह से इस सदन में बोल रहे हैं, वह कोई बोलने की मर्यादा नहीं है।

श्री अध्यक्षः पवन सैनी जी, कृपया आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से केवल यही प्रश्न करना चाहता हूं कि उस शहीद के आश्रितों को सरकार की तरफ से सहायता क्यों नहीं दी गई है ?

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। अभय सिंह जी, आप अपनी बात रखें।

श्री अभय सिंह चौटालाः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि शहीदों का सम्मान करना, हम सब की एक जिम्मेवारी है और शहीदों के परिवार के सदस्यों को सहायता देना और उनको रोजगार देना, यह हर सरकार की जिम्मेवारी है ताकि जब कभी भी फौज की भर्ती की बात आये तो कोई भी व्यक्ति भर्ती होने से पहले यह न सोचे कि अगर उसने कल को बार्डर पर जाकर अपनी शहादत दे दी तो

उसके पीछे से उसका परिवार किस तरह से अपना पालन–पोषण या भरण–पोषण करेगा। उस जवान को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार उसके शहीद होने के बाद उसके परिवार वालों को मान–सम्मान भी देगी और उनके बच्चों की आगे जिम्मेवारी भी लेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार शहीदों के परिवार वालों को रोजगार और पैसा देने की बात करती है, जोकि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पानीपत जिले के बरोली गांव का कर्मवीर नाम का एक जवान बी.एस.एफ. में था और वह आज से चार या पांच दिन पहले बॉर्डर पर शहीद हो गया है। अध्यक्ष महोदय, उस जवान के साथ सबसे बड़ी अनहोनी यह हुई है कि उसका जो बड़ा भाई था, वह हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी था और एक महीने पहले ऑन–ड्यूटी उसकी डेथ हो गई थी। उसकी 3 लड़की और 1 लड़का है। अध्यक्ष महोदय, इनके मां–बाप के ये दो ही लड़के थे। इसका छोटा भाई कर्मवीर जो है, वह बी.एस.एफ. में था और उसको बार्डर पर गोली मार दी गई थी और वह शहीद हो गया था। इसके भी 2 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का और एक लड़की है। इनके परिवार वालों के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है और आज के समय में इनके परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं बचा है, जो इनके परिवार का आगे पालन–पोषण ठीक ढंग से कर सके। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार जी उनके घर गए थे और वहां पर उस शहीद जवान को सलामी भी दी गई थी, लेकिन ज्यों ही उसके परिवार वालों को पैसे की अनाउंसमैंट देने की बात आई तो यह कहकर रोक दिया गया कि यह बी.एस.एफ. का जवान था और हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सिज के जितने भी जवान हैं, उनको शहीद के दर्जे में शामिल नहीं किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से वे पैंशन से वंचित हो जाते हैं और साथ–ही–साथ उनको सरकार की तरफ से जो सहायता दी जानी चाहिए, उनको उससे भी वंचित होना पड़ जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जिस रोडवेज कर्मचारी की ऑन–ड्यूटी डेथ हो गई थी, उसके परिवार के किसी सदस्य को तुरन्त जॉब दी जानी चाहिए और जो बी.एस.एफ. का जवान शहीद हुआ है, उसके भी परिवार वालों को सरकार की तरफ से तुरन्त सहायता दी जानी चाहिए ताकि उसका परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अभी नेता प्रतिपक्ष ने जिस शहीद की चर्चा की है, मैं उसके घर पर गया था और माननीय मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार जी भी गए थे और उन्होंने वहां पर कहा था कि हम इसकी इन्क्वायरी करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उस जवान को 3 गोली लगी थी और उसे सम्मान के साथ सलामी भी दी गई थी तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यहां पर इन्क्वायरी की बात कहां से आ जाती है ? मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आज तक उसके परिवार के सदस्यों को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी गई है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के नेता और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो बात कही है, उसके जवाब में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि बी.एस.एफ. और सी.आर.पी.एफ. के जो जवान शहीद होते हैं, उनके संबंध में एक एनॉमली क्रिएट हुई हुई है। कारगिल युद्ध के समय में हमारी एक्स एम.पी डॉक्टर सुधा यादव के पति श्री सुखवीर सिंह शहीद हुए थे और इस मामले को लेकर हमारी सरकार और भारत सरकार के बीच में विचार–विमर्श भी चल रहा है। जहां तक पानीपत से श्री कर्मबीर शहीद हुए थे । इन दिनों में बी.एस.एफ के जवानों की शहादत ज्यादा हुई है । राजगढ़ श्री हरिसिंह चौहान शहीद हुए थे, मैं भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राजगढ़ गया था । हरियाणा सरकार की तरफ से आर्मी, बी.एस.एफ. या सी.आर.पी.एफ. के जवानों के शहीद होने पर उनके परजिनों को 50 लाख रुपये की राशि सहायता स्वरूप प्रदान की जाती है । अध्यक्ष महोदय, जहां तक इनकी एनॉमली की बात है तो हरियाणा सरकार ने भारत सरकार के साथ इस मामले को लेकर विचार विमर्श चल रहा है । इस एनॉमली को जल्दी ही दुरुस्त कर लिया जायेगा । मुझे लगता है कि भारत सरकार की तरफ से शहीदों को जो दर्जा दिया जाता है और सुविधाएं दी जाती हैं और वहीं सुविधाएं हरियाणा सरकार ने बी.एस.एफ. और सी.आर.पी.एफ. के शहीदों के परिवारों के 273 बच्चों को उपलब्ध करवाई है । अध्यक्ष महोदय, श्री जय प्रकाश जी ने जिन शहीदों के बारे में जिक्र किया है उन परिवारों को भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी । (विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने आपके समक्ष माननीय सदस्य को कहा कि हम पानीपत से श्री कर्मबीर शहीद के केस को एग्जामिन करके नीति के अनुसार अधिकार बनता है वह निश्चित रूप से उसको दिया जायेगा । हमने इसके साथ ही साथ यह बात भी कही कि

जब सरकार इतनी जिम्मेदारी से काम कर रही है कि सन् 1971 के युद्ध में हुए शहीदों के परिवारों को ढूंढकर और उन शहीदों की तीसरी पीढ़ी को भी मुआवजा देने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इनकी बात का कोई औचित्य भी नहीं बनता था । इस प्रकार की भाषा का उपयोग इनको नहीं करना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हैं। सन् 1971 के परिवारों के लिए सरकार के पास कोई नीति न होकर के भी उन परिवारों की आर्थिक सहायता करने का काम हमने किया है । हमारी सरकार की तरफ से जो सैनिकों के प्रति श्रद्धा है, जो सम्मान का भाव है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है । माननीय सदस्य ने दोनों केसिज़ सदन में बतायें हैं, उन दोनों केसिज़ को तुरन्त एग्ज़ामिन करवाकर के जो उचित कार्रवाही बनेगी वह करने की पूरी कोशिश की जायेगी और सैनिकों के अधिकारों का भी पूरा ख्याल रखा जायेगा । (विघ्न)

श्री श्याम सिंह : अध्यक्ष महोदय, सारन गांव, जिला यमुनानगर का एक लड़का श्री पवन कुमार, S/o श्री अमर सिंह जोकि आसाम में आई.टी.बी.पी. में पोस्टिड था, वह जंगल में पागल हाथी के सामने अचानक आ गया था । उस वक्त उसके तीन साथी और भी थे जो मौके पर ही भाग गये थे । अध्यक्ष महोदय, उस पागल हाथी ने उस लड़के को मार दिया था । अब सरकार उस लड़के को कौन सी कैटेगरी के आधार पर शहीद का दर्जा देगी ? मैं उस लड़के के संस्कार पर भी गया था, उसके परिवार के सदस्यों ने सरकार से रिक्वैस्ट की कि हमारी भी आर्थिक सहायता की जाये । मेरा भी सरकार से अनुरोध है कि उस लड़के के परिवार की आर्थिक मदद की जाये ।

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, प्लीज बैठ जायें । आप ऐसे करोगे तो बजट पर चर्चा होना मुश्किल हो जायेगा। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री श्याम सिंह राणा साहब ने जो बात कही है, सरकार उस बात का जवाब दें ।(विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी बार–बार कह रही हैं तो मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में शहीदों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी और ये बार–बार रिकॉर्ड निकलवाने की बात कहती हैं? हमारी सरकार श्रीमती किरण चौधरी जी की भावनाओं का सम्मान करती है ।(विघ्न) किरण जी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि पहले आप प्रदेश की जनता से माफी मांग लें । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, प्लीज आप बैठ जायें । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि मेरे पिता जी फौज में थे, उस वक्त उनको दो–दो गोलियां लगी थी । अध्यक्ष महोदय, मेरे पिता जी ने देश के दुश्मनों से लौहा लेते हुए एक पैर पर और एक हाथ पर गोली खाई थी । (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी का मैं सम्मान करता हूं क्योंकि ये हमारी सेना से सम्बन्ध रखती हैं । (विघ्न) मैं इनसे सहानुभूति रखता हूं कि 10 साल सरकार में रहने के बावजूद भी फौजियों के लिए कुछ नहीं करवा पाई इसलिए मैं इनकी पीड़ा को समझता हूं । मेरी और श्रीमती किरण चौधरी जी की पीड़ा सांझी है क्योंकि ये भी एक फौजी की बेटी है । (विघ्न) मैं इनका सम्मान करता हूं । आपके पिता जी बड़े वीर बहादुर सैनिक और हमारे सीनियर ऑफिसर थे । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं बहन किरण चौधरी जी को बता देना चाहता हूं कि मेरी मां ने भी 6 बेटे जन्में हैं और तीन बेटे फौज में जाकर आये हैं, मैं अकेला फौज में नहीं गया था, मेरे दो भाई और भी फौज में गये थे इसलिए मैं इनके साथ पूरी सहानुभूति रखता हूं । (विघ्न) स्पीकर सर, श्रीमती किरण चौधरी जी की तकलीफ बड़ी जायज है क्योंकि इनकी रगों में सैनिकों का खून है और इनकी विरासत में सेना है क्योंकि इनके पूर्वजों की कई पीढ़ियां सेना में रही हैं। इसके बावजूद भी ये अपनी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान सैनिकों के लिए कुछ भी नहीं करवा पाई। मैं इनका दर्द समझ सकता हूं। (विघ्न) अध्यक्ष जी, जब किरण चौधरी जी सत्ता पक्ष में बैठती थी उस समय इनको सैनिकों के लिए किसी भी काम को करवाने की सुध नहीं आई। यह भी चिंता की बात है।

वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय सदस्य श्री असीम गोयल जी बजट वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का प्रारम्भ करेंगे।

श्री असीम गोयल (अम्बाला शहर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बजट अनुमान 2019–20 पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, कल इस महान सदन में हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी की दूरदर्शिता के चलते हुए सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया

गया है वो एक दीपक की तरह है। दीपक का प्रकाश किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। यहां पर पुरानी सरकारों ने जो बजट प्रस्तुत किये हैं वे एक टॉर्च की तरह होते थे और टॉर्च का फोकस एक खास स्थान पर ही होता है। इसी प्रकार से पुरानी सरकार द्वारा जो बजट यहां पर प्रस्तुत किये जाते थे उनका फोकस एक खास जिले और एक खास क्षेत्र के ऊपर होता था जबकि हमारी सरकार का जो बजट है वह मृग की कस्तूरी की तरह है। कस्तूरी की तरह हमारी सरकार के इस बजट की सुगंध भी चहुं ओर फैल रही है। इसके विपरीत पुरानी सरकारों का जो बजट होता था वह मृगमरीचिका की तरह होता था जो केवल प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम करता था। प्रदेश की जनता को उसमें दूर से चमक नज़र आती थी लेकिन जब वे उससे रूबरू होते थे तो सिर्फ उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। पहले की सरकारों द्वारा हरियाणा के लोगों के लिए महज़ दिखावे के लिए ही लोक लुभावन नीतियों का प्रचार किया जाता था और हकीकत में उनसे किसी का कोई भला नहीं होता था। (शोर एवं व्यवधान) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार ने अपने 10 साल के शासन काल के दौरान हरियाणा में कोई विकास कार्य नहीं किया लेकिन आज जब हमारी सरकार द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश को चहुंमुखी प्रगति के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है तो ये हरियाणा प्रदेश को प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ भी नहीं देखना चाहते। इसके ऊपर भी इनको आपत्ति होने लग गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कल जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है यह मनोहर सरकार का मनोहारी बजट है। (विघ्न) हमारे माननीय वित्त मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मनोहर छवि, मनोहर सपना, मनोहर बने हरियाणा अपना। इस नाते एक मंत्र को लेकर हमारी सरकार चली हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार के समय में हरियाणा हर हाल में मनोहर बनेगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमारी सरकार के समय में ही सभी जिलों को और हरेक विधान सभा को एक नज़र से देखा गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी ने क्षेत्रवाद, जातिवाद और विकास के भेदभाव के चक्रव्यूह को तोड़कर सबके लिए एक सर्वस्पर्शी बजट बनाया है। आदरणीय अभिमन्यु जी स्वयं एक किसान भी हैं और एक सफल उद्यमी भी हैं। उद्यमी होने के नाते लेबर के दुख–दर्द को भी वे अच्छी प्रकार से समझते हैं। वे सर्विस में रहे हैं इसलिए सर्विसमैन की तकलीफ को भी

अच्छी प्रकार से समझते हैं। इन और ऐसी ही सभी बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया है। मैं इस बजट का पुरजोर अनुमोदन करता हूं। अध्यक्ष जी, कल आदरणीय वित्त मंत्री जी ने चाणक्य की कुछ बातें अपने बजट में उद्धृत की। कौटिल्य ने कहा था कि सरकारी धन सम्बन्धी दायित्व में लगाये व्यक्तियों से पैसा दण्डस्वरूप वसूला जाना चाहिए और उनकी पदोन्नति भी नहीं करनी चाहिए ताकि वे धन का भक्षण न कर सकें बल्कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वे भक्षण किये गये धन को उगल दें। यह पुरानी सरकारों का मंत्र था। इसी प्रकार से हमारी सरकार जिस मंत्र के ऊपर चल रही है वह मंत्र यह है कि– ये अर्थान न भक्षयंति न्यायता वर्धंति च, रागः, प्रिये हते रता ते नित्यः अधिकारी कार्य। अध्यक्ष जी, जो कर्मचारी प्रजा की भलाई के लिए लगे रहते हैं और जो राजा धन नहीं हड़पते बल्कि उसे न्यायसंगत तरीके से आगे बढ़ाते हैं ऐसे लोगों को ही राज का कार्य दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार इस न्यायसम्मत तरीके से हरियाणा के प्रत्येक कोने का विकास करने के लिए भेदभाव को भूलकर, क्षेत्रवाद को भूलकर, जातिवाद को भूलकर तथा भाई–भतीजावाद को भूलकर हरियाणा एक हरियाणवी एक के मंत्र को आगे बढ़ाते हुये काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय बजट में जो आयकर सीमा 5 लाख रुपये की गई है उसके लिए आदरणीय केन्द्रीय वित्त मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2,26,644/– रुपये है और इसका राष्ट्रीय आंकड़ा 1,25,397/– रुपये है यानि 1 लाख रुपये से अधिक पर कैपिटा इन्कम के नाते आज हरियाणा इस देश में प्रति व्यक्ति आय के मामल में दूसरे नम्बर पर है और हरियाणा प्रदेश इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था से भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। 5 एकड़ तक की भूमि की काश्त करने वाले किसान और असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों के परिवार जिनकी मासिक आय 15,000/– रुपये से भी कम है, उनकी वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए, नई स्कीमों के लिए 1500 /– करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जी की भूरि–भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने 1,32,165 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है जो पिछले साल के बजट से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। अन्नदाता केवल अन्नदाता की भूमिका में न रहे। अन्नदाता ऊर्जा दाता

बने, अन्नदाता अपनी कमाई को बढ़ाने के और तरीके खोजे और जो 5 सालों में अन्नदाता की कमाई को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है इस बजट में उसकी साफ–साफ झलक दिखाई देती है। किसान बिजली उपभोक्ता के साथ–साथ बिजली उत्पादक और बिजली आपूर्तिकर्ता बने इसके लिए इस बजट में विभिन्न योजनाओं में उसका प्रावधान किया गया है। सोलर ऐनर्जी के नाते किसान को आगे बढ़ाने की बात बजट में कही गई है। अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट मंडियों का सृजन किया जायेगा। पिंजौर हिमाचल की तलहटी में लगा हुआ है और हिमाचल का सेब पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। पिंजौर में एक बहुत बढ़िया इंटरनेशनल लेवल की सेब की मंडी स्थापित करने की योजना है जिससे हमारे यहां के लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा और उद्योग भी लगेंगे। इसी प्रकार से सोनीपत के सेरसाह में मसालों की एक थोक मंडी और गुरूग्राम में फूलों की थोक मण्डी बनाने की योजना है। इसी तरह से राज्य में पशु पालकों द्वारा फोन पर घर–द्वार पर सचल पशु चिकित्सा सेवायें प्रदान करने के लिये पायलट परियोजना के रुप में आरम्भ में तीन जिलों जीन्द, यमुनानगर और मेवात में पशु संजीवनी सेवा शुरू की जायेगी और बाद में इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में किया जायेगा। पशु पालक को केवल फोन करना है और फोन पर ही डॉक्टर घर आकर पशु का उपचार करेगा। इसी प्रकार से कृषि के लिए 3834 करोड़ रुपये का जो बजट दिया गया है इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री जी का बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसी प्रकार से नम्बरदार जिनके ऊपर पिछली सरकारों में केवल नम्बरदार का तमगा लगा दिया जाता था लेकिन उनके मान–सम्मान की बात कभी नहीं की गई। उनका मानदेय 1500 रुपये से बढ़ा कर 3000/– रुपये मासिक करने का काम हमारी सरकार ने किया और उनको एक मोबाइल फोन देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। अध्यक्ष महोदय, तहसीलों में आधुनिक रिकॉर्ड रुम बनाये गये हैं। पिछली सरकारों में तहसीलों में रिकॉर्ड जला दिये जाते थे और अधिकारी के पास बहुत अच्छा बहाना होता था कि मेरा तो रिकॉर्ड जल गया है। कभी बाढ़ में भी रिकॉर्ड खराब हो जाता था। जमीनों के बहुत–बहुत घपले तहसीलों में होते थे लेकिन हमारी सरकार द्वारा पायलट प्रोजैक्ट के तहत आधुनिक रिकॉर्ड रूम कैथल, जीन्द और सोनीपत में स्थापित किये गये ताकि भविष्य में जमीनों के घोटाले न हों। शीघ्र ही इसको पूरे हरियाणा में स्थापित किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत पहले क्लेम की अदायगी करने वाला

हरियाणा देश में प्रथम राज्य बना। पहले हमारे जो साथी विदेश में रहते थे वे भारत में आकर कहते थे कि विदेशों में अगर हमें कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ जाये तो हम फोन करते हैं और हॉस्पिटल से गाड़ी आती है और हमारा ईलाज करके घर छोड़ कर जाती है। ऐसी योजना के बारे में सुनकर लगता था कि इस देश में यह योजना कैसे संभव हो सकती है ? लेकिन आदरणीय प्रधान मंत्री जी की दूरदर्शिता से पहली बार आदरणीय जे.पी. नड्डा जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वह एक ऐसी योजना लेकर आए जिसमें 10 करोड़ परिवार और लगभग 50 करोड़ भारत के लोग इस आयुषमान भारत की योजना के दायरे में आए हैं । जिनके परिवार का हर साल का 5 लाख रुपये तक का मैडिकल का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी । अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक बार की योजना नहीं है । उन परिवारों को मैडिकल की सुविधा के लिए हर वर्ष 5 लाख रुपये तक मिलेगा । इस योजना में क्लेम देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है । इस योजना की कैटेगरी में हरियाणा के अन्दर साढ़े दस लाख परिवार आए हैं । इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रिपल–बी मोड के ऊपर सीटी स्कैन की कैथ लैब का संचालन किया जा रहा है । हमारे अम्बाला के अन्दर भी जो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह सरकारी अस्पतालों में देने का काम किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के रेवाड़ी के अन्दर 22वां एम्स आया है। झज्जर के बाढ़सा गांव में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बनाया जा रहा है जो दिल्ली के एम्स का विस्तार है । अध्यक्ष महोदय, हमारी आयुर्वेदिक प्रणाली जिसका डंका कभी पूरी दुनिया में बजता था, आज उस आयुर्वेदिक सिस्टम को भुला दिया गया है । मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि चाइना के किसी वैद्य को ये बात पता चली कि भारत के अन्दर आयुर्वेदिक पद्धति की बड़ी प्रशंसा होती है । उसने परीक्षा लेने के लिए अपने एक आदमी को एक लैटर दिया और उसको कहा कि आप इस लैटर को भारत देकर आएं । उस व्यक्ति ने कहा कि इस लैटर में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यह तो खाली है । आप इस लैटर को फलां वैद्य को जाकर देना वह अपने आप ही इस लैटर के बारे में समझ जाएगा लेकिन उस वैद्य ने दो शर्तें रखी कि आप जब तक भारत पहुंचोगे लेकिन रास्ते में जब कभी भी आप आराम के लिए रुकोगे तब आप इमली के पेड़ के नीचे बैठोगे । इमली के ही पत्ते खाओगे और इमली का ही फल खाओगे । वह आदमी 6 महीने बाद जब भारत पहुंचा तो उसका सारा शरीर गल चुका था क्योंकि इमली के अन्दर यह गुण है कि अगर आप उसका ज्यादा सेवन

करते हो तो वह शरीर को गला देती है । जब वह आदमी वह लैटर लेकर भारत में उस वैद्य के पास पहुंचा तो वह मरणासन्न अवस्था में पहुंच चुका था । जब भारत के आयुर्वेदिक वैद्य ने वह चिट्ठी देखी तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था । उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता । मुझे तो चाइना के वैद्य ने यह चिट्ठी दी है और उन्होंने कहा था कि आप इस लैटर के बारे में अपने आप समझ जाओगे। भारतीय वैद्य ने कहा कि आप जब चाइना से आए तो क्या इमली के पेड़ के नीचे बैठ कर आए थे । वह आदमी कहने लगा कि हां, मुझे चाइना के वैद्य का यही आदेश था कि आप जब भी रुकोगे तो इमली के पेड़ के नीचे रुकोगे । फिर उस व्यक्ति को भारत के वैद्य ने भी वैसी ही एक खाली चिट्ठी और दी और उस व्यक्ति को कहा कि इसको चाइना लेकर जाओ। वह व्यक्ति कहने लगा कि प्रभु आप मेरी दशा देखिए। मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। मेरा तो सारा शरीर गल गया है। भारत के वैद्य ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि आप जब चाइना जाओगे तो आप नीम के पेड़ के नीचे बैठते हुए जाना। जब वह व्यक्ति 6 महीने बाद चाइना पहुंचा उसने रास्ते में नीम के पत्तों का सेवन किया और नीम के पेड़ के नीचे बैठा और जब वह चाइना के वैद्य के पास पहुंचा तो चाईना का वैद्य उस व्यक्ति को कहने लगा कि आपको तो मर जाना चाहिए था। वह व्यक्ति कहने लगा कि आपने तो मरने का प्रोग्राम पक्का कर दिया था लेकिन भला हो उस भारतीय वैद्य का जिसने मुझे नीम के पेड़ के नीचे बैठाकर जीवन दान दिया है । हमारी ऐसी आयुर्वेदिक पद्धति को हमारी पुरानी सरकारों ने पूरी तरह से भुलाने का काम किया था लेकिन हमारी सरकार ने उस आयुर्वेदिक पद्धति को जीवित करने के लिए कुरूक्षेत्र और पंचकुला के अन्दर आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का काम किया है। इसके लिए भी मैं सरकार की भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं । शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर आदरणीय राम बिलास जी के मंत्रालय में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया ताकि बच्चों का समग्र विकास हो सके और वह राष्ट्र के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम कर सकें। आदरणीय अध्यक्ष जी, 9वीं से 12वीं तक की बच्चियों के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा में हमारी सरकार ने 22 हजार बच्चियों को फायदा दिया है। ऐसी 22 हजार बच्चियों के घर से स्कूल की दूरी दो किलोमीटर थी उनको सरकार ने निःशुल्क साईकिल्ज प्रदान की हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 36 नये गवर्नमैंट कॉलेज और 2 नई यूनिवर्सिटीज जिनमें से एक गुरूग्राम के अन्दर और एक महर्षि बाल्मीकी संस्कृत महाविद्यालय कैथल के

अन्दर खोला जा रहा है । हरियाणा के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का लाभ मिले इसके लिए सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं, यही नहीं अध्यक्ष महोदय अब तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने जय जवान–जय किसान–जय विज्ञान के नारे के साथ एक नया नाम जोड़ने का काम किया है। अब जय जवान–जय किसान–जय विज्ञान नारे के साथ जय पहलवान जोड़ने का काम हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है। इन खिलाडियों ने हरियाणा की साख को भारत वर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उंचा करने का किया है। राष्ट्रमंडल खेल जो कि वर्ष 2018 में खेले गए थे उनमें भारत 66 पदक जीतकर लाया था जिसमें से अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने 22 पदक जीते थे अर्थात 1/3 हिस्सा हरियाणा प्रदेश का था। इसी प्रकार एशियन गेम्ज में भारत के 69 पदक आये और इनमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने 17 पदक जीते थे। इसी प्रकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 71 खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम किया गया जबकि पूर्व की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल 41 खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम किया था। यही नहीं हमारी सरकार राई के अन्दर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है ताकि हरियाणा के युवाओं का ज्यादा से ज्यादा रूझान खेलों की ओर बढ़े। इसी प्रकार हमारी सरकार ने 8601 खिलाड़ियों को लगभग 213 करोड़ रुपये पुरस्कार राशि देने का काम किया है जबकि पुरानी कांग्रेस की सरकार के समय केवल 51.84 करोड़ रुपये की राशि ही खिलाड़ियों को पुरस्कार के तौर पर दी गई थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए एक नई आई.टी.आई. का सृजन किया गया है और इस सैशन से इस आई.टी.आई. में एडमीशंज शुरू भी हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पेहवा से लेकर अम्बाला शहर जिसकी 50 किलोमीटर की दूरी बनती है, यहां पर एक भी ऐसा शिक्षण संस्थान नहीं था जहां पर ग्रामीण अंचल के बच्चे जाएं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन किया है कि एक आई.टी.आई. इस ग्रामीण अंचल में खोली जाये और उन्होंने इस बात को माना भी है जिसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री श्री विपुल गोयल जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को शायद इस बात की जानकारी होगी कि अम्बाला की आई.टी.आई. सबसे पुरानी आई.टी.आईज में से एक है और इस आई.टी.आई को नैशनल लैवल पर अवार्ड भी मिल चुका है। (विघ्न)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, बहन गीता जी जो कह रही हैं उसके बारे में मुझे भी सब कुछ पता है। वर्ष 1952 में यह आई.टी.आई. बनी थी और इसको माडर्न आई.टी.आई. का खिताब भी मिल चुका है और अब इसके लिए 12 करोड़ रुपये की राशि का बजट भी जारी हो गया है। मैं इसके बारे में अब बताने ही जा रहा था लेकिन इसी बीच बहन गीता जी उठकर बोलने लग गई। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्या को थोड़े धैर्य से बात सुननी चाहिए। मैं तो अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में ही बता रहा था मैं किसी तरह की कोई आलोचना तो कर नहीं रहा था? अगर मैं कोई गलत बात कहूं तो माननीय सदस्या उस पर कटाक्ष कर सकती हैं। 1952 में जब हरियाणा–पंजाब एक हुआ करता था, उस समय की यह आई.टी.आई.है और इस आई.टी.आई. को माडर्न आई.टी.आई. विकसित करने के लिए जो 10 से 12 करोड़ रुपये का बजट अभी सैंक्शन हुआ है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत–बहुत घन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त एक और विषय पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। मेरी विधान सभा क्षेत्र में लखनौर साहब नामक एक गांव है जो कि गुरू गोबिन्द सिंह जी की माता गुज्जर कौर का मायका है और गुरू गोबिन्द सिंह का नानका स्थल है। वर्ष 1969 में कांग्रेस की सरकार के समय महाराजा यादवेन्द्र सिंह जो कि वर्तमान में पंजाब के सी.एम. कैप्टन अमरिन्द्र सिंह के दादा थे, उन्होंने यहां पर एक डिग्री कॉलेज का पत्थर लगाया था लेकिन अफसोस इस बात का है कि पत्थर लगाने के बावजूद यहां पर एक ईंट तक उस कॉलेज के नाम के नहीं लगाई गई। कहने का भाव यह है कि पुरानी सरकारों ने धर्म के उपर भी राजनीति करने का काम किया। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया अनेक लोग यहां से चुनकर आये जैसे नग्गल हल्के से चौधरी हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा जी जीतकर इस सदन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं सिख समाज से हूँ और मैं इस डिग्री कॉलेज को बनाकर अपना ऋण उतारना चाहता हूँ लेकिन इसके बाद उन्होंने भी इस काम के लिए कोई एक ईंट तक लगाने का काम नहीं किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चट्ठा साहब प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, सिंचाई मंत्री भी रहे तथा स्पीकर के पद पर भी सुशोभित रहे लेकिन एक ईंट भी उन्होंने इस डिग्री कॉलेज में लगाने का काम नहीं

किया। मेरे को भी इस विषय की जानकारी नहीं थी मुझे इस बारे में तब जानकारी हुई जबकि वर्ष 2015 में मेरे पास एक पंचायत आई और उसने कहा कि हमारी 15 एकड़ भूमि पिछले लगभग 44–45 साल से एजुकेशन डिपार्टमैंट के नाम पर पड़ी हुई है। जिसका ठेका भी खत्म हो चुका है। इस जमीन को न तो पंचायत ठेके पर दे सकती है, न बो सकती है और न ही इस पर अब तक कोई डिग्री कॉलेज बना है। अध्यक्ष महोदय, अगर 15 एकड़ जमीन का 45 साल का ठेका आता तो इस आमदनी से गांव के विकास के अनेक कार्य करवाये जा सकते थे। मैंने जब विषय समझा तो मैंने उस पंचायत को कहा कि मुझे समय दें लेकिन इतना कहने पर ही पंचायत के लोगों ने मुझसे कहा कि बेटा तुम हमारे में से ही एक हो। आप तो अब राजनीति में आए हो यहां तो राजा यादवेन्द्र सिंह, हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा, निर्मल सिंह, विनोद शर्मा और न जाने कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां आकर चली गई, हमने सबके सामने दुखड़ा रोया है लेकिन किसी एक नेता ने भी इसकी सुध नहीं ली। अध्यक्ष महोदय, मैंने उन लोगों से रिक्वैस्ट की और कहा कि मुझे केवल एक साल का समय दें, जहां 45 साल हो गए हैं वहां 46 साल हो जायेंगे अगर मैं कॉलेज नहीं बनवा पाया तो कम से कम जमीन जरूर एजुकेशन विभाग से आपके नाम ट्रांसफर करवा दूंगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, कॉलेज हमारी सरकार ने बनाया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी पहले यह बताएं कि कौन सा कॉलेज बनाया है? उस कॉलेज का नाम बताएं जो अम्बाला सिटी में आपकी सरकार के समय में बना है? (शोर एवं व्यवधान)

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : अध्यक्ष महोदय, श्री कर्ण देव कम्बोज जी ने कल सदन में कहा था कि वर्ष 2014 से पहले की सरकार का जो कार्यकाल था, उसमें बहुत सी घोषणएं हुईं थी और योजनाओं की नींव रखी गई थी, उन सबकी जांच करवाई जाये, क्योंकि वे घोषणाएं जब पूरी नहीं हो सकती थी तो घोषणाएं की क्यों गई? (शोर एवं व्यवधान) क्या सिर्फ वोट लेने के लिए ही घोषणाएं की गई थी? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला सिटी में कॉलेज बनाया गया था। (शोर एवं व्यवधान) मुझे पूरी जानकारी है कि कॉलेज बनाया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि बहन गीता भुक्कल जी को सही जानकारी नहीं है। जिस कॉलेज की बात माननीय सदस्या कर रही है उस सरकारी स्कूल में आज भी क्लासिज़ लग रही है। हमारी सरकार ने उस स्कूल को कॉलेज की मान्यता दी है और उस कॉलेज की बिल्डिंग का कार्य शुरू हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलवन्त राम बाजीगर : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गुहला चीका में भी पहले की सरकार में कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ और कोई भी स्कूल नया नहीं बना (शोर एवं व्यवधान) विकास के नाम पर कांग्रेस पार्टी केवल पत्थर लगाने का ही काम करती थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं कलायत हल्के की भी विधायक रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि गुहला में विकास के अनेकों कार्य हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने केवल कागजों में ही विकास किया है। विकास के नाम पर पहले केवल पत्थर ही लगाने का काम हुआ करता था। अध्यक्ष महोदय, जिस माता गुज्जर कौर कॉलेज का जिक्र मैं सदन में कर रहा था उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी ने कहा था कि इस कॉलेज को डिग्री कॉलेज बना देते हैं। इस पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि इस कॉलेज को ऐसा बनाया जाये जिससे युवकों को रोजगार मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात आपके माध्यम से सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज दूसरा सरकारी वी.एल.डी.ए. कॉलेज हमारे हल्के में लगभग 37 करोड़ रुपये की लागत से बनने का काम शुरू हो चुका है। जो वर्ष 1969 में कॉलेज बनाने के लिए पत्थर लगा हुआ था उसको हम फोटो फ्रेम करवा कर संभाल कर रखेंगे ताकि आने वाले लोगों को यह पता लग सके कि कांग्रेस पार्टी कैसे धर्म के नाम पर भी राजनीति करती थी?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन श्रीमती गीता भुक्कल एक सीनियर नेता है और कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। श्रीमती किरण चौधरी जी भी बहुत सीनियर नेता है और दिल्ली की राजनीति से हरियाणा की राजनीति में आई हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली सरकार में भी काम कर चुकी हूँ और हरियाणा की सरकार में भी काम कर रही हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में बहनों के साथ एक परम्परा रहती है। बहन गीता जी झज्जर हल्के की बेटी है और उनकी ससुराल कलायत हल्के में पड़ती है। श्री असीम गोयल जी, सदन में जो जानकारी दे रहे हैं वह रिकॉर्ड के आधार पर ही दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, इसका आशय यह नहीं है कि हम अपनी प्रशंसा अपने आप करना चाहते हैं । हरियाणा में साढ़े चार साल में 46 नये कॉलेजिज खुले हैं जिनमें से 32 महिला विश्वविद्यालय हैं । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 10 फरवरी को 22 कॉलेजिज की एक–साथ आधारशिला रखी है । अध्यक्ष महोदय, नांगल–चौधरी राजस्थान के बॉर्डर का इलाका है । मैं बताना चाहता हूं कि हमने निजामपुर, उनाणी, सतनाली आदि 32 स्थानों पर 32 महिला महाविद्यालय एक–साथ खोले हैं । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अनेक सरकारी स्कूल्ज को बंद कर दिया गया है । (शोर एवं व्यवधान) निजी स्कूल्ज को बढ़ावा दिया जा रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्या किरण चौधरी जी बोलती हैं तो हम अपने नाक, कान और आँखे खोलकर पूरे आदर और सम्मान के साथ उनको सुनते हैं । माननीय सदस्या कांग्रेस विधायक दल की नेता और हरियाणा विधान सभा की वरिष्ठ सदस्या हैं । अतः इनको हमारी बात को भी शांति से सुनना चाहिए । हरियाणा का 46,212 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है । आज हरियाणा में कोई 20 किलोमीटर का भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कोई महाविद्यालय न हो । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : करण सिंह दलाल, अभी तो हमने बहन किरण को बैठाया था । अब तू खड़ा हो गया । मेरा कहना है कि रिकॉर्ड के मुताबिक 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना में हमारी सरकार की बहुत अच्छी प्रफौरमैंस है । यह तो समय का आवागमन है । इनको किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए । हम तो कभी गलतफहमी में रहते ही नहीं हैं । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर.) की जो रिपोर्ट है उसमें प्रदेश के हाल का अच्छी तरह से बखान किया गया है । अतः इनको उस पर भी बोलना चाहिए ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय बहन किरण जी का दिल्ली के साथ जो प्यार है वह अभी भी बना हुआ है । ये दिल्ली के एडीशन का हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार पढ़ती हैं । आदरणीय बहन, आप दैनिक ट्रिब्यून पढ़ा करो । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं दिल्ली के अखबार पढ़ती हूं तो मैं इतना माद्दा भी रखती हूं कि मुझे मालूम है कि हरियाणा में क्या–क्या हो रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बेरी में भी एक महिला महाविद्यालय खुलना था । अतः माननीय मंत्री जी उस महाविद्यालय को भी इन्हीं महाविद्यालयों में एड करके घोषणा कर दें ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे बड़े भाई डॉ. रघुवीर सिंह कादियान ने असैम्बली में 2 दिन पहले मुझसे बेरी में महाविद्यालय खोलने के लिए कहा था । माननीय सदस्य डॉ. रघुवीर सिंह कादियान का गांव दूबलधन है । यह गांव बेरी से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है । दुजाना–बेरी गांव तो बोलने में एक ही गांव हैं । यह केवल 2 किलोमीटर दूर है और यहां पर एक महाविद्यालय है । फिर भी हम पंडित भगवतदयाल जी की स्मृति में बेरी में एक महिला महाविद्यालय जरूर खोलेंगे ।

सरदार बख्शीश सिंह विर्क : अध्यक्ष महोदय, असंध में 12.4.2014 को एक कॉलेज का शाम के 4 बजे उद्घाटन किया गया था । अगले दिन सुबह जब मैं वहां से सैर करने गया तो वहां पर उसका उद्घाटन पत्थर ही गायब था । अब हम वहां पर 17 करोड़ रुपये की लागत से बाबा फतेह सिंह के नाम से एक कॉलेज खोलेंगे ।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय बहन गीता भुक्कल जी कह रही थी कि हमने अम्बाला शहर में एक कॉलेज खोला था । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अम्बाला शहर में बारहवीं का एक गर्ल्स सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल है । मुझे वहां पर एक फंक्शन में बुलाया गया था । जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि वहां पर 2 कमरों में कॉलेज की क्लासिज चल रही थी । उन्होंने कहा कि आप हमारे स्कूल/कॉलेज का हाल देखिये न तो यह पूरी तरह से स्कूल रहा और न यह पूरी तरह से कॉलेज रहा । इसके बाद मैंने उनसे कहा कि अब मैं यहां पर तभी आऊँगा जब इस कॉलेज के लिए एक अलग बिल्डिंग मन्जूर करवा दूंगा । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवादी हूं कि

सरकार द्वारा प्रदेश के 22 के 22 जिलों में एक– एक कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया। सरकार ने हर जिले में एक कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा नारायणगढ़ में कॉलेज खोला गया और मेरे हल्के में कॉलेज फिर पैंडिग रह गया था परन्तु जब मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस बारे में बताया तो उन्होंने अलग से कॉलेज खोलने के लिए मंजूरी दे दी। आज के दिन संबंधित कॉलेज की बिल्डिंग 12 करोड़ रुपये की लागत से बन रही है। कांग्रेस पार्टी की माननीय सदस्या को सिर्फ कागजों का ध्यान आ गया है कि उन्होंने अंबाला सिटी में कॉलेज खोला था परन्तु मेरे अंबाला सिटी में कोई कॉलेज नहीं खोला गया। यह रिकॉर्ड की बात है। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के में बस स्टैंड बनाने की बात आती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रदेश में चुनावों के कारण आचार संहिता लगने से पहले बस स्टैंड बनाने के नाम पर एक पत्थर रख दिया और उस समय कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके थे। अंबाला सिटी में बस स्टैंड बनाने की मांग काफी समय से चली आ रही थी। यह बात जीवन में पहली बार हुई कि कोई व्यक्ति एक नया प्लॉट खरीद ले और उसके ऊपर घर बनाये बिना अपने पुराने वाले मकान को गिरा दे। यह अंबाला में पहली बार हुआ कि बस स्टैंड के लिए जमीन एक्वायर की गयी और उसके एक्वीजिशन के प्रौसीजर को फॉलो नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा पुराना बस स्टैंड गिरा दिया गया क्योंकि वे उस स्थान पर एक मॉल बनाना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बस स्टैंड वाली जगह पर तत्कालीन डी.सी. डॉ0 साकेत कुमार से पत्थर लगवाकर बस स्टैंड का शिलान्यास करवा दिया परन्तु बस स्टैंड बनाने के लिए न तो प्रपोजल बनाया गया, न ही कोई ड्राइंग बनायी गयी, न ही कोई डी.एन.आई.टी. बनायी गयी और न ही एस्टीमेट बनाया गया। यह पहली ऐसी सरकार थी जिसने सिर्फ घोषणाएं करके पत्थर लगवाये परन्तु धरातल पर काम कोई नहीं किया। अध्यक्ष जी, प्रदेश में बिजली देने की बात आती है। हमारी सरकार ने 3205 गांवों को पहली बार 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। अगर मैं पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्ट्री की बात करूं तो पहले गांवों की सड़कें 12 फुट से कम चौड़ाई की होती थी।

.....

हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन व सदस्यों का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, आज हमारे भूतपूर्व मंत्री श्री विनोद शर्मा, जस्टिस श्री एस.एन. अग्रवाल, चेयरमैन हरियाणा बैकवर्ड क्लॉसिज कमीशन, श्री रमेश चन्द, माननीय सदस्य हरियाणा बैकवर्ड क्लॉसिज कमीशन, श्रीमती ऋतम्भरा संघी, माननीय सदस्य, हरियाणा बैकवर्ड क्लॉसिज कमीशन और श्री अशोक कुमार, माननीय सदस्य, हरियाणा बैकवर्ड क्लॉसिज कमीशन सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं।

.....

वर्ष 2019–20 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, पहले प्रदेश में सड़कों की चौड़ाई 12 फुट थी परन्तु हमारी सरकार ने सड़कों की चौड़ाई 18 फुट करवायी है। हमारी सरकार ने पहली बार स्वतः ही संज्ञान लेकर इन 12 फुट की सड़को को 18 फुट चौड़ा किया ताकि यातायात में सुगमता हो। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदसीन हुई।)** उपाध्यक्ष महोदया, पहली बार हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में एयर पोर्ट बनाया है। अभी यह डोमैस्टिक एयर पोर्ट है। इस एयर पोर्ट के अगले फेज में हवाई जहाजों के रख –रखाव, मरम्मत का काम, ओवर हॉलिग, पॉर्किग और हवाई पट्टी को 4,000 फुट से बढ़ाकर 10,000 फुट करके विस्तार किया जाएगा। हिसार जिला आगे आने वाले समय में दिल्ली का एक अल्टरनेट बनेगा और भगवान ने चाहा तो अगली बार यहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट बनाकर विस्तार किया जाएगा। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र की बात करूं तो हमारी सरकार ने फॉर्मा और टैक्सटाईल को लेकर एक नयी पॉलिसी बनायी है। लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग के लिए एक नयी योजना बनायी गयी है और अंबाला सिटी लॉजिस्टिक और टैक्सटाईल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक सबसे ज्यादा नैचुरल स्थान है। अंबाला में लगभग 1500 कपड़े की दुकानें हैं और इन दुकानों से लगभग 9,000 करोड़ रुपये का टर्न ओवर सरकार के पास आता है। इन दुकानों ने 12,000 से 14,000 अनस्किल्ड बच्चों को रोजगार दे रखा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री जी से अनुरोध है कि अंबाला में टैक्सटाईल से जुड़ा हुआ

12.00 बजे

कोई रिसर्च सैंटर खोला जाए ताकि बच्चे रिसर्च करके अंबाला को टैक्सटाईल हब के रूप में डिवैलप कर सकें। कुछ समय पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया कि जनसंख्या बढ़ने के कारण 2025 तक न तो दिल्ली के एयर पोर्ट पर स्थान रहेगा और ना ही रेलवे स्टेशन पर स्थान रहेगा और ना ही दिल्ली के बस स्टैंड पर स्थान रहेगा। दिल्ली आज ओवर पैक्ड हो चुकी है। हमारा अंबाला जिला दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होने के कारण दिल्ली का सब्स्टीच्यूट बन सकता है क्योंकि अंबाला जिला एक ही आई.सी. के ऊपर है। अमृतसर –कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के हिसाब से अंबाला स्थापित है और हाईवे से वैल कनैक्टिड है। अंबाला में रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है। चण्डीगढ़ का अतंर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट अंबाला से केवल 40 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है।उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से डिमांड करना चाहता हूं कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए टैक्सटाइल हब और लॉजिस्टिक हब बनाए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा का पूरे देश के अंदर तीसरा स्थान है और नॉर्थ इंडिया में पहला स्थान है। इसके साथ–ही–साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मोरनी के अंदर विश्व का पहला हर्बल पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और पतंजति पीठ के साथ एक एम.ओ.यू. भी साईन किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, यह विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनने जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारी आयुर्वेद्ध की जो पुरानी पद्धति है, उसमें बढ़ोत्तरी भी होगी। इस तरह से हमारी सरकार बजट के अंदर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लेकर आ रही है और मैं इसके लिए सरकार को साधुवाद देना चाहूंगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो पौधगिरी अभियान शुरू किया है, उसमें हर बच्चे को कहा गया है कि वे एक पौधा लगाएं और उसको बड़ा करें, ताकि ये पर्यावरण और हमारे लिए मित्र साबित हो। इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। जिस बच्चे का पौधा बड़ा होकर वृक्ष बनेगा और वह बच्चा जब तक उसको काटेगा, तब तक उसको कुछ न कुछ समय बाद प्रोत्साहन राशि मिलती रहेगी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, अगर मैं लॉ एण्ड आर्डर की बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सामने बैठे हुए साथी बहुत चिल्लाते हैं कि 'लॉ एण्ड आर्डर' खराब हो गया है। चलिए, यह ठीक बात है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे समय में 'लॉ एण्ड ऑर्डर' दूसरे तरीके से खराब हुआ है, लेकिन इनके समय में 'लॉ एण्ड ऑर्डर' का मतलब यह होता था कि 'पैसे लाओ और ऑर्डर ले जाओ'।

इन्होंने 'लॉ एण्ड ऑर्डर' का जो मतलब निकाल रखा था, वह यह था कि 'ला और ऑर्डर ले जा'। हमारी सरकार ने इनके मुताबिक उस 'लॉ एण्ड ऑर्डर' को खराब करने का काम किया। लेकिन हमारी सरकार ने जनता के मुताबिक इस 'लॉ एण्ड ऑर्डर' को ठीक करने का काम किया है।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं इनसे कहना चाहूंगी कि ये एक बार अच्छे से देख लें कि आखिर चार बार किसकी सरकार थी।

श्री असीम गोयलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या से पूछना चाहूंगा कि आखिर प्रदेश को किसने जलाया ? उपाध्यक्ष महोदया, आज चोर जो है, वह चौकीदार से सवाल कर रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः उपाध्यक्ष महोदया, मैं श्रीमती गीता भुक्कल जी से कहना चाहूंगा कि हरियाणा को जलाने वाले और लूटने वाले ये लोग हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः हरियाणा को जलाने वाले ये सारे लोग थे, जिन्होंने वोटों के लिए पूरे हरियाणा को जलाया था। (शोर एवं व्यवधान) यह पूरा प्रदेश जानता है कि हरियाणा को किसने जलाने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आदरणीय श्रीमती गीता भुक्कल जी से पूछना चाहता हूं कि जब इनका मकान जला था, उस समय सरकार ने कहा था कि हम इसकी सी.बी.आई. से इन्क्वायरी करवाएंगे, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये सी.बी.आई. इन्क्वायरी करवाने से पीछे क्यों भागीं ? (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः कृपया, आप सभी लोग अपनी–अपनी जगह पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदया, इन लोगों ने तो पूरे हरियाणा का नाश करके रख दिया था और पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः उपाध्यक्ष महोदया, इनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है। (शोर एवं व्यवधान) जब भी विकास की बात आती है तो ये सारे निरुत्तर हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः कृपया आप सभी लोग अपनी–अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या से पूछना चाहता हूं कि जब इनका मकान जला था, उस समय सरकार ने कहा था कि हम इसकी सी.बी.

आई. से इन्क्वायरी करवाएंगे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने सी.बी.आई. इन्क्वायरी क्यों नहीं करवाने दी?

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आज भी कह रही हूं कि सरकार इन सारे प्रकरण की सी.बी.आई. जांच करवा दे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने उस समय सी.बी.आई. जांच के लिए मना क्यों किया ? (शोर एवं व्यवधान) ये उस समय सी.बी.आई. जांच करवाने से क्यों भागीं ? (शोर एवं व्यवधान)

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं भी माननीय सदस्या से पूछना चाहूंगा कि ये उस समय सी.बी.आई. जांच क्यों नहीं करवाने दीं ? (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने सारे सबूत नष्ट कर दिए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या से पूछना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अगल–बगल में बैठने वाले जो लोग थे, वे कौन थे ? (शोर एवं व्यवधान) प्रोफेसर बिरेंद्र सिंह जी कौन थे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि ये सारे लोग चोर हैं और चौकीदार से सवाल पूछते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः कृपया, आप सभी लोग अपनी–अपनी सीट पर बैठ जाएं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमारे हर सवाल और हर मुद्दे पर ये लोग पिछली सरकार–पिछली सरकार का नाम ले रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं आज की वर्तमान सरकार से सवाल पूछ रही हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री विपुल गोयलः उपाध्यक्ष महोदया, हमने इनको कितनी बार बताया है, लेकिन चोर खुद चौकीदार से सवाल कर रहा है। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा को जलाने वाले यहां सवाल कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः डिप्टी स्पीकर मैडम, हमारे सम्मानित मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी ने पिछली बार भी यह कहा था कि माननीय सदस्या का घर जिन लोगों ने जलाया है, वे उनकी तफ्तीश करवाना चाहते हैं। उस समय माननीय सदस्या से पूछा गया कि क्या आप उस इन्क्वायरी से खुश हैं और क्या उस इन्क्वायरी में

शामिल होना चाहती हैं, तो ये खुद उस समय मुकर गई थीं। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या से पूछना चाहता हूं कि ये यहां पर बताएं कि उस समय सी.बी.आई. इन्क्वायरी करवाने से मुकरी थी या नहीं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि ये तमीज से बात करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री विपुल गोयलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या से पूछना चाहता हूं कि हम तमीज से क्या बात करें। (शोर एवं व्यवधान) ये तो ऐसे कह रही हैं कि जैसे ये हमसे आप–आप कहकर बात करती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो खुद सरकार से कह रही हूं कि इस पूरे प्रकरण की सी.बी.आई. जांच करवाएं। (शोर एवं व्यवधान)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से कहना चाहूंगा कि एक–एक आदमी जानता है कि इनका घर किसने जलाया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवरः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या से बस यही पूछना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अगल–बगल में बैठने वाले जो लोग थे, वे कौन थे ? (शोर एवं व्यवधान) प्रोफेसर बिरेंद्र सिंह जी कौन थे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री विपुल गोयलः आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सदन में जब भी हरियाणा के विकास की कोई बात होती है और जब भी हरियाणा को आगे ले जाने की बात होती है तो ये अपनी की हुई गलती को हमारे ऊपर डालकर बचना चाहते हैं। इन्होंने हरियाणा को जलाने का काम किया है और इसके लिए हरियाणा की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। (विघ्न)

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी । हरियाणा को जलाने का काम इन लोगों ने किया और ये अपनी गलती हमारे ऊपर डालकर के बचना चाहते हैं। इन्होंने 10 बार सवाल किए और हमने इनके सवालों का 10 बार ही जवाब दिया है। इस बात का छः महीने बाद इन लोगों को पता लग जायेगा । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा प्रदेश की जनता को इस बात का पता है कि किसने हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया और इस

बात का किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, आग लगाने वाले कौन हैं, इस बात का भी पता है ।

उपाध्यक्ष महोदया : प्लीज, आप सभी सदस्यगण अपनी–अपनी सीट्स पर बैठिये । असीम जी, आप बजट पर बोलिये। (विघ्न)

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदया, इन्होंने इस प्रकरण को अपनी ढाल बना लिया है । (विघ्न) जब भी कोई बात होती है तो ये लोग उछल–उछल कर खड़े हो जाते हैं कि हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया । हरियाणा प्रदेश की जनता को इस बात का पता है कि किसने हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा प्रदेश को इन लोगों ने जलाने का काम किया है और इस बात का सभी को पता है । इन लोगों के एरिया में हरियाणा प्रदेश जला, जो ये लोग बार–बार खड़े हो रहे हैं । हमारे एरिया में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इसमें इन लोगों की ही जिम्मेदारी बनती है। एक सोची समझी राजनीति के तहत साजिश करके हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया । उपाध्यक्ष महोदया, इन लोगों को रोहतक की जनता ने मेयर चुनाव के नतीजों में बता दिया है । हुड्डा जी, आपको रोहतक की जनता ने आईना दिखाया है । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : प्लीज, आप सभी सदस्यगण अपनी–अपनी सीट्स पर बैठिये । असीम जी, आप बजट पर बोलिये। (विघ्न)

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदया, रोहतक की जनता ने इनका भ्रम तोड़ने का काम किया है । जींद जिले को भी इन लोगों ने जलाया था और वहां की जनता ने श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को उपचुनाव में आईना दिखा दिया है । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : प्लीज, आप सभी सदस्य अपनी–अपनी सीट्स पर बैठ जाईये । आपको बजट पर बोलने का पूरा मौका दिया जायेगा । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, ये लोग आग लगवाकर पॉपुलर होने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को हरियाणा प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। इन लोगों को न तो जनता माफ करेगी और न ही कभी भूलेगी । (विघ्न) इन लोगों ने तो बेरी, रोहतक, कलानौर और झज्जर तक जला दिया । ये लोग न तो हरियाणा प्रदेश की जनता के हुए और न ही यहां के हुए । (विघ्न)

श्रीमती शकुन्तला खटक : उपाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि माननीय सदस्य श्री धनखड़ जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और इन लोगों को आने वाले चुनावों में पता लग जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदया : प्लीज, आप सभी सदस्यगण अपनी–अपनी सीट्स पर बैठिये । असीम जी, आप बजट पर बोलिये। (विघ्न)

श्री महीपाल ढांडा : उपाध्यक्ष महोदया, आने वाले समय में बहन शकुन्तला जी की बात इन्हीं पर ही लागू होने वाली है । बहन जी ने माटी की किस्म बताई थी कि खराब माटी, बीरान माटी और रेरे माटी । उपाध्यक्ष महोदया, मैं बहन जी से कहना चाहूंगा कि आने वाले चुनावों में हरियाणा प्रदेश की जनता इन लोगों की रेरे माटी करेगी । (विघ्न)

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे ख्याल से इन लोगों का चाव अभी तक उतरा नहीं है । इन्होंने अभी तक छह चुनाव देख लिए हैं और ये लोग अभी भी कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, इन लोगों को जनता ने छह चुनावों में जवाब देकर तमाचा मार तो दिया है और इनको कितना बड़ा तमाचा चाहिए । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, लोकसभा के चुनाव आने वाले है और हरियाणा प्रदेश में लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव होगा और उसके बाद विधान सभा की 90 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं । मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप ये चिंता करो कि इन सीटों पर जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी ? उपाध्यक्ष महोदया, ये लोग हल्ला इसलिए कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश की जनता हल्ला करते हुए इनको देख ले तो शायद विधान सभा में फिर से आने का मौका मिल जाये । मैं समझता हूं कि इनमें से आधे से भी कम लोग इन सीटों पर बैठ पायेंगे । (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, बजट पर इतनी अच्छी बहस हो रही है । यहां सदन में सभी वरिष्ठ माननीय सदस्य बैठे हैं । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, माननीय विधायक श्री असीम गोयल जी बजट पर बोल रहे हैं तो इन लोगों को किस बात की चरमराहट है, इनको जो चरमराहट हो रही है, वह नहीं होनी चाहिए। जब माननीय सदस्य को बोलने का मौका दिया गया है तो पहले इनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, आप सभी कृपया करके बैठ जायें और हाउस की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्यगण, आप सभी कृपया बैठ जायें क्योंकि जो माननीय सदस्यगण बिना चेयर

की परमिशन के बोल रहे हैं उनकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) असीम गोयल जी, आप कंटीन्यू करें।

श्री असीम गोयल : आदणीय उपाध्यक्ष महोदया जी, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की एफ.आई.आर. भी दर्ज़ नहीं होती थी। (विघ्न) हमारी सरकार ने गुलाबी थाने खोले जिनका मुख्य उद्देश्य पूर्ण रूप से महिलाओं का संरक्षण करना है। ये मेरा प्वायंट है महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बंधित मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूं। हमारी सरकार ने पहली बार बहन–बेटियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए प्रदेश भर में गुलाबी थानों की स्थापना की। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : असीम जी, आप कृपया करके कंक्लूड करें।

श्री असीम गोयल : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं यह बता रहा हूं कि हमारी सरकार द्वारा पहली बार महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से थाने खोलने का काम किया गया। (विघ्न) आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया जी, हमारी सरकार का यह पांचवा साल चल रहा है। हमारी सरकार के इस कार्यकाल का यह अंतिम बजट सत्र है। विधान सभा में सबसे अच्छे विधायक का पुरस्कार देने की बात कही गई थी। इस सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही तो नहीं हो पाई लेकिन मेरा आपको यह सुझाव है कि यहां पर सबसे नालायक विधायक का पुरस्कार देना शुरू किया जाना चाहिए और वह पुरस्कार कांग्रेस पार्टी के उन सम्मानित सदस्यों को दिया जाना चाहिए जो सबसे ज्यादा हाउस की कार्यवाही को डिस्टर्ब करते हैं। उपाध्यक्ष महोदया जी, भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा एक बहुत बड़ा सामाजिक आन्दोलन चलाया गया जिसके तहत पूरे देश से 100 ऐसे जिलों को चुना गया जिनके अंदर लिंगानुपात बहुत ही ज्यादा कम था। इन 100 जिलों में हरियाणा प्रदेश के भी 12 जिलों का नाम आया जोकि हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी, 2015 को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के इस अभियान की शुरूआत हरियाणा के पानीपत शहर से की। हरियाणा प्रदेश के जिन जिलों में जो आंकड़ा कभी 830 प्रति 1000 हुआ करता था आज वह आंकड़ा 914 प्रति 1000 हो गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की रही है। इससे भी बढ़कर 55000 युवक–युवतियों को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से 17000 भर्तियों की प्रक्रिया अभी चल रही है और लगभग 5500

भर्तियों का मामला माननीय कोर्ट में विचाराधीन है। उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा में ऐसी पहली सरकार है जिसके बारे में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा था कि जिस हरियाणा में एक बिजली का खम्बा भी बिना पैसे दिये नहीं लगता था और आपने एस.डी.एम. भी बिना पैसे दिये लगाने का काम किया है। न ही तो किसी से चैक लिया गया और न ही किसी को जैक की जरूरत पड़ी और बिना पैसे और सिफारिश के पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी गई हैं। पिछली सरकार में नौकरियां बेची जाती थी और बसों में दलाल जेबों में पर्चियां लेकर घूमते थे। पिछली सरकार के समय में नौकरियां बिकती थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहती हूं कि वर्तमान सरकार ने बिजली का एक भी नया उपक्रम नहीं लगाया है और अडानी से महंगी बिजली खरीदी जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा पहला राज्य है जिसने घरेलू बिजली की दरों में कटौती करके अपने नागरिकों को सुविधा देने का काम किया है। यह पहली सरकार है जिसमें 3205 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हमारी सरकार ने पहली बार हरियाणा में बिजली के बिल निपटान की योजना बनाई है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। धनवन्तरी जी के बाद हकीम लुकमान को शायद सबसे बड़े वैध होने का दर्जा प्राप्त है। मैं लुकमान के बाल्यकाल का एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। उनका बाल्यकाल बड़ी गरीबी में गुजरा। वे किसी के यहां नौकरी करते थे। एक दिन उनके मालिक ने उनसे कहा कि लुकमान मुझे मेमने के शरीर के दो सबसे सुन्दर और स्वादिष्ट हिस्से पका कर खिलाओ। लुकमान ने मेमने का दिल और दिमाग पका कर अपने मालिक को दे दिया। 15 दिन बाद उस मालिक ने फिर कहा कि लुकमान मुझे मेमने के शरीर के दो सबसे बदसूरत हिस्से पका कर खिलाओ। लुकमान ने उन बदसूरत हिस्सों के रुप में फिर मेमने का दिल और दिमाग पका कर खिलाया। मालिक को बहुत अचम्भा हुआ और उन्होंने कहा कि लुकमान शायद तुम्हारा नौकरी में मन नहीं लगता है। मैंने 15 दिन पहले जब मेमने के स्वादिष्ट हिस्से पूछे थे तो भी मेमने का दिल और दिमाग पका कर खिलाया और जब बदसूरत हिस्से पूछे तब भी तुमने मेमने का दिल और दिमाग पका कर खिलाया है। तब लुकमान ने कहा कि जिस दिल और दिमाग के अन्दर दूसरों की भलाई करने

की सोच है, जिस दिल और दिमाग के अन्दर अपने देश से प्रेम है, जिस दिल और दिमाग के अन्दर दूसरों के लिए प्यार है, ममता है वह दिल और दिमाग इस शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जिसमें बुराई है, ईर्ष्या है वह दिल और दिमाग इस शरीर का सबसे बदसूरत हिस्सा है। अब हरियाणा की जनता ने खूबसूरत हिस्से को यहां बैठा रखा है और बदसूरत हिस्सा जहां बैठा है वह आपके सामने है। बजट में कितनी बार इन लोगों ने हरियाणा के साथ वर्षों वर्ष धोखा किया है। मैं इस बजट का अनुमोदन करते हुये आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, आदरणीय वित्त मंत्री कप्तान अभिमन्यु जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः के नाते उन्होंने जो बजट बना कर पेश किया है, हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात को चरितार्थ किया उसके लिए मैं उनकी बहुत भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, अब डॉ. अभय सिंह यादव जी बजट पर अपनी बात रखेंगे।

डॉ. अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, ऐसा नहीं होता कि सत्ता पक्ष की तरफ से दो–दो विधायक बोलेंगे । यह कोई तरीका नहीं है । आप विपक्ष को बोलने का समय दीजिए । ऐसा करके आप सदन की परम्परा को तोड़ रही हैं । अभी तक तो विपक्ष के नेता भी नहीं बोले हैं । आप यह गलत परम्परा डाल रही हैं । यह हर तरीके से गलत परम्परा डाली जा रही है । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : किरण जी, प्लीज आप बैठिए । मैंने दो सदस्य विपक्ष के भी बुलवाए हैं । इनके बाद आप को भी बुलवाएंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढ़ांडा : उपाध्यक्ष महोदया, आप इनसे पूछिये कि क्या इनके समय में कोई गलत परम्परा नहीं थी । माननीय सदस्या हमें परम्परा मत सिखाएं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, अब तक सदन की यह परम्परा रही है कि गवर्नर ऐड्रस के ऊपर पहले दो ट्रैजरी बैंच वाले बोलेंगे । बजट के ऊपर हमेशा विपक्ष शुरूआत करता है । अब यह गलत परम्परा डाली जा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि यह गलत परम्परा डाली जा रही है । यह परम्परा का निर्वहन नहीं

है । बजट पर चर्चा विपक्ष शुरू करता है । आपका बजट पत्र आया है आपने तो उस पर बुलवाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदया : परमेन्द्र जी, हमने आपकी बात को मान लिया है लेकिन अब अभय सिंह यादव जी बोलने के लिए खड़े हो गए हैं तो उनको बोल लेने दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

Smt. Kiran Choudhry: Deputy Speaker Madam, you are setting a wrong precedent in the Assembly and this should not be done. It is totally wrong precedent. You must keep up the precedent.

श्री अभय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप मुझे बोलने की इजाजत दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : मैडम, आप पहले विपक्ष को बुलवाइये ।(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : मैडम, इसके बाद हम विपक्ष से दो–दो सदस्यों को बुलवा देंगे । हम विपक्ष को बोलने का पूरा समय देते हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, हमारे बीच पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हैं वह बहुत ही सीनियर मैंबर हैं । ये 5–6 बार विधान सभा के सदस्य रहे हैं । इन्होंने बहुत सारे सैशन देखे हैं । इन्होंने बहुत सारी सरकारों के अन्दर बजट की चर्चाओं में भाग लिया है । मंत्री जी, आप बता दें कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है उसके बाद जब उस पर चर्चा की शुरूआत की जाती है तो वह पक्ष से शुरू होती है ? बजट पर चर्चा तो हमेशा ही विपक्ष की तरफ से की जाती है । आप यहां विपक्ष की तरफ से चर्चा शुरू करवाने की बजाए पक्ष की तरफ से शुरू करवा रहे हैं । इसका मतलब यह तो नहीं है कि आपकी सरकार बहुमत में है तो आप विधान सभा की परम्परा को ही तोड़ दोगे । यह तो गलत परम्परा है । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : अभय सिंह जी, उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार पिछले तीन सालों से लगातार बजट पर पक्ष के सदस्य ही बोलते आ रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, एक सरकार जब बजट पेश करती है तो सरकार का कोई न कोई विधायक उस पर बहस का प्रारम्भ करता है । अभय सिंह जी की यह बात ठीक है कि उसके बाद विपक्ष उसका अनुमोदन करता है । चौधरी अभय सिंह जी विपक्ष के नेता उस समय सदन में उपस्थित नहीं

थे । विपक्ष को और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को अनुपातिक हिसाब से बोलने का पूरा समय मिलेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात को ठीक करना चाहूंगा । (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी कह रहे हैं कि उस समय मैं सदन में उपस्थित नहीं था । उपाध्यक्ष महोदया, आपसे पहले जब अध्यक्ष महोदय, बैठे थे उनको भी सभी ने यह बात कही थी । (शोर एवं व्यवधान) मैंने उनको भी कहा था ।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, यह आपकी कुर्सी की मर्यादा का सवाल है । इस सदन की मर्यादा का सवाल है इसलिए जो परम्परा है आप उसको टूटने मत दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः देखिए हमने तो विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया है। यह मेरे पास रिकार्ड है जिसको देखने से साफ पता चलता है कि पिछले दो साल से सदन में पक्ष और विपक्ष के दो–दो सदस्यों को बजट पर बोलने के लिए समय दिया जाता है और आज भी सदन में इसी आधार पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा रहा है। हम सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजीशन को ही बुलवाना चाहते थे लेकिन अभय जी आप सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए आपको यह मौका नहीं मिल सका। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, बात रिकॉर्ड की नहीं है बल्कि बात तो सदन की परंपराओं को बनाये रखने की है। क्या परंपराओं को तोड़ने की सारी ठेकेदारी सरकार की ही है। सदन की परंपराओं को बनाये रखना चेयर का काम होता है और सदन में बजट पर बोलने का मुझे पहले मौका न देकर एक तरह से चेयर की तरफ से सदन की परंपराओं को तोड़ने का काम किया गया। मैं सदन में उपस्थित था चलो आपकी बात मान लेते हैं मैं नहीं था तो आपको श्रीमती किरण चौधरी जी को बजट पर बोलने के लिए समय देना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, सदन की जो भी परंपरायें होती है देश की सभी विधान सभाओं में इसको जनरली फोलो किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं भी दिल्ली विधान सभा में डिप्टी स्पीकर के पद पर आसीन रह चुकी हूँ। मुझे भी सदन की परंपराओं का ज्ञान है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, आज सदन में जब परंपराओं को तोड़ा जा रहा था तो इस सदन के बहुत ही सीनियर सदस्य, संसदीय कार्य मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी भी उस परंपरा को तोड़ने में शामिल हुए हैं।(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः अभय जी, सदन में अगर कोई बात बार–बार होती रहे तो वही बात आगे चलकर परंपरा बन जाती है और यही नहीं प्रैक्टिस से भी परंपरायें विकसित होती रहती हैं। पिछले दो–तीन साल से जिस तरह की प्रैक्टिस चल रही थी, हमने उसको ही आज भी एडॉप्ट करने का एक प्रयत्न किया था? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, प्रेसीडेंट बहुत इंपोर्टेंट होते हैं क्योंकि यह सदन के संचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Precedents are treated as law. Precedents are as important as law.

उपाध्यक्ष महोदयाः ठीक है अभय जी, अब आप अपनी बात रखें।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद): उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया और इस बात के लिए बधाई भी देता हूँ कि जिस प्रकार सदन की परंपराओं को आज तोड़ने का काम किया जा रहा था, मुझे बोलने का मौका देकर आपने उन परंपराओं को बनाये रखने का भी काम किया है। कल वित्त मंत्री महोदय ने बजट प्रस्तुत किया था और जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो उससे पहले झोले की बात चली और झोले की बात किसी और ने नहीं कही बल्कि पार्लियामेंट अफेयर्ज मिनिस्टर ने की थी कि हम तो झोला लेकर आए हैं और इस झोले में वे सारी सुविधायें हैं जिससे हरियाणा प्रदेश की जनता को आगे बहुत सारी सुविधायें मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदया, इस चार–सवा चार के कार्यकाल के दौरान जितने भी बजट प्रस्तुत किए गए है उन सबमें केवल आंकड़े दर्शाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है और हमेशा अलग–अलग डिपार्टमैंट के लिए जहां बढ़ोतरी करने का काम किया जाना चाहिए था, वहां कटौती करके लोगों के सामने और दिक्कत और कठिनाई पैदा करने का काम किया गया है। कल के भी दो घंटे बजट के भाषण में केवल आंकड़ों को तोड़–मरोड़कर प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि किस किस डिपार्टमैंट में कितनी–कितनी बढ़ोतरी की गई है तथा किस–किस मद में कितना–कितना पैसा दिया गया है और बजट को किसान हितेषी दिखाते हुए बजट में 1500 करोड़ रुपये अलग से प्रावधान करके यह दिखाने का प्रयास भी किया गया कि आने वाले समय

में इस 1500 करोड रुपये की राशि को एक योजना के तहत किसान के हितों के लिए खर्च किया जा सकेगा। योजना तो बनी नहीं और 1500 करोड़ रुपये किसानों के लिए बजट में प्रावधान कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूँगा कि तेलंगाना राज्य ने अपने किसानों को 4 हजार रुपये प्रति फसल के हिसाब से यानी एक एकड़ में किसानों की अपनी दो फसलों के 8 हजार रुपये उनके खाते में डाल दिए हैं। किसानों को अपनी फसल की बिजाई और उगाई में कोई समस्या न आए और उनकी दशा को और ज्यादा सुधारने के लिए इन पैसों को 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये अर्थात् एक एकड़ के हिसाब से 10 हजार रुपये किसानों के खाते में डालने जा रही है। हरियाणा सरकार ने जो 15 सौ करोड़ रुपये इस तरह से किसानों के लिए बजट में रखा है, यह सारा का सारा पैसा तेलंगाना राज्य की तर्ज पर किसानों के खाते में जमा करवाना चाहिए ताकि किसानों को अपनी फसल की बिजाई और उगाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत पेश न आए। बजट में जो अनुमान होते हैं उनका वर्षवार और कुल कर्ज की राशि का ब्यौरा पहली बार हरियाणा के इतिहास में नहीं दिया गया है। यह पहली बार हुआ है कि सरकार ने बजट में अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए एक तरह का नायाब तरीका निकाला है। अतीत में बजट में कर्ज की राशि का ब्यौरा दिया जाता था। भाजपा के कार्यकाल के दौरान हरियाणा प्रदेश के इतिहास में अपने बजट अनुमानों में न तो वर्षवार और न ही कुल कर्ज की राशि का ब्यौरा दिया गया है। यह नही बताया गया कुल कितने कर्ज प्रदेश ने लिया हुआ है और कितना कर्जा हमने दोबारा से पे करने का काम किया हुआ है? कृषि के क्षेत्र में बजट की भागीदारी पहले से कम हुई है। वर्ष 2016–17 में कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 13.71 प्रतिशत खर्च करने की बात बजट में रखी गई थी। उसके बाद वर्ष 2017–18 में कृषि के लिए बजट में 12.49 प्रतिशत खर्च करने की बात रखी गई थी। उसके बाद वर्ष 2018–19 में कृषि का बजट फिर कम करते हुए 12.22 प्रतिशत कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अब जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके लिए बहुत देर तक सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई थी और यह कहा गया था कि यह सरकार कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुपये खर्च करेगी। जिससे किसानों को बहुत सारा फायदा पहुँचेगा। अध्यक्ष महोदय, अबकी बार भी कृषि के बजट को कम करके केवल 10.31 प्रतिशत कर दिया गया है। यह आंकड़े मैं अपनी

तरफ से नहीं कह रहा हूँ बल्कि सरकार की तरफ से दिए हुए आंकड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बिजली के क्षेत्र में यही कहा गया है कि बहुत सारे गांवों में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर दी गई है। बहुत सारे नये ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं और बहुत सारे नये सब–स्टेशन बना दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक घोषणा कर दी है कि हम 90 हजार नये ट्यूबवैल के कनैक्शन देंगे। इससे बहुत से किसानों को फायदा होगा। अगर ये सारी चीजें सरकार ने करनी है तो सौ फीसदी बजट में भी इसकी बढ़ौत्तरी करनी चाहिए थी। बिजली के क्षेत्र में जो सब्सिडी किसानों को दी जाती है उसमें दखेंगे कि वर्ष 2016 में टोटल सब्सिडी 10.76 प्रतिशत थी । वर्ष 2017–18 में बिजली पर सब्सिडी 6.31 प्रतिशत थी । वर्ष 2018–19 में 5.87 परसैंट थी । इसको वर्ष 2019–20 में 4.63 परसैंट कर दिया गया । बिजली विभाग के टोटल बजट में भी कमी कर दी गई । मेरा कहना है कि अगर उसमें कमी करोगे तो फिर सुधारीकरण कैसे होगा ? इसी तरह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट है । वर्ष 2016–17 में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट का बजट टोटल बजट का 6.28 परसैंट था । अगले वर्ष 2017–18 में उसको कम करके 6.23 परसैंट कर दिया गया । उसके बाद 2018–19 में उसको फिर कम करके 5.87 परसैंट कर दिया गया । अब की बार उसको और कम करके 4.12 परसैंट कर दिया गया । अगर इसी तरह से इसमें लगातार कमी होती रहेगी तो लोगों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के माध्यम से मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं कहां से मिलेंगी और रोडवेज में बसों का नया बेड़ा कहाँ से आएगा ? आप यह सौ फीसदी मानकर चलिए कि पिछले दिनों जब हमारे रोडवेज के कर्मचारी लगातार स्ट्राइक पर थे, लगातार सरकार से मांग कर रहे थे, लगातार सरकार के साथ–साथ बातचीज के जरिये समाधान चाहते थे और सरकार ने उन पर 'एस्मा' लगाकर, टर्मिनेशन के नोटिस देकर, उनको जेलों में डालकर दबाने का प्रयास किया और उनकी स्ट्राइक को कुचलने की कोशिश की थी । इससे साफ होता है कि आपकी नीयत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट को बढ़ाने की बजाय उसको कम करने की है । सरकार उसको पूर्ण रूप से प्राइवेट लोगों के हाथों में देना चाहती है ताकि हरियाणा का जो कर्मचारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट में काम कर रहा है वह घर बैठ जाए और सरकार के चहेतों को परमिट मिल जाए तथा उनका कारोबार खड़ा हो जाए । इस तरह से सरकार कर्मचारियों की बजाय अपने चहेतों की तरफ ध्यान दे रही है । अब मैं पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के विषय पर कहना चाहूंगा कि यह विभाग जनता के लिए सीवरेज

डालने, स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने, साफ–सफाई का ख्याल रखने आदि का काम करता है । इसको ज्यादा पैसा देना चाहिए था क्योंकि आबादी लगातार बढ़ रही है और उसके साथ–साथ जो बाकी छोटे–छोटे कस्बे थे वे आज शहर का स्वरूप ले रहे हैं । अतः वहां पर भी सीवरेज पाइप डालने आदि की आवश्यकता होगी । इसके अलावा इस सरकार की पोलिसी है कि जिस गांव की आबादी 15 हजार से ज्यादा है वहां के लिए भी सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाया जाएगा । सरकार इस तरह से वहां के लोगों को सुविधा देने का काम करेगी । पब्लिक हैल्थ का काम है कि नये वॉटर वर्क्स स्थापित करे । अगर उसे नये वॉटर वर्क्स बनाने पड़ेंगे तो उसके लिए विभाग को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी । अतः सरकार को इस विभाग के लिए बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए थी लेकिन सरकार ने इसके बजट में कमी की है । वर्ष 2016–17 में पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को बजट का 3.16 परसैंट शेयर मिला था । इसके बाद अगले वर्ष 2017–18 में इसको थोड़ा–सा बढ़ाया गया था और 3.31 परसैंट कर दिया गया । इस तरह से एक वर्ष में बढ़ोतरी की गई थी । पहले वर्ष में बजट कम था और अगले वर्ष में इसको बढ़ा दिया गया था लेकिन उससे अगले वर्ष 2018–19 में फिर इसको कम कर दिया गया । इसको .11 प्रतिशत घटाकर 3.20 प्रतिशत कर दिया गया । अब की बार और भी ज्यादा कटौती की गई है जबकि आबादी के हिसाब से इसके लिए बजट में राशि बढ़ानी चाहिए थी । इसको कम करके 2.71 प्रतिशत कर दिया गया । अब मैं ग्रामीण विकास क्षेत्र में पैसे के खर्च के बारे में कहना चाहूंगा कि आज मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी कि अलग–अलग आबादी के हिसाब से गांवों में सरकार द्वारा पैसा दिया जाएगा । इस पैसे से गांवों की पंचायतों की डिवैल्पमैंट होगी और लोगों की सुख–सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा । उसके लिए 1 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये की राशि देने की बात कही गई थी । इसके लिए सरकार को टोटल बजट में इस विभाग के शेयर में बढ़ोतरी करनी चाहिए थी । अगर आपने गांवों की पंचायतों को इतना पैसा देना है तो इसके लिए आपको विभाग के बजट में सौ फीसदी वृद्धि करनी चाहिए थी । बढ़े हुए बजट से ही गांवों में पैसा पहुंच पाएगा । सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 में 4.80 प्रतिशत पैसा ग्राम विकास में खर्च किया गया था परन्तु सरकार ने वर्ष 2018–19 के बजट में पैसों को कम करके 3.76 प्रतिशत कर दिया। अबकी बार सरकार ने इस बजट में थोड़ी सी बढ़ोत्तरी करके 3.83 प्रतिशत किया है। सरकार इस मामूली सी बढ़ोत्तरी से 10 हजार की आबादी वाले गांवों को

विकास के लिए 1 करोड़ रुपये देने की बात कर रही है और 10,000 की आबादी से ऊपर वाले गांवों के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये देने की बात कर रही है। यह पैसा कहां से आएगा क्योंकि पैसा नहीं होगा तो गांवों का डिवैलपमैंट कैसे होगा ? आजकल तो गांवों में डिवैलपमैंट सिर्फ एक ही चीज की हो रही है फिर उसमें चाहे गांव हों या शहर हों, उनमें पुरानी गलियों को उखाड़कर इन्टर लॉकिंग की नयी गलियां बनायी जा रही हैं। जबकि इन सभी गलियों को उखाड़ने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा पहले जो सीमेंटिड गलियां बनायी गयी थी, उनको भी उखाड़कर नयी इन्टर लॉकिंग की सड़कें बनायी गयी हैं। ये जो इन्टर लॉकिंग सड़कें बनायी जा रही हैं इससे सबसे ज्यादा नुकसान व्हीकल्ज को होता है क्योंकि जो व्हीकल्ज उन सड़कों से गुजरता है तो वे टाइल्ज व्हीकल्ज के टायरों को नुक्सान पहुंचाती हैं। आम लोगों की शिकायत है कि टाइल्ज की सड़कों की वजह से उनके व्हीकल्ज के टायर खराब हो जाते हैं और टाइल्ज पर चलते समय गाड़ी बबल भी करती है जिसकी वजह से गाड़ी को नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त टाइल्ज के रेट्स में भी डिफरैंसिज हैं। फैक्ट्री में से कोई प्राईवेट व्यक्ति टाइल्ज खरीदता है और उन्हीं टाइल्ज को विभाग खरीदता है तो उनके रेट्स में डिफरैंस होता है। एक टाइल 7 रुपये में मिलती है परन्तु सरकार 14 रुपये प्रति टाइल के रेट्स के हिसाब से टाइल्ज खरीद गली/सड़कों का निर्माण करवाती है। ईवन शहरों में तो टाइल्ज के रेट्स 20 रुपये के हिसाब से फिक्स किये गये हैं जबकि ये टाइल्ज 7 रुपये में मिलती हैं, इस प्रकार से यह 13 रुपये का डिफरैंस कहां पर जा रहा है ? इसके लिए सरकार को पता करना चाहिए कि इस डिफरैंस को कौन ले रहा है ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि जब जी.पी.डी.पी. (ग्राम पंचायत डिवलैपमैंट प्लान) के तहत कोई सड़क बन जाती है तो उसके बाद कोई भी बनी हुई गली को दोबारा से नहीं बनवा सकता। विभाग के पास हर गांव का एक नक्शा बनकर आ गया है जिसमें संबंधित गांव की फोटो भी होती है। उसी के हिसाब से गलियां बनायी जाती हैं। पहले जब जी.पी.डी.पी. नहीं बनी थी तो उन्ही गलियों को दोबारा से बनाने का काम होता रहता था। अब प्रत्येक गांव पर जी.पी. डी.पी. सिस्टम लागू है और हरेक गांव का मास्टर प्लॉन बनाया गया है जिसमें सभी गलियों का विवरण है। इससे यह पता चल जाएगा कि कौन–सी गलियां कच्ची हैं,

कौन–सी गलियां पक्की हैं और कौन–सी गलियां बनायी जानी हैं। इसलिए अब सरकार खेतों के रास्ते बनाने की तरफ ध्यान दे रही है। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी सरकार में रहे हैं तो उनको भी मालूम है कि ये रेट्स फिक्स करने का काम डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली कमेटी करती है। यह कमेटी इतनी स्ट्रिक्टली रेट्स फिक्स करती है कि कई बार तो हमारे पास शिकायतें भी आती हैं कि विभाग द्वारा जो रेट्स फिक्स किये गये हैं उन्हीं रेट्स पर सामान नहीं मिल रहा है जिसके कारण विकास कार्य रुक गये हैं। इसलिए कमेटी द्वारा जो रेट्स फिक्स गये हैं उनको ठीक करवा दें क्योंकि उन रेट्स पर टाइल्ज नहीं खरीद पा रहे हैं। वास्तव में गांवों के सरपंच हमारे विभाग के पास इस तरह की शिकायतें लेकर आते हैं। इसलिए रेट्स फिक्स करने का काम डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली कमेटी करती है और यह कमेटी हर 3 महीने में बैठक करके यह बात निर्धारित करती है कि पंचायत द्वारा जो काम किये जाने हैं वे संबंधित रेट्स पर सामान खरीद कर किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त विभाग बाकी काम टैंडर्ज द्वारा करता है और 20 लाख या उससे ऊपर के काम टैंडर्ज द्वारा किये जाते हैं। टैंडर्ज में कम्पीटीशन होता है। इस प्रकार से यह पूरा पारदर्शी सिस्टम है।

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा पारदर्शी सिस्टम की बात की जा रही है। सामान खरीदने के लिए डी.सी. द्वारा रेट्स फिक्स करने की बात कही जा रही है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत हैं कि डी.सीज. जो रेट फिक्स करते हैं, वह सही रेट्स फिक्स करते हैं ? मैं डी.सी. रेट्स का एक मामला माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाया था जिसमें सोनीपत जिले में नगर परिषद् का ऑफिस बनाया गया था। डी.सी. द्वारा सोनीपत में इस नगर परिष्द की बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए रेट्स फिक्स किये गये थे। अगर वह बिल्डिंग डी.सी. द्वारा फिक्स किये गये रेट्स के आधार पर सामान खरीदने की बजाय दूसरे रेट्स पर खरीदकर बनायी जाती तो सरकार को बहुत लाभ होता। इस समय मेरे पास बिल्डिंग से संबंधित दस्तावेज नहीं हैं क्योंकि मैंने वे दस्तावेज सरकार को दे दिये थे। इस बिल्डिंग में लगभग 5 करोड़ रुपये कंस्ट्रशन के लिए खर्च होने थे। डिप्टी कमिश्नर की रेट्स वाली लिस्ट को साइड में रख दिया गया और दिल्ली सरकार के रेट्स के ऊपर संबंधित बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवायी गयी जिसमें उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पर 12 करोड़ रुपये की लागत आयी। जबकि हरियाणा सरकार की तरफ से डी.सी. ने जो रेट्स फिक्स किये थे उन्हीं

रेट्स के अधार पर संबंधित बिल्डिग का कंस्ट्रक्शन करवाया जाना चाहिए था । उपाध्यक्ष महोदया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि यह जो 7 करोड़ रुपए का डिफरैंस है, जिसका सरकार को सीधा–सीधा चूना लगा है और मैं चाहता हूं कि इसकी जानकारी हाउस में आनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी जब अपनी बात रखें तो वे इसका भी जवाब दे दें।

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि चूंकि यह विषय बजट से संबंधित नहीं है तो मैं चाहता हूं कि अगर ऑनरेबल मिनिस्टर इसका जवाब अभी दे देंगी तो यह माननीय विपक्ष के नेता के लिए अच्छा होगा।

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मैंने इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगा था, लेकिन उसका जवाब अभी तब नहीं आया है।

कैप्टन अभिमन्युः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि इनके सवाल का जवाब माननीय मंत्री जी दे रही है और इसके साथ ही साथ इनकी समस्या का समाधान भी कर देंगी।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से यह जानना चाहूंगी कि नगर–परिषद को भंग हुए करीब 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है और यह मामला कौन–से सन् का है ? क्योंकि वर्तमान में नगर–निगम की बिल्डिंग का जो कार्य चल रहा है, वह कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहूंगी कि कृपया ये हमारी संज्ञान में ये बातें लेकर आएं, क्योंकि ये मेरे विभाग से संबंधित विषय है और अगर ये हमें दस्तावेज देंगे तो हम इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन्होंने दिल्ली का रेट क्यों लागू करवाया था ?

श्री कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि वहां पर नगर–परिषद तो है ही नहीं।

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर वह बिल्डिंग नगर–परिषद द्वारा नहीं बनाई गई थी तो आखिर किसके द्वारा बनाई गई थी, यह इनके विभाग का मामला है और इन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ?

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगी कि ये हमें दस्तावेज दे देंगे तो हम उसकी जांच करवा देंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैंने इससे संबंधित दस्वावेज माननीय मुख्यमंत्री जी को दिये थे, लेकिन उन दस्तावेज के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर माननीय मंत्री जी उस दस्तावेज की जांच करवाने के लिए कह रही हैं तो मैं इन्हें कल उस दस्तावेज की कॉपी उपलब्ध करवा दूंगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे पास इसी तरह से हैल्थ डिपार्टमैंट से संबंधित मामला भी है। सरकार की तरफ से वायदा किया गया था कि सरकार हर डिस्ट्रिक्ट हेड–क्वार्टर में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएगी। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि एम्स को लेकर दो दिनों तक पूरा विवाद चला था कि एम्स मनेठी में बने या अपनी पुरानी जगह पर ही रहे। मैं चाहता हूं कि नए हॉस्पिटल बने, नए एम्स खुले, उनके नए सैंटर बने, मेडिकल कॉलेज बने और प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल की सुख–सुविधा मिले, हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये सारी चीजें तब होंगी, जब सरकार हैल्थ विभाग में बजट का पैसा ज्यादा खर्च करेगी। आबादी के हिसाब से 100 फीसदी हमारे यहां डॉक्टरों, नर्सों और टैक्नीशियन्स की कमी है। इसके साथ ही साथ आज के समय में हमारे यहां पर जो एक्स–रे और सी.टी. स्कैन करने वाले डॉक्टर्ज हैं, उनकी भी भारी कमी है। सरकार की तरफ से नए–नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात बारी–बारी से कही गई थी, लेकिन अभी तक एक भी मेडिकल कॉलेज सरकार की तरफ से शुरू नहीं किया गया है और वर्तमान सरकार के चार वर्ष निकल भी गए हैं। इसके साथ ही साथ अलग–अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को मेडिकल की सुविधा देकर के इस बात के लिए भी सरकार अपनी पीठ थप–थपाने का काम करती है कि हमने यहां पर मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, वहां पर मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। इस मेडिकल कॉलेज के विषय को लेकर के श्री जाकिर हुसैन जी और श्री नसीम अहमद जी ने बहुत दफा इस विधान सभा में उठाया और बारी–बारी कहा कि मेवात का जो मेडिकल कॉलेज है, उसकी हालत बहुत खराब है और उस मेडिकल कॉलेज में जो आई.सी.यू. है, उसकी हालत जनरल वार्ड से भी ज्यादा बुरी है। उस मेडिकल कॉलेज के अंदर जो टायलेट्स हैं, उनमें जो सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह नहीं है। वह हॉस्पिटल नहीं, बल्कि एक तरह से नर्क के समान लगता है। इस विषय को हमारे माननीय सदस्य ने कई दफा मंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम किया था और अनुरोध किया था कि ये विधान सभा की तरफ से तीन–चार एम.एल.एज. की कोई टीम बनाएं, जो

वहां जाकर उस मेडिकल कॉलेज की हालत का जायजा ले और उसकी हालत में सुधार करने का काम करे। इसके साथ ही साथ हमारे माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि इसकी विजिलैंस इन्क्वायरी करवाई जाए, क्योंकि उस मेडिकल कॉलेज की कंस्ट्रक्शन गलत थी और उसमें जो इन्स्ट्रूमैंट्स लाकर लगाए गए थे, वे पुराने थे। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आई.सी.यू. वार्ड की हालत जनरल वार्ड से भी ज्यादा बुरी है तो हम यह मानकर चल सकते हैं कि इसका कोई इलाज हो ही नहीं सकता । अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग में भी जो पैसा बढ़ाना चाहिए था, बढ़ाने की बजाये घटा दिया गया । बजट वर्ष 2016–17 में 3.98 प्रतिशत था और वर्ष 2017–18 में कम करके 3.75 प्रतिशत कर दिया । उसके बाद वर्ष 2018–19 में 4.40 प्रतिशत यानी बजट बढ़ा दिया गया लेकिन इस बार बजट बढ़ाने की बजाये फिर 3.80 प्रतिशत कर दिया यानि घटा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अगर हम टोटल बजट में 3.80 प्रतिशत खर्च करेंगे तो सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता को 100 प्रतिशत नई सुविधाएं नहीं दे सकती है । जहां तक हैल्थ डिपार्टमेंट की बात है इस डिपार्टमेंट से रिलेटिड आज कितनी तरह की बीमारियां नये–नये स्वरूप में पैदा हो गई हैं जैसे स्वाइन फ्लू की बीमारी आ गई और कभी डेंगू जैसी बीमारी आ गई और कभी नये तरीके का फीवर आ गया। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में घग्घर नदी और यमुना नदी का पानी पलवल जिले, फरीदाबाद जिले में होडल विधान सभा क्षेत्र, मेवात जिले तक पहुंच कर रतिया विधान सभा क्षेत्र से होकर मेरे क्षेत्र के आखिरी गांव तक पानी पहुंचता है । अध्यक्ष महोदय, नदियों में बरसात के दिनों में बारिश का पानी आने के कारण जो नदियों में कैमिकल और जहरीला पानी खड़ा हुआ होता है वह बारिश के पानी की वजह से आगे की तरफ निकल जाता है । जब इस पानी से किसान अपने खेतों में सिंचाई करता है तो खेतों में पानी लगाने की वजह से उस किसान को भी खड़े–खड़े बीमारी हो जाती है । अध्यक्ष महोदय, किसान के खेत में पैदा होने वाली फसल में भी चाहे वह सब्जियां हों, चाहे गेंहू की फसल हों, चाहे बाजरे की फसल हों, चाहे धान की फसल हों, इन सभी फसलों में कैमिकल होने की वजह से बीमारियां बढ़ जाती हैं । अध्यक्ष महोदय, आज इसी वजह से हरियाणा प्रदेश में जहां हेपेटाइटिसा–बी और सी की बीमारियां रतिया विधान सभा क्षेत्र से लेकर सिरसा विधान सभा क्षेत्र के आखिरी छोर तक मिलेगी । अध्यक्ष महोदय, वहीं कैंसर के रोगियों की भी कमी नहीं है । बठिंडा से एक ट्रेन चलती है और उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन रखा गया है । उस ट्रेन में

जब कोई व्यक्ति सफर करने के लिए जाता है तो वह यह नहीं कहता है कि यह बठिंडा से जोधपुर जाने वाली ट्रेन है । वह यह कहता है कि कैंसर ट्रेन का टाईम इतने बजे है और इतने बजे स्टेशन पर आकर रुकेगी । अध्यक्ष महोदय, उस ट्रेन में मैक्सिमम कैंसर पेशेंट ही सफर करते हैं और कैंसर के पेशेंटों की संख्या जहां बढ़ रही है, हमारे यहां स्वाइन फ्लू और डेंगू जैसी बीमारियों की संख्या भी निरन्तर बढ़ती जा रही है । अध्यक्ष महोदय, हमारे पास अच्छी लैब भी नहीं है जिनमें व्यक्ति जाकर अपना टैस्ट करवाने के बाद पूर्ण रूप से कह सके कि मेरी जो जांच हुई उससे मैं संतुष्ट हूं । जहां टैक्नीकल स्टॉफ की कमी है, वहीं डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है, जो गांव के अस्पताल हैं, चाहे वह मेरे गांव का अस्पताल हो या किसी दूसरे गांव का अस्पताल हो। अध्यक्ष महोदय, सभी गांवों के अस्पतालों में टैक्नीकल स्टाफ और डॉक्टरों की कमी है, जिस अस्पताल में पूरा स्टॉफ नहीं होगा तो मानकर चलो कि वहां पर 100 प्रतिशत ही बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है, उससे लोगों के सामने दिक्कत आयेगी । अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों के पास पैसा है, वे तो अपना इलाज किसी प्राईवेट अस्पताल में करवा लेते हैं लेकिन गरीब आदमी कहां जाये क्योंकि आजकल दवाईयां भी बहुत महंगी होती जा रही हैं और ऊपर से जी.एस.टी. लगने के बाद तो लोगों के सामने और भी बड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो गईं हैं । जिसकी वजह से सबसे बड़ी मार गरीब आदमी पर ही पड़ रही है। सरकार ने स्वास्थ्य योजना पर बजट बढ़ाने की बजाय घटा दिया और वित्त मंत्री जी लगातार दो घंटे तक बजट प्रस्तुत करते रहे, लोगों को बरगलाते रहे, गुमराह करते रहे और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य दो घंटे तक मेजें थपथपाते रहे । अध्यक्ष महोदय, जब ये लोग आंकड़ो के हिसाब से देखेंगे तो इस बात का अंदाजा खुद–ब–खुद लग जायेगा कि यह बजट केवल और केवल दिखावे मात्र के अलावा कुछ नहीं है । अध्यक्ष महोदय, जहां शिक्षा की बात आती है तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के अंडर यह डिपार्टमेंट आता है । वर्ष 2017–18 में शिक्षा के लिए जब बजट पेश किया गया था तो उस समय में बजट की कुल राशि में से 14.24 प्रतिशत खर्च करने के बाद भी वर्ष 2018–19 में उस राशि को कम करके 12.96 प्रतिशत कर दिया गया । इस प्रकार से 1.18 परसैंट उसको कम कर दिया गया। सत्तापक्ष के लगभग सभी माननीय सदस्य यह कहते नहीं थकते कि वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि हमने हरियाणा प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर

22 नये कॉलेजिज की स्थापना कर दी। यह बात मैं भी स्वीकार करता हूं कि सरकार द्वारा कॉलेजिज तो बना दिये गये होंगे लेकिन उन कॉलेजिज में कोई शिक्षक नहीं है और हरियाणा प्रदेश में शिक्षकों की कमी इसलिए है क्योंकि सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती ही नहीं की गई है। इसी प्रकार से स्कूल्ज़ में भी 40 हज़ार से ज्यदा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। सरकार द्वारा जो नये कॉलेज बनाये गये हैं उनमें स्टाफ पूरा नहीं है। अगर स्टाफ पूरा नहीं है तो फिर वहां पर शिक्षा विभाग स्टॉफ पूरा करने के बजाये वहां से किसी न किसी डिपार्टमैंट को हटा दिया जाता है। जहां तक शिक्षा की बात है पन्नीवाला मोटा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था उस कॉलेज की वजह से पन्नीवाला मोटा गांव के 6 बच्चों का उस कॉलेज में एडमिशन होता था और उस गांव के ये 6 बच्चे हर साल सरकारी या प्राईवेट जॉब प्राप्त करते थे। यह अकेले पन्नीवाला मोटा गांव की ही बात नहीं है। इस तरह के ग्रामीण अंचल के अंदर जो अनेक कॉलेज बने उन सभी में सम्बंधित गांवों के बच्चों के लिए सीट्स रिजर्व़ होती थी। सरकार द्वारा अब पन्नीवाला मोटा के उस कॉलेज को बंद किया जा रहा है। मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी सरकार से यह रिक्वैस्ट की थी कि पन्नीवाला मोटा के इस इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करने के बजाये उस कॉलेज का सुधारीकरण किया जाये। उस कॉलेज के अंदर पूरा स्टाफ नियुक्त किया जाये ताकि उस इलाके के बच्चों को लाभ मिल सके लेकिन सरकार द्वारा उस कॉलेज का सुधार करके आगे बढ़ाने के बजाय सरकार द्वारा उस कॉलेज को बंद करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। मैंने विधान सभा के पिछले सत्र में भी यहां पर एक बात कही थी कि जो पन्नीवाला मोटा इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसीपल है जब उसकी इंक्वॉयरी की गई थी तो उसकी डिग्री को गलत पाया गया था लेकिन सरकार द्वारा उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया जी, विपक्ष के नेता बजट पर बोल रहे हैं लेकिन यहां पर न तो मुख्यमंत्री और न ही सरकार के दूसरे मंत्री बैठे हैं। इसी प्रकार से मुख्य विभागों के उच्चाधिकारी भी ऑफिसर्ज गैलरी में नहीं बैठे हैं।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया जी, बहन गीता भुक्कल जी को जो मंत्रीगण और अधिकारीगण यहां पर बैठे हैं वे दिखाई नहीं दे रहे हैं यह बड़ी चिंता की बात है because Government is very much present on the benches. सरकार विपक्ष के माननीय नेता को बड़े ध्यान से सुन रही है।

उपाध्यक्ष महोदया : गीता भुक्कल जी, आप कृपया करके बैठ जायें। आप बिना किसी परमिशन के अपने आप ही खड़ी हो जाती है। आप सदन की सीनियर सदस्या हैं। आप मंत्री भी रही हैं इसलिए आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। अभय सिंह जी, आप कृपया कंटीन्यू करें।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया जी, आज बहुत सी बातें तो अच्छी हुई हैं। पहली बात तो यह है कि दर्शक दीर्घा में आज लोगों के बैठने की जगह नहीं है और बहुत से लोग सदन की कार्यवाही को खड़े होकर देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब मैं बोलता था तो सत्तापक्ष के मंत्री और दूसरे माननीय सदस्य भी बार–बार खड़े होकर हाउस की कार्यवाही को डिस्टर्ब करते रहते थे। इसके विपरीत आज बहुत शांति है। यहां पर ऐसे–ऐसे लोग भी खड़े हो जाते थे जिनका किसी डिपार्टमैंट से सम्बन्ध नहीं होता था बल्कि वह एम.एल.ए. होता है और अपनी एम.एल.ए. की जिम्मेदारी निभाने के बजाये मंत्री की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते थे। आज इस प्रकार के सभी लोग बाहर हैं इसलिए यहां पर शांतिपूर्ण माहौल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि राम बिलास शर्मा जी ने आज सभी को कहा होगा कि तुम सभी जाओ मैं अकेला ही देख लूंगा। उपाध्यक्ष महोदया, मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा था। सरकार को शिक्षा की मद में बजट बढ़ाना चाहिए था लेकिन सरकार ने बजट को बढ़ाने की बजाय उसे उल्टा कर कम कर दिया है। यह भी प्रदेश के लोगों के साथ सरासर धोखा है। यहां पर इस बात का भी बड़ा राग अलापा गया कि हमारी सरकार एक लाख 38 हज़ार करोड़ रुपये का बजट लेकर आई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार बजट तो एक लाख 38 हजार करो़ड़ रुपये का ले आई है लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार ने यह नहीं बताया कि सरकार ने इन पांच सालों में कर्ज़ कितना लिया है? सरकार द्वारा जो कर्ज़ लिया गया है उसके ब्याज को लौटाने के लिए भी सरकार द्वारा कर्ज़ लिया जा रहा है। सरकार को यहां पर यह भी क्लीयर करना चाहिए था कि सरकार इस कर्ज़ को किन सोर्सिज़ से लौटायेगी। वर्ष 2004–05 में जब हमारी सरकार सत्तासीन थी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में भागीदार थी उस समय हरियाणा प्रदेश के अलग बनने के बाद से तब तक टोटल कर्ज़ 23,319 करोड़ रुपये था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो वह कर्ज बढ़कर 70931 करोड़ हो गया लेकिन अब इस सरकार के बनने के बाद वह कर्ज कम होने की बजाय 1,80,000/– करोड़ रुपये के करीब हो गया है। आपकी सरकार ने 5 वर्ष में लगभग

13:00 बजे

1,09,000/– करोड़ रुपये कर्ज के रूप में लिये हैं। आज के बजट का 28 प्रतिशत पैसा उसी पैसे के ब्याज और मूलधन के रूप में जायेगा। उसके अलावा आपके इस बजट में एक बात बहुत स्पष्ट की हुई है कि जो राजकोषीय घाटा होता है वह हमारी सरकार के समय में एक नया पैसा भी नहीं था जो आपकी सरकार के समय वर्ष 2017–18 में बढ़ कर 3.05 प्रतिशत हो गया था। चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा को भी पार कर गया था। इसका सीमा से ऊपर जाने का मतलब यह है कि सरकार का वित्तीय प्रबन्धन ठीक नहीं है जिसकी वजह से राजकोषीय घाटा सीमा से पार हो गया था। पिछली बार यह घाटा 8506.70 करोड़ रुपये था जो इस बार बढ़ कर 12022 करोड़ हो गया है, यह भी बढ़ा है। एक तरफ तो ये घाटे बढ़ रहे हैं तथा दूसरी तरफ यह बात भी दर्शाई गई है कि हमारे हरियाणा की पर कैपिटा इन्कम 2.5 लाख हो गई है यानि एक व्यक्ति की आय 2. 50 लाख रुपये वार्षिक हो गई है। यह सरासर गुमराह करने की बात है। अगर आप फरीदाबाद और गुरूग्राम को अलग कर दें तो वह इनकम मुश्किल से 40 हजार रुपये रह जाती है। वह 40 हजार इनकम एक परिवार की है। आज हरियाणा प्रदेश में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो प्रदेश द्वारा लिए हुए कर्ज के अनुसार जिसकी अदायगी नहीं हो रही है, जिसको कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है, उस कर्जे के साथ पैदा होता है। सरकार यह भी बताये कि यह 1,09,000/– करोड़ रुपये का जो कर्जा लिया गया है यह किसके लिए लिया गया है तथा इसको कहां पर खर्च किया गया है? इस कर्ज को खर्च करके सरकार ने किस–किस को क्या–क्या सुविधायें दी हैं? इस कर्ज का ब्याज देने के लिए सरकार के पास पैसा किस–किस सोर्स से आता है? पैसा किसी भी सोर्स से नहीं आ रहा है इसलिए सरकार को कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार यह कह रही है कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख रुपये वार्षिक है और दूसरी तरफ जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वह लगभग 1 लाख रुपये के कर्ज के साथ पैदा होता है। जिस प्रदेश में एक बच्चा एक लाख रुपये के कर्ज के साथ पैदा होता है वह प्रदेश तरक्की कैसे करेगा? आंकड़ों के हिसाब से इस बजट में आपने सबके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हैं कि जिन लोगों को बजट की सही जानकारी नहीं है, या जो इसको गहराई से अध्ययन करने वाले लोग नहीं हैं उनके लिए तो यह बजट लुभावना हो सकता है लेकिन असलियत तक जब कोई पहुंचता है और जब इसकी जानकारी लेता है तब इसका

पता चलता है कि यह बजट केवल ढ़कोसला है । इसके लिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं और मैं वित्त मंत्री व पार्लियामैंट अफेयर्ज मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि बजट के ऊपर सारी चर्चा के बाद जब इसको पास करवाने के लिए अपनी स्पीच रखें या अपनी बात रखें तो मैंने जो बातें इनके सामने रखी हैं उन सभी एक–एक बातों का विस्तार से जवाब दें ताकि हमें पता लग सके कि आपने इस बजट में आंकड़ों का गोलमाल करके किस तरह से लोगों को गुमराह किया है । उस चीज को छुपाने की बजाए वह विधान सभा के अन्दर अपनी बात जरूर कहें । आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद । आपसे एक प्रार्थना और है क्योंकि बजट सैशन है, आज हमारे 6–7 मैंबर आए हुए हैं आप इन सभी को भी थोड़ा–थोड़ा समय 10–10, 15–15, 20–20 मिनट बजट पर बोलने के लिए जरूर दें । केवल हमारी पार्टी के ही नहीं चाहे वह कांग्रेस पार्टी के लोग है, चाहे वह आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे कोई इण्डिपैंडैंट्स हैं सभी सदस्यों को बजट पर बोलने का समय दीजिए ताकि सभी लोग विधान सभा में अपने–अपने हल्के की बात रख सकें । आपका धन्यवाद ।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान (बेरी): उपाध्यक्ष महोदया, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बजट की डिस्कशन पर बोलने का समय दिया । उपाध्यक्ष महोदया, वैसे तो अगर वित्त मंत्री जी यहां होते क्योंकि पिछली बार भी जब मैं बजट पर बोला था । उसमें मैंने जो प्रश्न किए थे उन प्रश्नों के 10 प्रतिशत जवाब भी उनकी स्पीच में नहीं मिले है। जब कोई प्रश्नों को नोट ही नहीं करेगा तो जवाब कहां से देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदया : कादियान साहब, पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर यहां बैठे हैं वह नोट कर रहे हैं ।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, वैसे तो वित्त मंत्री बड़े काबिल हैं, पढ़े–लिखे हैं, फौजी हैं, मैं उनके कौशल की दाद देता हूं । जिस ढंग से उन्होंने बजट में शब्दों और आंकड़ों का मकड़जाल रचा है । इसको तो कोई अर्थ शास्त्री या हिन्दी का कोई स्कोलर दोनों बैठ कर समझाएंगे तब यह बजट समझ में आ सकता है नही ंतो यह बजट समझ में नहीं आ सकता है । आपने भी देखे होंगे कि उन्होंने बजट में कैसे–कैस शब्द इस्तेमाल कर रखे हैं । उसमें किस तरह से आंकड़ों का मकड़जाल रचा गया है । मैं वित्त मंत्रालय के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बहुत–बहुत बधाई बाद देता हूं जिन्होंने अपनी काबिलियत और महारथ से इस बजट को बनाने में और सरकार की स्कीम को बचाने में अपना सब

कुछ समर्पित कर दिया है । उपाध्यक्ष महोदया, सी.ए.जी. की रिपोर्ट किसी सरकार का या बजट का एक शीशा होता है । मैंने पिछले सैशन में भी इस बात को उठाया था कि जब किसी भी विधान सभा में, किसी भी लोक सभा में या राज्य सभा में बजट पेश होते हैं तो सी.ए.जी. की रिपोर्ट सदन के पटल पर लाई जाती है क्योंकि वह सरकार का एक शीशा है । उसमें कुछ ऑब्जैक्शंज होते हैं । उसमें सरकार की कुछ कमियां हैं । उसमें बजट अलोकेशन होता है । उसमें पैसा कहां गया, कहां पिलफ्रेज हुआ , कहां डकैती हुई, कहां लूटमार हुई यह सब सी.ए.जी. की रिपोर्ट में आता है । वह रिपोर्ट बजट से पहले क्यों नहीं आई ? उसका न आने का क्या कारण रहा ? वह किस लिए नहीं आई ? क्या आप अपनी कमियों से इतना भय खाते हैं कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट में हमारी कमियां उजागर होंगी । उपाध्यक्ष महोदया, जो मैं कह रहा हूं यह एक सीरियस मैटर है ।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय डॉ. रघुवीर सिंह कादियान को मैं निवेदन करता हूं कि आप कल झोले के ऊपर बिगड़ गए थे । उस झोले में सारा सामान है । डॉ. साहब, उस झोले में सी.ए.जी. की रिपोर्ट भी है । वह हिन्दी में भी है और अंग्रेजी में भी है ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, उसमें नहीं है । मैंने सी.ए.जी. की रिपोर्ट के बारे में श्रीमती महुआ पाल मैडम से पता किया है । उनके हस्ताक्षर होकर वह रिपोर्ट केन्द्र सरकार में गई है । केन्द्र सरकार से वह रिपार्ट आई ही नहीं है तो फिर वह कहां पटल पर रखी जाएगी और कहां वह बजट में आई है ? आप सदन को क्यों गुमराह कर रहे हैं । अब फैसला हो जाए अगर उस झोले में सी.ए.जी. की रिपोर्ट हो तो मैं अपनी गल्ती मान लूंगा ।

श्री राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, इनको बजट वाला जो झोला सौंपा गया था, उसको इन्होंने खोला ही नहीं है और जब खोला ही नहीं है तो बताओ पढ़ेगे कैसे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः उपाध्यक्ष महोदया, शर्मा जी बजट को न पढ़ने की बात कह रहे हैं जबकि हकीकत यह है कि हमारे साथी तो सारी रात सोए तक नहीं। अगर सी.ए.जी. की रिपोर्ट बजट रखने वाले झोले में होती तो यह जरूर पढ़ते। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, अगर कल दिए गए बजट के झोले में सी.ए.जी. की रिपोर्ट हो तो मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ लेकिन असलीयत यह है कि उसमें सी.ए.जी. की रिपोर्ट थी ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, डॉ कादियान जी एक विद्वान सदस्य हैं और काफी लंबे समय से इस सदन के सदस्य रहते आए हैं। कादियान जी वर्ष 1987 में हमारे साथ कोआपरेटिव मिनिस्टर रहे और श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी इनको स्पीकर तो बना दिया था लेकिन इनको कभी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया। इनको इसी बात का दुख और मलाल भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहूंगा कि बजट का यह नियम है कि बजट को प्रस्तुत करने से पहले उसका स्टेटिस्टिकल सर्वे किया जाता है उसके बाद ही वह सदन में प्रस्तुत होता है। इस झोले में 10 किलो वजन है और यह वजन ऐसे ही थोड़ा हो गया? करण सिंह दलाल जी सदन में बैठे हैं, उनको मेरी बात के लिए हुंकारे भरने का काम तो करना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदया, कादियान जी सी.ए.जी. रिपोर्ट के न होने की बात कह रहे हैं। यह स्टेटिस्टिकल सर्वे या इकॉनामिक सर्वे की बात नहीं कर रहे हैं। स्टेटिस्टिकल सर्वे अलग चीज है और इकॉनामिक सर्वे अलग चीज है तथा सी.ए.जी. की रिपोर्ट कुछ अलग चीज है। हम सदन में सी.ए.जी. की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं हमें केवल सी.ए.जी. की रिपोर्ट के बारे में ही बताया जाये ?

श्री राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, मैं हुड्डा साहब को बताना चाहूंगा कि बजट के साथ सी.ए.जी. की रिपोर्ट है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदया, बजट के साथ सी.ए.जी. की रिपोर्ट नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, यदि बजट के साथ सी.ए.जी. की रिपोर्ट है और मैं गलत बयानबाजी करते हुए सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लेकर आया जाये और अगर शर्मा जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो इनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लेकर आया जाये। यह मैटर सच्चाई और झूठ का है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, डॉ. साहब हमेशा गुस्से में रहते हैं। यह तो सिर्फ एक बैग की बात है अगर कोई कमी है तो यह भी याद रखना चाहिए कि हाउस अभी खत्म भी नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदया, शर्मा जी के बारे में असल बात मैं सदन को बताता हूँ और वह यह है कि इनको पूरी उम्मीद थी कि खट्टर साहब इनको फाइनेंस का महकमा देंगे लेकिन वह नहीं दिया गया। चलो कोई बात नहीं। उपाध्यक्ष महोदया, स्टेटिस्टकल सर्वे और इकोनोमिक सर्वे अलग–अलग चीज होती हैं और सी.ए.जी. की रिपोर्ट अलग होती है और शर्मा जी को यह बात मान लेनी चाहिए कि बजट के साथ सी.ए.जी. की रिपोर्ट नहीं है। वास्तव में सी.ए.जी. की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी ही नहीं गई। यह इस सदन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट से पहले सी.ए.जी. की रिपोर्ट न रखी जाये। कारण यह है कि चुनाव आने वाले हैं और अगर सी.ए.जी. की रिपोर्ट टेबल कर दी जाती तो सरकार की बहुत सारी पोल खुल जाती। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि सदन के पटल पर सी.ए. जी. की रिपोर्ट क्यों नहीं रखी गई?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): उपाध्यक्ष महोदया, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मैं पिछली बार इसी सदन में विपक्ष की विधायक हुआ करती थी। यदि पिछली बार की सरकार के लास्ट के दो सालों के रिकॉर्ड को देखें तो पता चलेगा कि लास्ट के दो सालो में सी.ए.जी. की रिपोर्ट टेबल नहीं की गई थी। यदि किसी को शक है तो हाउस की प्रोसीडिंग्ज निकालकर देख ली जायें । जो वर्ष 2014 का लास्ट बजट का सैशन था उसमें भी सी.ए.जी. की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, सी.ए.जी. की रिपोर्ट को सदन में इसलिए पेश नहीं किया गया कि कहीं सरकार की नाकामयाबियों का चिट्ठा न खुल जाये। सी.ए.जी. की रिपोर्ट न होने से सरकार की कमियों का पता नहीं चलता है। चुनाव के समय को ध्यान में रखकर जानबूझकर यह रिपोर्ट गायब कर दी गई है। कितने बुरे हालात हो गए हैं सरकार के?(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, कल जब सदन में झोले की बात चली तो उस समय प्रश्न काल चल रहा था और मैंने झोले पर इसलिए ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मैं प्रश्न काल को इंट्रप्ट नहीं करना चाहता था। जब झोले की बात कल की गई थी तो इन्होंने बताया था कि इसमें बजट है। फिर अगले दिन अखबारों में खबर छप गई कि झोला छाप सरकार। उपाध्यक्ष महोदया,

झोला छाप तो डाक्टर भी खतरनाक होता है? झोला छाप सरकार कहां तक लेकर जाओगे? दैनिक ट्रिब्यून में आज यह छपा है कि झोला छाप सरकार। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे रामबिलास शर्मा जी बड़े विद्वान आदमी हैं लेकिन इनके मुख्यमंत्री बनने की राह का कांटा अभी निकल नहीं सका है और यह कांटे का दर्द बार बार इनको चुभ रहा है और दर्द पैदा कर रहा है। खैर अब मैं बजट के विषय पर आता हूँ। कैप्टन साहब इस बार हवन करके सदन में बजट पेश करने के लिए आए थे और सदन में बजट पेश किया। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी सरकार के कार्यकाल का पांचवा व अंतिम बजट सदन में प्रस्तुत किया है। यदि माननीय वित्त मंत्री जी यह घोषणा करते कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की प्रॉपर्टी जनता की होगी। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का शरीर भी जनता का होगा अर्थात् जनता की सेवा के लिए ही होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि जाट आरक्षण के दौरान मेरी कोठी के नाम से जितने भी मुकद्दमे युवाओं पर दर्ज हुए हैं, मैं उन मुकद्दमों को वापिस लेता हूँ। जिन युवाओं के नाम मुकद्दमे में दर्ज हुए थे, जिसके कारण से उनका भविष्य अंधकार में चला गया है, मैं उनके लिए एक तरक्की का रास्ता खोलता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी की इस बात से माननीय वित्त मंत्री जी की फ्राखदिली और दरियादिली का पता चलता है लेकिन ऐसा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा प्रदेश को तीन बार जलाया गया है और बजट में इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। यह प्रदेश सत्ता पक्ष ने जलाया या फिर विपक्ष ने जलाया, इस बात पर अभी भी संदेह बना हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, इस संबंध में जो प्रकाश सिंह कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाये ताकि सच्चाई का पता लग सके।

उपाध्यक्ष महोदया : कादियान जी, आप सिर्फ बजट पर ही बोले।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, जिस दंगे फसाद के कारण हरियाणा का भाईचार टूटा और हरियाणा की संस्कृति टूटी है, उसको रिस्टोर करने का बजट में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : कादियान जी, यह कोई प्रश्न काल नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा का भाईचारा किसने तोड़ा है? (शोर एवं व्यवधान) जाट आरक्षण में कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री बिरेन्द्र सिंह आदि के नाम सामने आए थे। (शोर एवं व्यवधान) सारा का सारा हरियाणा जला कर राख

कर दिया। (शोर एवं व्यवधान) रोहतक की सीट कांग्रेस पार्टी क्या हार गई इन्होंने सारा रोहतक ही जला कर रख दिया। (शोर एवं व्यवधान) हम भी चुनाव तीन बार हार चुके हैं लेकिन हमने अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, सबसे बड़ा घोटाले बाज तो श्री मनीष ग्रोवर जी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : दांगी जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, लूट का माल आज किसके घर जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : जय प्रकाश जी, कृपया करके आप अपनी सीट पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : उपाध्यक्ष महोदया, रोहतक की सीट क्या हार गई कांग्रेस पार्टी की सरकार उन्होंने सारा हरियाणा ही जला कर रख दिया। (शोर एवं व्यवधान)

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Deputy Speaker, Madam, I want your protection. Please bring the House in order.(Interruption).

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, शुगर मिलों के जरिए लूट का माल श्री मनीष कुमार ग्रोवर के घर जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : डॉ0 साहब, आप अपनी स्पीच कंटीन्यू रखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : उपाध्यक्ष महोदया, श्री करण सिंह दलाल तो पूरे प्रदेश में दलाली का काम करता है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : दलाल साहब, आप अपनी सीट पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Deputy Speaker, Madam, I want your protection. Please bring the House in order.(Interruption).

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, मैं बोलना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : जय प्रकाश जी, आपको बोलने के लिए बाद में समय दे दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) अभी आप बैठ जाइए।

श्री उदय भान : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी के घर की जांच होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : उदय भान जी, आप बैठ जाइये। डॉ0 कादियान जी बजट पर बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : उपाध्यक्ष महोदया, चोरी का सबसे ज्यादा माल इनके घर पर है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं इनके विषय में कहना चाहूंगा– 'चोर मचाए शोर ।' (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : आप सब बैठिये और सिर्फ बजट पर ही बात कीजिए ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : डिप्टी स्पीकर मैडम, इस सरकार से ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं । डिमॉनेटाइजेशन की वजह से हजारों–लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं । इस बजट में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया कि उनको रोजगार देने के लिए क्या–क्या कदम उठाए जाएंगे । इस फैसले ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है । इसके अलावा जी.एस.टी. ने कारोबारियों और व्यापारियों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया । उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि उनको किस तरीके से रिहैब्लीटेट किया जाएगा । सरकार की गलतियों और लापरवाही की वजह से हजारों किसान सड़क पर आन्दोलन कर रहे हैं, हजारों मजदूर, कर्मचारी और मनरेगा कर्मचारी सड़कों पर आन्दोलन कर रहे हैं । डिप्टी स्पीकर मैडम, आप देखिये कि हमारा प्रदेश किस दिशा में जा रहा है । प्रदेश में जहां विकास का रोडमैप तैयार होना चाहिए था वहां पर सरकार की गलतफहमियों और वादाखिलाफी की वजह से प्रदेश बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है । आने वाले चुनाव में सरकार को इसका पता चल जाएगा । आज प्रदेश और देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । प्रदेश में पिछले 5 साल से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है । मेरा कहना है आज अमीर और गरीब का गैप बढ़ रहा है । आर.बी.आई., सी.बी. आई., ई.डी., इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी.ए.जी. कांस्टीच्यूशनल इंस्टीच्यूट्स/ऑटोनौमस बॉडीज़ हैं । आज पूरे देश में इनके ऊपर से विश्वास और भरोसा उठ रहा है । आज जिस तरीके से इन संस्थाओं पर डिक्टेटरशिप के माध्यम से अटैक हो रहे हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है उससे आने वाले समय

में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी, चरमरा जाएगी । इस विषय पर इंटैलैक्चूअल्स के आर्टिकल/ऐडीटोरियल भी छपे हैं । (विघ्न)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि ये कौन–सी संस्थाओं पर डिक्टेटरशिप से हमले की बात कर रहे हैं ? (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, ये किसकी इजाज़त से बोल रहे हैं ? (विघ्न)

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया, हम क्यों नहीं बोलेंगे ? अगर हम न बोलें तो क्या ये ऐसे ही झूठ बोलते जाएंगे ? मैं माननीय सदस्य करण सिंह दलाल जी से पूछना चाहता हूं कि ये किस अथॉरिटी से खड़े होकर बोल रहे हैं ? क्या ये अपने आपको स्पीकर समझते हैं ? (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, विधायक साथी सरकार पर बेमतलब के आरोप लगा रहे हैं । ये कह रहे हैं कि जो वैधानिक संस्थाएं हैं उन पर तानाशाही से हमले किये जा रहे हैं । मुझे बताइये कि किसके ऊपर हमले किये जा रहे हैं ? हमला तो आज पाकिस्तान पर हुआ है । आप उसकी बात कीजिए ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, यह बढ़िया बात है और इस कार्य में हम भी आपके साथ हैं ।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेन्द्र मोदी ने साबित कर दिया कि मोदी जी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं । उन्होंने कहा था कि मैं आतंकवाद को नेस्तनाबूत कर दूंगा और आज उन्होंने उसकी कार्रवाई शुरू कर दी है । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, सुप्रीम कोर्ट में लोग न्याय पाने के लिए जाते हैं । हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज मीडिया के माध्यम से जनता के दरबार में आये कि हमें न्याय दिलाया जाए । (विघ्न)

श्री अनिल विज: उपाध्यक्ष महोदया: माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजिज की प्रैस कॉन्फैंस करने वाले मामले में सरकार का क्या रोल है ? सरकार का इस मामले में कोई रोल नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज प्रैस कॉन्फ्रैंस करते हैं तो इसमें सरकार का क्या रोल है ?

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रैस कॉन्फ्रैंस करने वाले मामले में सरकार का कोई रोल नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए।

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदयाः इस मामले में सरकार का कोई रोल नहीं है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आज तक इस प्रकार से जजिज ने कभी प्रैस कॉन्फ्रैंस नहीं की थी। ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ ।

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदया, अगर जज प्रैस कॉन्फ्रैंस कर रहे हैं तो इसमें सरकार क्या कर सकती है ? आज बात पाकिस्तान पर हमले की हो रही है परन्तु विपक्ष के माननीय सदस्य इस बात को डायवर्ट करना चाहते हैं। आज माननीय प्रधान मंत्री जी ने पाकिस्तान पर अटैक करके दिखा दिया है कि इस देश पर आतंकवादी हमले को सहन नहीं किया जाएगा। आतंकवादी कहीं पर भी छिपे हुए हों, उनको वहीं पर जाकर मारेंगे। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादियों के अड्डे थे, उनको सेना ने नष्ट कर दिया। हमारे फौजियों ने आतंकवादियों को पाकिस्तान में उनके घर में घुसकर मारा है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदया, हमारे फौजियों ने पाकिस्तान में बने हुए आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट कर दिया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने साबित कर दिया है कि उनका 56 इंच का सीना है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने शेरों वाला काम किया है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है परन्तु माननीय मंत्री जी बीच में बोलकर मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं इसलिए Deputy Speaker Madam, I want your protection. (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैनः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, आतंकवाद के सफाये के मामले पर हम सब एक हैं। माननीय मंत्री जी को फौजियों को राजनीतिक दायरे में नहीं लाना चाहिए। आतंकवाद के सफाये के मामले में हम सब देशवासी एक हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदया, विपक्ष के माननीय सदस्यों को माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहिए और आतंकवाद के सफाये के मामले में हमारे पूरे देश को एक होकर माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः कादियान जी, आप अपनी बात कंटीन्यू रखें।

डॉ0 रधुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि आतंकवाद के सफाये के काम के लिए हमें माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहिए। आज पूरा देश माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ खड़ा है। (विघ्न)

श्रीमती शकुंतला खटकः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदया, आतंकवाद से लड़ने के मुद्दे पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस दिन पुलवामा में जवानों पर आतंकवादी हमला हुआ था उसी दिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने फौज को खुली छूट दे दी थी कि वे दिन, समय और स्थान स्वयं तय करके जवानों पर हुए आतंकवादी हमले का बदला लें। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी फौज ने वह काम करके दिखा दिया है। आज पूरा देश माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ खड़ा है। यह बदला लेने के लिए पूरे देश माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा है।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, हम भी आतंकवादी हमले के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ हैं और देश की सरकार के साथ हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश पर आतंकवादी अटैक हुआ तो हमारी फौज ने भी कार्रवाई की है। हम सब देशवासी

एक हैं और हम देश के साथ हैं। सरकार को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह ठीक बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः किरण जी, प्लीज आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी अपनी बात रखेंगे।

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों को बैठने के लिए कह दें। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः कादियान जी, आप अपनी बात कन्टीन्यू रखें। सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं।

डॉ0 रधुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, किसानों के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए इस बजट में कोई सब्सिडी का जिक्र नहीं है। इसमें ना ही मुनाफे को दोगुना करने के लिए कोई कदम उठाए गये हैं और ना ही डाईवर्सिफिकेशन का कोई जिक्र किया गया है। न ही किसानों के कर्जे को माफ करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की कोई बात नहीं की है। इस बजट में प्रदेश सरकार को न तो केन्द्र सरकार से कोई आर्थिक मदद मिली है और ना ही कोई बड़ा प्रोजैक्ट लगाने की बात की गयी है। सरकार का जश्न, गीत–गानों व स्वर्ण जयंती मनाने पर ध्यान है। अफसरशाही ने प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार करने की बजाय माननीय वित्त मंत्री जी को बजट के मामले में उलझा दिया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्लान और नॉन प्लान बजट की बात का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि पहले वर्ष 2018–19 में नॉन प्लान बजट 73.91 प्रतिशत था परन्तु सरकार ने अब वह बजट घटाकर 71.3 प्रतिशत कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही सीरियस मैटर है। इसमें नॉन प्लान की परसैंटेज तो घटी है लेकिन वॉल्यूम 9054/– करोड़ रुपये की है। पिछले साल की बजाय अब वर्ष 2019–20 के बजट में एस्टीमेट बढ़ा दिया है। नॉन प्लान एक्सपैंडिचर का इस तरह से बढ़ना बहुत ही सीरियस मैटर है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि प्रदेश में कर्मचारियों की

संख्या बढ़ रही है और उनकी तनख्वाह भी बढ़ रही है जिसके कारण नॉन प्लान एक्सपैंडिचर बढ़ रहा है।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान: उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी को इसमें परसैंटेज देखनी चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: उपाध्यक्ष महोदया, इसमें परसैंटेज तो ठीक है क्योंकि इस बार 38,000 करोड़ रुपये की राशि नॉन प्लान बजट में मिलेगी।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान: उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने बताया कि नॉन प्लॉन बजट में 9,000 करोड़ रुपये बढ़े हैं। यह अच्छी बात है कि अब प्रदेश में 38,000 करोड़ रुपये नॉन प्लान बजट में मिलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब कर्मचारी बढ़ेंगे तो नॉन प्लान बजट भी बढ़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अगर नॉन प्लान बजट बढ़ाया है तो कर्मचारियों की पुरानी पैंशन बहाल कर दें, एडहॉक बेसिज कर्मचारी, डी.सी. रेट के कर्मचारी, ए.एन.एम. और मिड डे मील वर्कर्ज को भी सैलरी दें। कर्मचारियों की पुरानी पैंशन स्कीम बहाल करे और कच्चे कर्मचारियों के लिए रेगुलराईजेशन पॉलिसी बनायें। इन सभी चीजों के लिए सरकार को कोई न कोई स्टैप उठाना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश धनखड़: उपाध्यक्ष महोदया, बजट में नॉन प्लान के लिए पैसे बढ़ाये गये हैं, यह अच्छी बात है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक और विषय के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को बोलना चाहिए था, परन्तु वे नहीं बोले। इसमें लिखा गया है कि माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा फरवरी, 2019 में झज्जर जिले के बाढ़सा गांव में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, नयी दिल्ली का विस्तार है, का उद्घाटन किया गया है। Madam, what about ten other projects ? इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। इनमें National Cardiovascular Centre (600 beds) 2400 Crore, General-purpose hospital (500 beds) 400 crore, National Transplantation Centre (500 beds) 400 crore, National Centre for Child Health (500 beds) 400 crore, Digestive Diseases Centre (500 beds) 400 crore, National Institute for

Geriatrics (200 beds) 160 crore, Comprehensive Rehabilitation Centre 200 crore, Centre for Blood Disorders (120 beds) 200 crore, Centre for Laboratory Medicine 200 crore, National Centre for Nursing Education and Research 100 crore है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये राज्य सभा के एक सवाल के जवाब में आई है कि ये सभी सैंटर्ज भी खोले जाएंगे, लेकिन हरियाणा के बजट में इन 10 सैंटर्ज का कोई जिक्र नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, मुझे खुशी है कि हमारे रेवाड़ी जिले में एम्स बने और वहां की जनता को इसकी सुविधाएं मिलें, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर इन संस्थाओं के साथ कोई खिलवाड़ हुआ तो यहां पर बहुत बड़ा जान–माल का नुकसान हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदया, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन संस्थाओं की भी स्थापना की जाए। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि इन्होंने पहले भी बेरी, रोहतक और झज्जर में जान–माल का नुकसान करवाया है और अभी भी नुकसान करवाते जा रहे हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने यह माना है कि यह राज्य सभा का उत्तर है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार ने इन सारी चीजों को ऑन किया है कि यह एम्स का सैकंड कैंपस है और हमें जो करना है, वह हम सब करेंगे। कांग्रेस पार्टी केवल अफवाहें फैलाने वाली पार्टी बन चुकी है और यह रोजाना लोगों में ख्वामखाह ही अफवाहें फैलाने का काम कर रही है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ये सारी की सारी बातें केन्द्र सरकार ने ऑन की हुई है और बाढसा एम्स में जो होना था, वह सब होगा। उपाध्यक्ष महोदया, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को इस बात का दर्द है कि इनकी पार्टी के कार्यकाल में एम्स क्यों नहीं बना और हमारी सरकार के कार्यकाल में एम्स बनाने के लिए उद्घाटन और भूमि पूजन भी हो चुका है, इसलिए इन लोगों को हमारी सरकार से ईर्ष्या हो गई है और इन्हें यह लगने लगा है कि अब ये जनता को क्या जवाब देंगे ? उपाध्यक्ष महोदया, जहां पर नील गाय प्रजनन करती थी, अब वहां पर हमने एम्स बनाने का काम शुरू कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी लघु और सीमांत किसानों को 6000 रुपए सालाना दिए जाने की घोषणा की गई थी और इन पैसों को राहुल गांधी जी ने दिनों में बांटकर एक दिन के हिसाब से 17 रुपए कर दिया। मैं राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने पैसों को घंटों में

नहीं बांटा। कांग्रेस पार्टी ने एक सिस्टम बना लिया है कि अगली बातों को पहले से पहले कहे, उसका अफवाहें बनाने का काम करे। इस तरह से कांग्रेस पार्टी इसका दुरुपयोग कर रही है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि ये सारी की सारी चीजें होने वाली हैं और उनके पास राज्य सभा का पॉजीटिव उत्तर है। माननीय सदस्य झूठे सवाल खड़ा करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन इन्हें जनता को गुमराह करने से बचना चाहिए। माननीय सदस्य लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यह बिल्कुल ही गलत बात है। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर इस बजट में बाढ़सा के कैंसर इन्स्टीट्यूट का जिक्र है तो इन 10 संस्थाओं का भी जिक्र होना चाहिए था। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि जो हुआ है, उसे हमने बता दिया है और जो होना है, वह होकर ही रहेगा। (विघ्न) वह दिल्ली एम्स का दूसरा कैम्पस है। इसके साथ ही साथ एक अलग से एम्स बिलासपुर, रांची और रायपुर आदि में बनने जा रहा है। उस मनेठी में एम्स के होने का बहाना बनाकर और उसके प्रति ईर्ष्या दिखाते हुए, इसके महत्व को कांग्रेस पार्टी कम दिखाने का नाटक कर रही है। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं कि इसका महत्व बिल्कुल कम नहीं हो रहा है और यह बाढ़सा के जैसा एम्स था, उससे बेहतर होगा। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि ये झूठी अफवाहें न फैलाएं और इलाके की जनता को गुमराह करने का काम न करें। मैं इन्हें यही कहना चाहता हूं कि ये राजनीति के लिए इतने ओछे हथकंडे न अपनाएं कि लोगों को गुमराह ही करना शुरू कर दें। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजनीति में ड्रामा तो ये करते हैं। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मैं माननीय सदस्य डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी को बताना चाहूंगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस समय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2012 में बाढसा में एम्स बनाने का काम शुरू करवाया था और इस बात को हुड्डा साहब ने भी मानी है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की यह कोशिश है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलें और हम 19 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल भी चुके हैं। (विघ्न) भिवानी जिले में पंडित नेकी राम शर्मा

जी के नाम से भी एक मेडिकल कॉलेज खोला गया है। हमारी बहन श्रीमती किरण चौधरी जी की दिक्कत यह है कि ये पूरी की पूरी बात सुनना नहीं चाहती हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : किरण जी, प्लीज आप बैठ जाये । (विघ्न)

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि आप हमारे राइट को प्रोटैक्ट कीजिए । (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी जब अपनी बात कहती हैं तो बहुत देर तक बोलती रहती हैं जब हम अपनी बात कहने के लिए खड़े होते हैं तो बीच में ही खड़ी हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदया, मुझे मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर कंपलीट करने दीजिए । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी हमें गुमराह नहीं कर सकते हैं । (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या को कहना चाहता हूं कि आप कभी गुमराह नहीं हो सकती हो और आपको कोई गुमराह कर भी नहीं सकता है । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मुझे कोई गुमराह नहीं कर सकता है । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : किरण जी, यही बात तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं । किरण जी, प्लीज बैठ जायें ।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, एम्स को बनाने का प्रौविजन भारत सरकार के बजट में है और इसको बनाने के लिए सौभाग्य से श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 8 हजार करोड़ रुपये की राशि अलॉट की है और यह एम्स हमारे अहीरवाल में है। उपाध्यक्ष महोदया, यह जो बाढ़सा में एम्स की एक्सटैंशन का मामला है, इस बात को भी हुड्डा साहब ने माना है कि वर्ष 2012 में इसका उद्घाटन हुआ था। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने वर्ष 2015 में एम्स–2 बनाने के लिए बाढ़सा में भूमिपूजन करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसमें 700 बैड का कैंसर इंस्टीट्यूट चल रहा है। हमारी सरकार मनेठी में जो 'एम्स' बनाने जा रही है उसको लेकर मेरी बहन गीता भुक्कल जी और डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान साहब ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, उसको सुनकर

मुझे बहुत दुःख हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी बात पर धमकी दे रहे थे और किसको धमकी दे रहे थे, कि बहुत बड़े जानमाल का नुकसान हो जायेगा। जानमाल का नुकसान क्यों हो जायेगा? किस बात को लेकर के जानमाल का नुकसान हो जायेगा? आपने तो पहले भी जानमाल का नुकसान करके देख लिया है। उपाध्यक्ष महोदया, इन लोगों की भाषा ठीक नहीं है और मुझे इनकी भावनाएं भी ठीक नहीं लगती है।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक भाषा के इस्तेमाल की बात है, हम इतने कमजोर नहीं हैं कि अगर वर्तमान सरकार हमारे हकों के ऊपर अटैक करेगी तो इसके लिए हमें चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं?

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, हुड्डा साहब ने अपने प्रयत्नों से बाढ़सा में एम्स की एक्सटेंशन का वर्ष 2012 में उद्घाटन किया था और हमारी सरकार ने उसको कंप्लीट करने का काम किया है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं कि इन लोगों के कौन से अधिकारों पर अटैक हुआ है? क्या मनेठी और अहीरवाल हरियाणा प्रदेश का हिस्सा नहीं है?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, ये लोग बहुत गहरा षड़यंत्र रचने की फिराक में हैं और ये चाहते हैं कि बाढ़सा के आस पास बंजर हो जाए। हमारी सरकार एम्स बनाकर विकास करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा वहां ऐसा वातावरण उत्पन्न करना कि ये इलाका ठीक नहीं है, ये इलाका तो दंगे और आग लगाने वाला है । इस षड़यंत्र के तहत सोचते हैं, ये लोग भले नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदया, इन्होंने रोहतक को जलाया और आज वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया है । मैं इन लोगों को कहना चाहूंगा कि वहां पर विकास ज्यों का त्यों होना है । मैं वहां के स्थानीय लोगों को बता कर आया हूं कि डॉक्टर कादियान जैसे लोग जो आज बयान दे रहे हैं। वे ऐसी बातें करके यहां का विकास रुकवाना चाहते हैं, ये लोग कभी भी तुम्हारी भलाई के बारे में नहीं सोच सकते हैं । ये तो वो लोग हैं, जो अपनी राजनीति रोटियां सेंकने के लिए अपने ही शहर को जलवाने में हिचक महसूस नहीं करते हैं इन्होंने बेरी, रोहतक, कलानौर और झज्जर तक जला दिये, ये वही लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदया, इन लोगों से हरियाणा प्रदेश की जनता को बचाना होगा और अभी भी ये लोग उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाढ़सा में सभी तरह का विकास किया जायेगा और ये लोग विकास होता हुआ

नहीं देख सकते हैं ये लोग यही सोचते हैं कि आज बाढ़सा में भी आगजनी कैसे हो? यही इनकी सोच है और इनकी सोच को खत्म करना हमारा काम है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, इन लोगों को यह बात अच्छी नहीं लग रही है।

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी बार–बार कह रहे हैं कि हरियाणा जला दिया। जब हरियाणा सरकार के पास प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट है तो सी.बी.आई. इन्क्वायरी के लिए ऑर्डर कीजिए। मैं विधान सभा में यह प्रस्ताव करता हूं और दांगी साहब ने भी एक प्रस्ताव रखा है कि जो हरियाणा प्रदेश में आगजनी हुई है। (विघ्न)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : उपाध्यक्ष महोदया, एम्स को लेकर ये लोग अपने समय में भी गुमराह होते रहे और करते रहे और आज भी गुमराह कर रहे हैं । मैं सन् 2012 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लैटर पढ़कर सुनाना चाहता हूं । (विघ्न) इन लोगों को सच से इतना डर लग रहा है ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, ये लोग हरियाणा प्रदेश को जलाने की बात करते हैं और हम इस पर पानी भी न डालने का काम करे। ये लोग तो हर वक्त पेट्रोल और माचिस साथ में लेकर हरियाणा प्रदेश को जलाने की फिराक में रहते हैं। (विघ्न)

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया जी, इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि बाढ़सा में कभी भी कोई एम्स सैंक्शंड नहीं हुआ था। मैं यहां पर इस मामले से सम्बंधित गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का लैटर नम्बर वी–16015/02–2009/एम.बी., दिनांक 17 जनवरी, 2012 पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें यह लिखा हुआ है कि –

For extension of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi and setting up of other allied Health Institutions, the Central Government has recently cleared a proposal to set-up a temporary outreach OPD of AIIMS. "I again want to utter the words, not AIIMS but OPD of AIIMS. इस प्रकार से यह पूरी तरह से क्लीयर है कि वहां पर ओ. पी.डी. ऑफ एम्स चल रही है। एम्स की सैट–अप का मतलब यह होता है कि वहां पर मैडीकल स्टूडैंट्स भी भर्ती किये जायेंगे और उनकी अलग सीट्स भी होंगी। ऐसा नहीं है सिर्फ एक्टैंशन एम्स अर्थात जो दिल्ली का एम्स है उसकी

एक्सटैंशन यहां पर की गई है वहां पर कोई एम्स सैट अप नहीं हुआ था। एम्स हमारी सरकार ने मनेठी में सैट–अप किया है।

श्री आनंद सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया जी, जिस प्रकार की बात मौजूदा सत्र में हो रही है उनसे कोई अच्छा संदेश नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी विषय हो पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धैर्यपूर्वक बात करनी चाहिए। विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर भी पॉजीटिव में मिलने की आवश्यकता है। डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी ने यहां पर अपना प्रश्न रखा है। यह प्रश्न आज से तीन दिन पहले भी आ चुका है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले क्लीयर भी कर दिया था कि जो इंस्टीच्यूशंज डॉ. कादियान जी ने यहां पर पढ़ी हैं जो बाढ़सा में सैट–अप होना है। वे सारी मानी गई हैं कि ये इस्टीच्यूशंज यहां पर खोली जायेंगी। जो बात यहां पर पहले हो चुकी है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया हो उस मामले के ऊपर मंत्री महोदय द्वारा इतने जोर–शोर के साथ बोलना उचित नहीं है। यहां पर इस प्रकार का व्यवहार मंत्री जी को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी माननीय सदस्यों की जनता के प्रति एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके हिसाब से हमें यहां पर बात करनी चाहिए। विपक्ष के माननीय सदस्यों को यहां पर प्रश्न पूछने का अधिकार है और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब देना सत्तापक्ष का कर्त्तव्य बनता है। मंत्रियों द्वारा यहां पर सभी सवालों का जवाब धैर्यपूर्वक दिया जाना चाहिए। ऐसी उनकी प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही भी बनती है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैडम, ये यहां पर बार–बार इशू उठता है जबकि इस सम्बन्ध में पहले ही क्लैरिफिकेशन हो गई थी। जो बाढ़सा है वह एम्स का कैम्पस–II है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें जैसा डॉ. कादियान साहब ने कहा वे इंस्टीच्यूट मंजूर हुए हुये हैं। मत्री जी कहते हैं जो इंस्टीच्यूट वहां पर मंजूर हुए हैं वे सभी वहां पर स्थापित होंगे लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि वहां पर एक इंस्टीच्यूट ऐसा था जिसका 2400 करोड़ रुपये का टैण्डर हो गया था और वर्तमान गवर्नमैंट के सत्तासीन होने के बाद वह कैंसिल हुआ है। यह जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमैंट की बनती है। इस मामले को भी देखा जाये। हम भी यह चाहते हैं कि रेवाड़ी में एम्स बने हमें भी इसकी खुशी है क्योंकि भी हमारी स्टेट का ही हिस्सा है। मेरा मंत्री जी से यह कहना है कि इस मामले में कंफ्यूजन क्रिएट करने

की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे देश में जो प्रत्येक स्टेट को एक एम्स मिलता है वह हमारी स्टेट को रेवाड़ी में मिला है हमें इसकी बहुत खुशी है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मनेठी और बाढ़सा का न तो कोई लिंक है और न ही कोई कम्पीटीशन है। हरियाणा प्रदेश में जो भी इंस्टीच्यूट सैंक्शंड हो चुके हैं वे सभी के सभी बनें, यह सरकार की जिम्मेदारी है। हम इसको सरकार के नोटिस में ले आये हैं इसलिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया जी, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी बिलकुल ठीक कह रहे हैं। जब इन्होंने यहां पर सवाल उठाया उसी समय देश के हैल्थ मिनिस्टर और जो एम्स को देखने वाले आई.ए.एस. अधिकारी मिस्टर पाण्डे दोनों से मेरी बात हुई है। जैसा हुड़डा साहब कह रहे हैं उन दोनों ने यही कहा। पहली बात तो यह है कि बाढ़सा में सैपरेट एम्स नहीं है बल्कि यह दिल्ली के एम्स का ही एक्सटैंशन है। यह दिल्ली के एम्स का ही दूसरा कैम्पस है। इसको उस रूप में देखना जैसा मैंने कहा कि रायपुर का एम्स है, रांची का एम्स है या फिर मनेठी में बन रहा है वे एक सैपरेट आईडैंटिटी के साथ बन रहे हैं। यह हमारे लिए अच्छी बात है कि बाढ़सा में जो एम्स का कैम्पस है वह दिल्ली में स्थित मेन एम्स का ही हिस्सा है। दूसरी बात इन्होंने यह कही है कि जितनी भी ट्रेड्स हमने यहां पर सोची हैं उनमें से एक ट्रेड को हमने कम से कम समय में पूरा किया है और दूसरी ट्रेड्स को भी हमें यहां पर पूरा करना है। एक भी चीज को हम यहां से नहीं घटा रहे हैं, सारी की सारी चीजें पूरी कर रहे हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, इस प्रकार से तो इसमें कंट्रोवर्सी हो गई है। मेरा तो इस बारे में यही कहना है कि कैंसर इंस्टीच्यूट भी केन्द्र सरकार द्वारा ही बनाया गया है। मेरा तो कहना यह है कि ये जो 10 इंस्टीच्यूशन्ज हैं जो इसमें मैन्शन नहीं थे, वे भी बनने चाहिएं थे। इसमें मैन्शन नहीं था इसलिए मैंने बोला है। उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं बजट पर वापिस आना चाहता हूं। ऐलोकेशन ऑफ बजट बहुत महत्वपूर्ण आसपैक्ट है। माननीय नेता प्रतिपक्ष भी बोल रहे थे कि बजट का जो घेरा है वह कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, कैसे किस विभाग को कितना ऐलोकेट किया जाये? जरूरतों के हिसाब से किस विभाग को कितना मिलना चाहिए। बहुत से विभागों का पांचों वर्षों का परसैंटेज के हिसाब से बजट ऐलोकेशन मेरे पास है। मैं कुछ विभागों का जिक्र करना चाहूंगा। एग्रीकल्चर और सिंचाई का वर्ष 2015–16 में टोटल बजट का 12.39 प्रतिशत बजट ऐलोकेट किया गया था जो

वर्ष 2017–18 में 12.49 तथा वर्ष 2018–19 में 12.22 तथा इस वर्ष 2019–20 में बजट ऐलोकेट किया गया है वह 10.31 प्रतिशत कर दिया गया है। इस प्रकार एग्रीकल्चर एण्ड एलायड का बजट लगातार पांचों सालों में तेजी से कम हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी तरह से कम हो कर 11.60 प्रतिशत पर आ गया है। इसी तरह से अगर पॉवर की बात की जाये तो जहां वर्ष 2015–16 में 8.27 प्रतिशत था वह 2017–18 में घट कर 6.31 प्रतिशत पर आ गया था। वर्ष 2018–19 में 5.87 प्रतिशत पर आ गया था और वर्ष 2019–20 में घटकर 4.68 प्रतिशत पर आ गया है। इसी प्रकार से अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाये तो वर्ष 2015–16 में कुल बजट का 3.82 प्रतिशत था जो वर्ष 2017–18 में घटकर 3.75 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2018–19 में 4.14 प्रतिशत था जो वर्ष 2019–20 में घट कर 3.80 प्रतिशत पर आ गया है। यह कुल बजट का ऐलोकेटिड बजट के प्रतिशत के हिसाब से मैंने इन विभागों का बताया है। उपाध्यक्ष महोदया, देश या प्रदेश की 70–80 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है। किसान किसी भी देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान की जेब में पैसा है तो बाजार में भी रौनक है, अस्पताल में भी रौनक है, कोर्ट कचहरी में भी रौनक किसान के ऊपर ही डिपैंड करती है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और बाजार में भी रौनक किसान के कारण ही है। ये सारी चीजें किसान की जेब में पैसे के दम पर ही चलती हैं। आज किसान गरीबी और बदहाली की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर है और कृषि का बजट घटता जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान मरा नहीं है, किसान सोया हुआ है, वह अनभिज्ञ है। खराब मौसम किसान का दुश्मन है, ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी भी किसान की दुश्मन हैं। इसी प्रकार से कीड़े कांटे और बीमारी किसान की दुश्मन हैं। किसान की इनपुट्स के जो दाम बढ़ रहे हैं वे भी किसान के दुश्मन हैं तथा किसान को उसकी उपज के जो अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं वे भी किसान के दुश्मन हैं। इसके अतिरिक्त जिस ढंग से कृषि के लिए कम बजट ऐलोकेशन हुआ है वह भी किसान का दुश्मन है। मैडम, जिस तरह से एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड सैक्टर्स में बजट की एलोकेशन लगातार पांच साल से डाउन हो रही है तो उसमें सरकार भी किसान की दुश्मन है क्योंकि बजट में न किसी प्रकार की डायवर्सिफिकेशन है, न कोई दुगुना करने की बात कही है । इसमें न कहीं स्वामीनाथन की बात कही गई है, न कोई किसी प्रकार की प्रोडक्टीविटी को बढ़ाने की बात कही गई है ।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा

उपाध्यक्ष महोदया : डॉ. साहब, आप बाद में बोल लेना । मुख्यमंत्री जी कुछ घोषणाएं करना चाहते हैं ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस नाते से एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं । अपने देश में व्यक्ति के पहचान की एक बहुत बड़ी सुविधा दी गई है । हर व्यक्ति की, हर नागरिक की पहचान उसके आधार की बनाई गई है । मैं समझता हूं कि उस आधार की पहचान के बाद बहुत सी सरलता और बहुत सी सुविधा सामान्य व्यवहार में और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में व्यक्ति को अपनी पहचान के लिए जगह–जगह दर–दर भटकना नहीं पड़ेगा जैसे पहले भटकना पड़ता था । उसके लिए कभी किसी की शिनाख्त ले जाओ और कभी किसी की शिनाख्त ले जाओ और झूठी–सच्ची शिनाख्तों के बाद बहुत से विवाद भी होते थे लेकिन जब से आधार कार्ड बना, आधार नं. बना तब से बहुत सी ऐसी समस्याएं, ऐसे विवाद समाप्त हो गए और सामान्य जीवन का सरलीकरण हुआ है । आज मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक और विचार किया है । अभी तक तो आधार कार्ड के नाते से व्यक्ति की पहचान ही की जाती थी लेकिन कुछ सरकारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति की बजाए परिवार को मिलती हैं और हमारे समाज की व्यवस्था में परिवार अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है । परिवार की पहचान के साथ–साथ बहुत चीजें जुड़ी हुई होती हैं । उसको विचार करके हम उसमें एक नई योजना की शुरूआत करने जा रहे हैं । जिसमें हम हर परिवार का एक पहचान पत्र अर्थात फैमिली आई.डी. के नाम से एक परिवार पहचान पत्र बनाने जा रहे हैं ताकि एक परिवार की इंडीपैंडेंट परिवार के नाते से यह पता चल सके कि उसका मुख्य व्यवसाय क्या है ? उसमें कितने सदस्य हैं ? उनमें जो नये सदस्य जुड़ने वाले हैं वह भी साथ–साथ जुड़ते जाएंगे । एक रियल टाईम अर्थात सैंसस–बी वह भी हमारे इस सिस्टम से संभव हो पाएगा । यानि वह परिवार पहचान पत्र होगा जिसको हम फैमिली आई.डी कहेंगे । ऐसा हम जल्दी ही एक परिवार पहचान पत्र बनाने जा रहे हैं । हमने इसकी शुरूआत इस नाते से की है जिसके लिए लगभग 28 लाख परिवारों का डाटा कलैक्शन हो गया है । सामान्यतः अनुमान के हिसाब से हरियाणा में 52 से 55 लाख परिवार हैं ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : मुख्यमंत्री जी, आपका परिवार कितने सदस्यों का हैं ।

श्री मनोहर लाल : कादियान जी, परिवार एक मैंबर का भी हो सकता है और 10 मैंबर का भी हो सकता है । मेरा परिवार जो मैंने घोषणा की है वह आज की डेट में अढ़ाई करोड़ लोगों का परिवार है । मैं अपने परिवार के अढाई करोड़ लोगों की चिन्ता करता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : मुख्यमंत्री जी, आप उन अढ़ाई करोड़ सदस्यों का हिसाब दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : कादियान जी, हम सभी का हिसाब ले रहे हैं । आप जरा मेरी पूरी बात को सुन लीजिए । (शोर एवं व्यवधान) आप कोई अच्छी बात हो तो उसकी सराहना करना भी सीख लीजिए । हर चीज में आलोचना ही आलोचना करना यह उचित नहीं होती है ।(शोर एवं व्यवधान) इसलिए जो यह 28 लाख परिवारों का डाटा कलैक्शन हो गया है यह क्रम अभी चल रहा है । मैं समझता हूं कि आने वाले महीने में बाकी बचा हुआ काम भी 31 मार्च से पहले–पहले हम कम्पलीट कर लेंगे । उनको एक विधिवत आई.डी. मिलेगी और परिवार का एक नं. भी मिलेगा ताकि अगर कोई डुप्लीकेसी होती है तो उसका बचाव हो सके । अब इसमें हम एक नई योजना शुरू कर रहे हैं ।

श्रीमती किरण चौधरी : मुख्यमंत्री जी, क्या यह राशन कार्ड से अलग होगा ?

श्री मनोहर लाल : किरण जी, यह राशन कार्ड से अलग होगा । राशन कार्ड में भी बहुत से सर्वे समय–समय पर होते रहे हैं और बहुत सी शिकायतें आती रही हैं । उस राशन कार्ड में भी सामान्यतः जो राशन कार्ड बनवाना चाहता है वही बनवाता है लेकिन यह तो हर एक परिवार का होगा । उस परिवार को किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वह हर परिवार की एक पहचान होगी । चाहे वह राशन कार्ड बनवाए या न बनवाए । वह राशन कार्ड पीला बनवाए, नीला बनवाए, गुलाबी बनवाए, हरा बनवाए, खाकी बनवाए चाहे कोई भी राशन कार्ड बनवाए या न बनवाए लेकिन अब हर परिवार का प्रदेश का एक प्रकार से जो प्रदेश का डोमिसाईल है वह सभी उसमें दर्ज होंगे । उसमें भी हम व्यवस्था बनाएंगे कुछ माईग्रेशन होती है । कुछ प्रदेश से बाहर के लोग आ जाते हैं और कुछ अपने प्रदेश से बाहर चले जाते हैं । यह सारी व्यवस्था हम बनाएंगे लेकिन इसमें विधिवत प्रदेश का एक डाटा एकत्र होगा । इसमें आज जिस योजना की मैं घोषणा करने जा रहा हूं वह ऐसे पात्र परिवार हैं जो सामान्य आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवार हैं जिनकी चिन्ता हम कर रहे हैं, चाहे कोई किसान के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे

श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं या फिर चाहे कारीगर के रूप में ही काम क्यों न कर रहे हों, किसी भी प्रकार के वे परिवार जिनके पास पांच एकड़ से कम की जमीन है यानी दूसरे शब्दों में जिनके पास 2 हैक्टेयर या इससे कम की जमीन है और जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपया या इससे कम है अर्थात वर्ष की 1 लाख 80 हजार रुपये आय है, ऐसे परिवारों के लिए मैं अब एक योजना सदन के सामने रख रहा हूँ। कल बजट में इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है और अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष भी इस योजना के बारे में जानना चाह रहे थे, अतः अब मैं इस योजना को सदन के सामने रखने जा रहा हूँ। इस योजना के तहत अगर इस कैटेगरी में जैसाकि मैंने अभी बताया था, परिवार में 2 या 3 सदस्य भी हैं तो भी परिवार के नाते एक सिंगल व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के दो भाग है। प्रथम भाग में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु के परिवार के सदस्य शामिल हैं, दूसरे भाग में 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के परिवार के सदस्य शामिल हैं और तीसरे भाग में परिवार के वे सदस्य शामिल हैं जिनकी आयु 60 साल से उपर है। वास्तव में यह योजना जो बनाई गई है केवल 18 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष तक की आयु के परिवार के सदस्यों के लिए बनाई गई है और जो घर का मुखिया जिसकी आयु 60 वर्ष से उपर की है, उसकी योजना अलग से लाई जायेगी। वर्तमान में केवल 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु वाले परिवार के सदस्यों के लिए दो भागों में यह योजना लाई जा रही है। जहां तक इस योजना का प्रथम भाग है अर्थात 18 से 40 वर्ष तक की आयु के वे व्यक्ति जो इस योजना में कवर होंगे उनको प्रति व्यक्ति 500 रुपये प्रति महीने अर्थात साल के 6000 रुपये देने की व्यवस्था की गई है। बजट में इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और भविष्य में अगर 100–200 करोड़ रूपया कम भी पड़ता है तो इसको सप्लीमेंटरी में डाल देंगे क्योंकि एक्जैक्ट हिसाब कभी नहीं हुआ करते और थोड़ी बहुत फ्लकचुएशन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बनाई गई है जिसके तहत किसानों के अलावा अन्य सब वे व्यक्ति जिनकी मासिक आय 15000 रुपये तक है, वे इस योजना के तहत हर चार महीने में 2000 रुपये नकद प्राप्त कर सकते हैं। कल–परसों इस योजना की पहली किस्त दे दी गई है और जल्द ही दूसरी किस्त भी दे दी जायेगी। इसी योजना के अल्टरनेट के तौर पर भी सरकार ने प्रावधान किए हैं। मान लो कोई कैश नही लेना चाहता तो उनके लिए भी

योजनाएं बनाई गई है जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जिसके तहत 60 वर्ष की आयु के पश्चात 3000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे और इसी प्रकार जीवन ज्योति बीमा योजना बनाई गई है, यह योजना बिना एक्सीडेंटल अवस्था के लिए बनाई गई है, जिसके तहत 2 लाख रुपये का बीमा किया जाता है। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

उपाध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, अगर हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए?

आवाजेंः ठीक है, जी।

उपाध्यक्ष महोदयाः ठीक है, सदन का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लालः उपाध्यक्ष महोदया, इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत एक्सीडेंटल डैथ के दौरान 2 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है और पार्शियल डिसेबिलिटी की अवस्था में 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

14:00 बजे

उपाध्यक्ष महोदया, ऐसी तीन योजनाएं हैं। एक योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति महीना का प्रीमियम 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' में देंगे। ' प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना' में 30 रुपये प्रति महीना देंगे या फिर 330 रुपये प्रति वर्ष देंगे। ' प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' में 12 रुपये प्रति महीना देंगे। यह सब प्रीमियम हरियाणा सरकार की तरफ से योजनाओं में दिए जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, 500 रुपये में से जो पैसा बचेगा उसमें से 'परिवार समृद्धि निधि योजना' में लगायेंगे। 'परिवार समृद्धि निधि योजना' में आयु के हिसाब से जिसका हिस्सा है, वह 18 हजार रुपये से लेकर 30 हजार रुपये तक हर पांच साल में उस व्यक्ति को मिलेगा। यदि उसकी आयु 40 वर्ष की है तो 18 हजार रुपये यदि वह 18 वर्ष का है तो 30 हजार रुपये प्रीमियम के मिलेंगे। (विघ्न) इस प्रकार से जो 40 वर्ष से 60 वर्ष तक के लोग हैं अगर वे कैश लेना चाहे तो उसी प्रकार से 6 हजार रुपये साल का मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदया, अगर वह 'परिवार समृद्धि निधि योजना' में ऑप्शन लेना चाहता है तो उसको हर 5 साल के बाद वैसे तो उसके 30 हजार रुपये बनते हैं लेकिन उसको 36 हजार रुपये मिलेंगे। एक आयु के बाद जो शेष पैसा बचेगा उसको भी एक टेबल जो हम बनायेंगे उसके हिसाब से लाभ मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदया, इस प्रकार से पांच प्रकार की योजनाएं हैं ताकि हम गरीब परिवारों को सहायता पहुँचा सके। उपाध्यक्ष महोदया, किसानों

के लिए पैंशन की योजना है। यह योजना 18 वर्ष से 40 वर्ष तक तथा 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की पैंशन योजना स्कीम है। यह आयु के हिसाब से यानी जो आज 18 वर्ष का व्यक्ति है उसको 60 वर्ष के बाद 15 हजार रुपये प्रति महीना मिलेंगे। जिसकी आयु 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक है उसको 60 वर्ष के बाद 3 हजार रुपये प्रति महीना मिलेंगे। 18 वर्ष का व्यक्ति 60 वर्ष का होते ही उसको 15 हजार रुपये प्रति महीना पैंशन मिलेगी। अर्थात् एक हिस्सा किसान पैंशन योजना का है और दूसरा हिस्सा हर साल 6 हजार रुपये यानी 4 महीने के बाद 2 हजार रुपये मिलने का है। 'परिवार समृद्धि निधि योजना के अन्तर्गत हर पांच साल के बाद अगर वह इक्ट्ठी पैंशन लेता है तो 36 हजार रुपये मिलेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, इस प्रकार से 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के किसानों को कुछ न कुछ लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। लाभ का एक सिद्धांत है कि 500 रुपये प्रति महीना अर्थात् 6 हजार रुपये प्रति वर्ष सबको मिलेगा ताकि उनके परिवारों में कुछ न कुछ समृद्धि आ सके। उपाध्यक्ष महोदया, जब ये योजनाएं लागू हो जायेंगी तो किसान अपने ऑप्शन के हिसाब से अपना नाम योजना में दे देगा। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी बड़ी अच्छी योजना की घोषणा की है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस योजना की घोषणा की है वह हमें समझ नहीं आई है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : आपको यह योजना इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि ये योजना आपके काम की नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि यह अच्छी बात है कि उन्होंने यह योजना बनाई है । जब इस योजना को सदन के पटल पर लिखित रूप में रखा जाएगा तभी हम ठीक से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि फिलहाल यह योजना हमारी समझ में नहीं आई है । 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत किसान के 'किसान क्रेडिट कार्ड' से औसतन 6 हजार रुपये सालाना काटे जा रहे हैं । मेरा कहना है आप किसान को 2–2, 4–4 महीने की किस्त में 6 हजार रुपये देने की बात कर रहे हैं । मेरा आपको सुझाव है कि जब आप किसान से लगभग 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष फसल बीमा की किस्त के ले रहे हो तो आपको इस योजना के माध्यम से किसानों

को इससे डबल करके पैसे देने चाहिए । यह तो ऐसी बात हुई कि आप किसान की एक जेब से 6 हजार रुपये निकाल रहे हो और दूसरी जेब में 6 हजार रुपये डालने की कोशिश रहे हो । अतः यह अच्छी बात नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, मैं सिर्फ 8 मिनट बोला हूँ । अगर आप अब हाउस एडजॉर्न करना चाहती हैं तो मैं फिर बोल लूंगा क्योंकि मेरी स्पीच 5–10 मिनट में खत्म नहीं होगी । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप फिर बोल लेना । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, यह बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या गलत बात कर रही हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं गलत बात नहीं कर रही हूं । मैं गांवों में जाती हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या दिल्ली में रही हैं और इन्होंने दिल्ली की ही राजनीति की हैं । ये कभी गोलागढ़ में नहीं गई । इनको गांव की बातों का क्या पता । ये दिल्ली में रही हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से सीनियर हूं ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदया, सीनियौरिटी की बात ठीक है । मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये सदन को गुमराह न करें । मेरा कहना है कि किसान की जमीन के हिसाब से ही उसका बीमा कटता है । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब सदन दिनांक 26 फरवरी, 2019 दोपहर 3.07 बजे (द्वितीय बैठक) तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*14:07 **(तत्पश्चात् सभा मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2019 दोपहर बाद 3.07 बजे (द्वितीय बैठक) तक के लिए *स्थगित हुई।)**